

# घरतीपुत्र की विरासत: पश्चिमी यूपी और किसान की राजनीति

पश्चिमी  
यूपी



लेखक : डॉ. सैयद नासिर शाह



# धरतीपुत्र की विरासत: पश्चिमी यूपी और किसान की राजनीति

लेखक : डॉ. सैयद नासिर शाह

© 2026, डॉ. सय्यद नासिर शाह

Published By : Qalamse.com ( Official Website)

# धरतीपुत्र की विरासत : पश्चिमी यूपी और किसान की राजनीति

लेखक : डॉ. सैयद नासिर शाह

## सर्वाधिकार सुरक्षित।

लेखक अथवा अधिकारधारक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी अंश का पुनरुत्पादन, अनुवाद, संग्रहण या प्रसारण किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता। यह प्रतिबंध लागू कानून के अंतर्गत अनुमत उपयोगों पर लागू नहीं होगा।

इस पुस्तक में व्यक्त विचार और विश्लेषण लेखक के हैं। ऐतिहासिक घटनाओं, व्यक्तियों और सार्वजनिक जीवन से संबंधित विवरणों को यथासंभव सही रखने का प्रयास किया गया है। किसी तथ्यात्मक त्रुटि की सूचना मिलने पर आगामी संस्करण में आवश्यक सुधार किया जाएगा।

© 2026, डॉ. सैयद नासिर शाह

प्रथम संस्करण : 2026

Qalamse.com

## इंतिसाब

अपने मरहूम वालिद जनाब **डॉ. सय्यद मशहूद अली साहब** और शफ़ीक़ वालिदा मोहतरमा **सबीहा जबीन साहिबा** के नाम, जिनकी तरबियत और दुआओं ने मुझे सच की राह पर चलने और इंसान की मेहनत की क़द्र करने का सलीक़ा दिया। अपने अज़ीज़ मरहूम भाई **डॉ. सय्यद यासिर यज़दानी साहब** के नाम, जिनकी बे-लौस मुहब्बत और यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। अपनी अज़ीज़ हमसफ़र **रुख़सार नासिर** और **नाबिश** के नाम, जिन्होंने सब्र और मुहब्बत के साथ इस सफ़र में मेरा साथ निभाया। और अपनी प्यारी बेटियों **सय्यदा ज़ैनब फ़ातिमा** और **अज़ीज़ा ज़हरा मरवा** के नाम, इस दुआ के साथ कि उनका मुस्तक़बिल इल्म, अमन और इज़्ज़त से भरा हो। वे अपनी जड़ों से जुड़ी रहें, अपने ख़्वाब पूरे करें और दूसरों के दुख में काम आने वाली इंसान बनें।

— डॉ. सैयद नासिर शाह

## विषय-सूची

प्रारंभिक पृष्ठ

शीर्षक एवं प्रकाशन परिचय ..... 3

सर्वाधिकार एवं संस्करण विवरण ..... 4

इंतिसाब ..... 5

तशक्कुर (शुक्रिया नामा) ..... 8

भूमिका ..... 9

### भाग 1 — चौधरी चरण सिंह जी: विचार, जीवन और विरासत

अध्याय 1 — चौधरी चरण सिंह जी: जीवन परिचय ..... 14

अध्याय 2 — किसान का नेता बनने की यात्रा ..... 18

अध्याय 3 — उनकी आर्थिक सोच: गाँव, किसान और छोटा..... 21

अध्याय 4 — सामाजिक न्याय और ग्रामीण भारत ..... 24

अध्याय 5 — प्रधानमंत्री तक की राजनीतिक यात्रा ..... 27

अध्याय 6 — उनके प्रमुख पद, सम्मान और भारत रत्न ..... 30

अध्याय 7 — मुस्लिम समाज और चौधरी चरण सिंह जी की ..... 33

अध्याय 8 — पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट-मुस्लिम किसान..... 36

### भाग 2 — चौधरी अजीत सिंह जी: विरासत से आधुनिक राजनीति तक

अध्याय 9 — चौधरी अजीत सिंह जी: संक्षिप्त जीवनी ..... 39

अध्याय 10 — तकनीकी शिक्षा से राजनीति तक ..... 43

अध्याय 11 — राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण और विस्तार ..... 47

अध्याय 12 — केंद्रीय मंत्री के रूप में चौधरी अजीत सिंह..... 51

अध्याय 13 — किसान, गन्ना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ..... 55

अध्याय 14 — चौधरी अजीत सिंह जी और मुस्लिम समाज ..... 59

अध्याय 15 — गठबंधन राजनीति, सफलताएँ और चुनौतियाँ ..... 63

अध्याय 16 — चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक विरासत ..... 67

## विषय-सूची (क्रमशः)

### भाग 3 — जयंत चौधरी जी: नई पीढ़ी, नई भाषा

- अध्याय 17 — जयंत चौधरी जी: जीवन और राजनीतिक यात्रा ..... 71  
अध्याय 18 — दादा और पिता की विरासत से जयंत चौधरी..... 75  
अध्याय 19 — जयंत चौधरी जी की राजनीतिक सोच और..... 79  
अध्याय 20 — युवा, शिक्षा, कौशल और रोजगार ..... 83  
अध्याय 21 — किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जयंत..... 87  
अध्याय 22 — सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व ..... 91  
अध्याय 23 — राष्ट्रीय लोक दल का संगठन और नई पीढ़ी..... 95  
अध्याय 24 — उत्तर प्रदेश से आगे: उत्तराखंड और आस..... 99

### भाग 4 — जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोक दल और मुस्लिम समाज

- अध्याय 25 — मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक से आगे..... 103  
अध्याय 26 — शिक्षा और कौशल: मुस्लिम युवाओं के..... 106  
अध्याय 27 — रोजगार, छोटे कारोबार और ग्रामीण ..... 109  
अध्याय 28 — मुस्लिम किसान और राष्ट्रीय लोक दल ..... 112  
अध्याय 29 — पसमांदा समाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व ..... 115  
अध्याय 30 — मुस्लिम महिलाओं और युवाओं की..... 118  
अध्याय 31 — पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक भाईचारा ..... 121  
अध्याय 32 — उत्तराखंड के मुस्लिम समाज और राष्ट्रीय ..... 124  
अध्याय 33 — सत्ता में हिस्सेदारी: टिकट से आगे संगठन..... 127  
अध्याय 34 — नया सवेरा: चौधरी चरण सिंह जी की ..... 130

## तशक्कुर (शुक्रिया नामा)

सबसे पहले मैं **अल्लाह रब्ब-उल-इज़्ज़त** का बे-पायाँ शुक्र अदा करता हूँ, जिसकी तौफ़ीक़ और रहमत से मुझे यह किताब मुकम्मल करने का हौसला मिला। उसी के करम से मैं अपने खयालात को अल्फ़ाज़ दे सका और “**धरतीपुत्र की विरासत: पश्चिमी यूपी और किसान की राजनीति**” को पाठकों के सामने पेश कर सका।

इस डिजिटल किताब (ई-बुक्स) को आप तक पहुँचाने के सफ़र में मैं **Qalamse.com** की पूरी टीम का तहे-दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने मेरी तहरीर पर भरोसा किया और इसके प्रकाशन की ज़िम्मेदारी उठाई। किताब की तैयारी और उसे बेहतर शक्ल देने में उनकी रहनुमाई, मेहनत और सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।

मैं उन तमाम अहबाब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने लिखने के दौरान मेरा हौसला बढ़ाया, मेरी बातों को सुना और अपने मशवरों से मदद की। इस सफ़र में छोटे-बड़े हर सहयोग की अपनी अहमियत रही है। उम्मीद है कि यह किताब किसान के जीवन, उसकी मेहनत और पश्चिमी यूपी की राजनीतिक विरासत को समझने में कुछ काम आएगी। पाठकों की राय और सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा।

दुआगो,  
डॉ. सैयद नासिर शाह

## भूमिका

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए यहाँ के गाँवों को समझना जरूरी है। यहाँ खेत की मेड़ से शुरू हुई बात कई बार प्रदेश और देश की सत्ता तक पहुँची है। फसल का दाम, गन्ने का भुगतान, सिंचाई का पानी, बिजली का बिल और जमीन का सवाल इस इलाके के सार्वजनिक जीवन का हिस्सा रहे हैं। इन सवालों के पीछे किसान का पूरा घर होता है— उसकी मेहनत, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल और आने वाले दिनों की चिंता। इसी जीवन से किसान की राजनीति अपना अर्थ पाती है।

इस किताब को लिखने के पीछे मेरी इच्छा उस राजनीतिक परंपरा को समझने की है, जिसने गाँव के आदमी को अपनी बात कहने का हौसला दिया। ऐसा आदमी जो मेहनत करता था, देश का पेट भरता था, लेकिन सरकारी दफ्तरों और सत्ता के दरवाजों पर अक्सर अपने को कमजोर पाता था। उसकी परेशानी को सार्वजनिक सवाल बनाने और उसकी आवाज को राजनीतिक महत्व दिलाने में चौधरी चरण सिंह जी का स्थान बहुत बड़ा है। उनके जीवन और विचारों से होकर इस किताब की शुरुआत होती है।

चौधरी चरण सिंह जी के लिए किसान का प्रश्न बहुत व्यापक था। खेती की हालत का संबंध गाँव के बाजार से था, छोटे दुकानदार से था, कारीगर से था और उस मजदूर से भी था जिसकी रोजी खेत में मिलने वाले काम पर निर्भर थी। किसान की आमदनी घटती तो उसका असर आसपास के अनेक घरों पर पड़ता। ग्रामीण जीवन के इस आपसी संबंध को समझे बिना उनकी आर्थिक सोच को समझना अधूरा रहेगा। उन्होंने जिस भारत की चिंता की, उसमें छोटी जोत वाले किसान और अपने हाथों से काम करने वाले आदमी की जगह केंद्रीय थी।

उनके सार्वजनिक जीवन को पढ़ते हुए यह सवाल बार-बार सामने आता है कि देश की तरक्की में गाँव के हिस्से क्या आया। जिन लोगों की मेहनत पर खेती टिकी है, उनकी जरूरतें नीति बनाते समय कितनी सुनी गईं? छोटे किसान के पास अपनी उपज बेचने की कितनी ताकत है? कर्ज और खर्च के बीच वह अपने परिवार को किस तरह सँभालता है?

ये प्रश्न उस समय भी जरूरी थे और आज भी हमारे सामने हैं। परिस्थितियाँ बदली हैं, लेकिन किसान की मेहनत और उसकी आमदनी के बीच की दूरी अब भी गंभीर विचार माँगती है।

चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति को उनके व्यक्तित्व से अलग करके देखना भी कठिन है। गाँव से उनका संबंध, प्रशासन को देखने का उनका ढंग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी चिंता मिलकर उनके राजनीतिक जीवन को आकार देते हैं। इस पुस्तक में उनके जीवन परिचय के साथ उन अनुभवों और विचारों को समझने की कोशिश की गई है जिनसे उनका किसान नेतृत्व बना। उनके पद और सम्मान अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। उन तक पहुँचने की यात्रा और उनके पीछे की सोच भी उतनी ही विस्तार से पढ़े जाने योग्य है।

इसके बाद यह यात्रा चौधरी अजीत सिंह जी तक आती है। उन्हें एक ऐसी विरासत मिली जिसके साथ लोगों का गहरा लगाव और बड़ी अपेक्षाएँ जुड़ी थीं। पिता के प्रति जनता का सम्मान उनके लिए सहारा था, और उसी सम्मान के कारण उनसे उम्मीदें भी अधिक थीं। उन्हें बदलती राजनीतिक परिस्थितियों में अपना रास्ता बनाना था, संगठन को सँभालना था और किसान की आवाज के लिए जगह बनाए रखनी थी। उनके सार्वजनिक जीवन में इन जिम्मेदारियों के साथ चलने का प्रयास दिखाई देता है।

चौधरी अजीत सिंह जी की शिक्षा और तकनीकी पृष्ठभूमि उनके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। उनके राजनीतिक जीवन को समझते समय यह देखना जरूरी है कि आधुनिक शिक्षा से निकला उनका अनुभव ग्रामीण समाज की जरूरतों से किस तरह जुड़ा। राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण, उसका संगठन, केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी भूमिका और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उनका संबंध इस चर्चा के हिस्से हैं। उनके निर्णयों, उपलब्धियों और कठिनाइयों को साथ रखकर ही उनकी राजनीतिक यात्रा का उचित आकलन किया जा सकता है।

जयंत चौधरी जी के सामने यह विरासत एक नए समय में आती है। आज किसान परिवार का नौजवान खेती की चिंता के साथ पढ़ाई, नौकरी, कौशल और कारोबार के अवसर भी चाहता है।

उसके जीवन में गाँव और शहर दोनों मौजूद हैं। वह अपने परिवार की जमीन से जुड़ा रह सकता है और साथ ही अपने लिए कोई दूसरा पेशा भी चुनना चाह सकता है। किसान राजनीति को इस बदलती आकांक्षा को समझना होगा। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व और प्राथमिकताओं का अध्ययन करते समय इस पुस्तक में ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखा गया है।

तीन पीढ़ियों की इस यात्रा में निरंतरता भी है और बदलाव भी। समय के साथ राजनीतिक भाषा बदलती है, संगठन की जरूरतें बदलती हैं और लोगों की अपेक्षाएँ भी बदलती हैं। इसलिए विरासत को समझने के लिए यह देखना होगा कि पुरानी चिंताओं को नए हालात में किस रूप में आगे बढ़ाया गया। किन सवालों पर जोर बना रहा, किन पर कम हुआ और किन नए प्रश्नों को जगह मिली—इन बातों पर विचार किए बिना किसी राजनीतिक परंपरा की पूरी तस्वीर सामने नहीं आती।

पश्चिमी यूपी इस पूरी चर्चा की जमीन है। यहाँ खेती, बाजार, बिरादरी, पंचायत और स्थानीय नेतृत्व के बीच गहरा संबंध रहा है। किसान समाज के भीतर भी अनेक अंतर हैं। छोटी जोत वाले किसान, बड़े भूमिधर, बटाई पर खेती करने वाले और खेतिहर मजदूर की स्थितियाँ एक जैसी नहीं होतीं। महिलाओं का श्रम अक्सर खेती और घर दोनों को सँभालता है, फिर भी निर्णय लेने में उनकी भागीदारी सीमित रह जाती है। किसान की राजनीति का अध्ययन करते समय इन अलग-अलग अनुभवों को सुनना जरूरी है।

इस क्षेत्र के सामाजिक संबंध भी पुस्तक का हिस्सा हैं। अलग-अलग जातियों और धार्मिक समुदायों के लोग लंबे समय से खेती, मजदूरी, व्यापार और पड़ोस के रिश्तों में जुड़े रहे हैं। इन संबंधों में सहयोग के अनुभव हैं और तनाव के भी। जाट-मुस्लिम किसान साझेदारी को इसी व्यापक ग्रामीण जीवन के भीतर समझा गया है। जहाँ साझा आर्थिक हित लोगों को करीब लाते हैं, वहीं सामाजिक दूरियाँ और राजनीतिक टकराव उस संबंध को कमजोर भी कर सकते हैं। भाईचारे की चर्चा तभी सार्थक होगी जब उसके बनने की मेहनत और उसके टूटने की कीमत, दोनों को समझा जाए।

मुस्लिम समाज का उल्लेख भी इसी सामाजिक और आर्थिक संदर्भ में आता है। उसके किसान, मजदूर, कारीगर, छोटे कारोबारी, महिलाएँ और युवा इस इलाके के जीवन का हिस्सा हैं।

शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा, सम्मान और प्रतिनिधित्व से जुड़े उनके प्रश्नों का संबंध व्यापक ग्रामीण समाज से भी है। पुस्तक में इन विषयों को उनकी वास्तविक परिस्थितियों के साथ देखने का प्रयास है। किसी समुदाय को एक जैसी सोच या एक ही राजनीतिक पसंद वाला मान लेने से उसकी अपनी विविधता ओझल हो जाती है।

इस किताब में चुनाव और राजनीतिक गठबंधन भी आएँगे। उनसे नेतृत्व के निर्णयों, संगठन की स्थिति और जनसमर्थन में आए बदलाव को समझने में सहायता मिलती है। फिर भी पुस्तक का मुख्य सरोकार उन विचारों और सामाजिक संबंधों से है जिनके आधार पर किसान राजनीति खड़ी हुई। किसी चुनाव का परिणाम एक समय की स्थिति बताता है। किसी राजनीतिक विरासत को समझने के लिए उससे लंबी अवधि और व्यापक अनुभव को देखना पड़ता है।

चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी के प्रति सम्मान रखते हुए उनके सार्वजनिक जीवन को गंभीरता से पढ़ना इस पुस्तक का उद्देश्य है। जहाँ उनके काम ने लोगों के जीवन और राजनीतिक चेतना पर असर डाला, उसे समझना चाहिए। जहाँ कोई निर्णय विवाद का कारण बना या लोगों की अपेक्षाएँ पूरी नहीं हुईं, वहाँ भी ठहरकर विचार करना चाहिए। पाठक को ऐसी समझ मिलनी चाहिए जिसमें वह योगदान का महत्व पहचान सके और अपनी राय भी बना सके।

**“धरतीपुत्र की विरासत”** लिखते समय मेरे सामने बार-बार किसान के घर का वही साधारण दृश्य आता है—एक परिवार अपनी मेहनत के भरोसे अगली फसल की तैयारी कर रहा है। उसे मौसम की चिंता है, लागत की चिंता है और बच्चों के भविष्य की भी। राजनीति से उसकी अपेक्षा बहुत ठोस है। वह चाहता है कि उसकी बात सुनी जाए, उसके श्रम की उचित कीमत मिले और जरूरत पड़ने पर व्यवस्था उसका साथ दे।

इस पुस्तक के माध्यम से मेरी कोशिश उस आवाज, उसके नेतृत्व और उसकी बदलती यात्रा को समझने की है। चौधरी चरण सिंह जी से चौधरी अजीत सिंह जी और फिर जयंत चौधरी जी तक आते हुए हम पश्चिमी यूपी के उस समाज को भी पढ़ेंगे जिसने इन नेताओं से उम्मीद रखी, उनका साथ दिया और समय-समय पर उनसे सवाल भी किए। इन पन्नों में किसान के जीवन को लेकर समझ और उसकी मेहनत के प्रति आदर कुछ और बढ़ सके, तो मैं इस प्रयास को सार्थक मानूँगा।

**डॉ. सैयद नासिर शाह**

## **भाग 1 — चौधरी चरण सिंह जी: विचार, जीवन और विरासत**

### **अध्याय 1 — चौधरी चरण सिंह जी: जीवन परिचय**

चौधरी चरण सिंह जी के जीवन को समझने की शुरुआत दिल्ली की सत्ता से नहीं, उस ग्रामीण संसार से होती है जहाँ खेती परिवार की रोजी भी थी और उसके भविष्य का आधार भी। गाँव में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति किसान का नेता नहीं बन जाता। उनके जीवन की विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने आसपास दिखाई देने वाली कठिनाइयों को पढ़ाई, कानून और सार्वजनिक काम के माध्यम से समझा। बाद में यही अनुभव उनकी आर्थिक सोच और राजनीति का आधार बना।

उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को नूरपुर गाँव में हुआ, जो उस समय मेरठ जिले का हिस्सा था। परिवार खेती से जुड़ा हुआ था। ग्रामीण जीवन की मेहनत, सीमित साधनों में घर चलाने की चिंता और जमीन के साथ परिवार का संबंध उनके शुरुआती परिवेश में मौजूद थे। आगे चलकर उन्होंने किसान के प्रश्न पर जो लिखा और किया, उसमें इस पृष्ठभूमि का महत्व दिखाई देता है।

शिक्षा ने उनके सामने गाँव से बाहर की दुनिया खोली। उन्होंने 1923 में विज्ञान में स्नातक और 1925 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद कानून का अध्ययन किया और गाजियाबाद में वकालत शुरू की। विज्ञान, इतिहास और कानून की पढ़ाई ने उन्हें अलग-अलग प्रकार से सोचने का अवसर दिया। उनके बाद के लेखन में तथ्यों, ऐतिहासिक उदाहरणों और कानूनी व्यवस्थाओं के प्रति रुचि दिखाई देती है।

उनकी शिक्षा का महत्व उस दौर की ग्रामीण परिस्थितियों में रखकर देखना चाहिए। खेती से जुड़े घर में पढ़ाई का अर्थ केवल परीक्षा पास करना नहीं था। उससे नौकरी और पेशे का रास्ता खुलता था, साथ ही उन संस्थाओं की भाषा समझ में आती थी जिनसे गाँव का सामान्य आदमी अक्सर दूरी महसूस करता था। कानून की पढ़ाई ने चौधरी चरण सिंह जी को उसी दूरी के दोनों सिरों तक पहुँचाया। एक तरफ गाँव के आदमी का अनुभव था, दूसरी तरफ अदालत और प्रशासन की प्रक्रिया। आगे उनके काम में दोनों के बीच बातचीत दिखाई देती है।

उन्होंने अपने ग्रामीण परिचय को शिक्षा के बाद पीछे नहीं छोड़ दिया। गाँव उनके लिए केवल जन्मस्थान नहीं रहा, वह उनके अध्ययन का विषय और सार्वजनिक काम का आधार बना। किसान की दशा पर विचार करते हुए वे व्यक्ति की मेहनत से आगे उस व्यवस्था को देखते थे जिसमें मेहनत का फल बंटता है। परिवार खेत में पूरा समय लगाए, फिर भी उसकी हालत कमजोर क्यों रहे—इस प्रश्न को समझने के लिए उत्पादन के साथ स्वामित्व, कर्ज और बाजार को देखना पड़ता है। उनकी राजनीतिक समझ इन्हीं संबंधों के बीच परिपक्व हुई।

वकालत के काम ने जमीन, कर्ज और अधिकारों से जुड़े प्रश्नों को समझने का एक व्यावहारिक रास्ता भी दिया। खेत पर मेहनत करने वाले व्यक्ति की स्थिति केवल उसकी पैदावार से तय नहीं होती। राजस्व, लगान, उधार और स्वामित्व की शर्तें भी उसके जीवन को प्रभावित करती हैं। चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति में इन विषयों की गहरी उपस्थिति रही।

1925 में उनका विवाह श्रीमती गायत्री देवी जी से हुआ। सार्वजनिक जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता बढ़ने के साथ परिवार को कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। उनके जेल जाने के दौरान घर की जिम्मेदारी श्रीमती गायत्री देवी जी ने संभाली। किसी स्वतंत्रता सेनानी की जीवनी में परिवार का यह श्रम अक्सर संक्षेप में रह जाता है, जबकि सार्वजनिक संघर्ष को संभव बनाने में उसका बड़ा योगदान होता है।

चौधरी चरण सिंह जी कांग्रेस से जुड़े और स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हुए। 1930 में नमक सत्याग्रह में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। बाद में व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भी उन्होंने कारावास सहा। उनका राजनीतिक जीवन स्वतंत्र भारत में किसी पद की तलाश से शुरू नहीं हुआ था। उसकी शुरुआती जमीन औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष में बनी थी।

1937 में वे छपराईली क्षेत्र से पहली बार प्रांतीय विधानसभा पहुँचे। इसके साथ उनके सार्वजनिक जीवन में विधायी काम का नया अध्याय शुरू हुआ। अब ग्रामीण कठिनाइयों को केवल सभा में उठाने के बजाय कानून और प्रशासन के स्तर पर रखने का अवसर था।

आने वाले वर्षों में कर्ज से राहत, भूमि संबंधों और किसान की आर्थिक सुरक्षा के प्रश्न उनके काम के प्रमुख विषय बने।

छपरायली से विधानसभा तक पहुँचने पर उनकी जिम्मेदारी का स्वरूप बदला। स्थानीय कठिनाई को कानूनी भाषा में रखना पड़ता था, प्रस्ताव के परिणाम समझाने पड़ते थे और दूसरे प्रतिनिधियों को अपने पक्ष का कारण बताना पड़ता था। इस काम में केवल लोकप्रियता पर्याप्त नहीं थी। अध्ययन और बहस की तैयारी चाहिए थी। उनके व्यक्तित्व का यह पक्ष आगे भी बना रहा। वे किसान की बात को भावनात्मक अपील तक सीमित रखने के बजाय शासन की नीति में जगह दिलाना चाहते थे।

उनकी पहचान अध्ययनशील नेता की थी। पढ़ना और लिखना उनके सार्वजनिक जीवन से अलग शौक भर नहीं था। वे अपने विचारों को पुस्तक, टिप्पणी और नीति संबंधी तर्क के रूप में सामने रखते थे। जमीन और खेती के प्रश्न पर उनकी कई पुस्तकें इसी लंबे बौद्धिक श्रम का परिणाम थीं। वे असहमति होने पर भी अपने पक्ष को विस्तार से समझाने का प्रयास करते थे।

उनके स्वभाव की दृढ़ता सार्वजनिक जीवन में ताकत भी बनी और टकराव का कारण भी। जिन आर्थिक विचारों पर उनका विश्वास था, उन्हें वे बड़े राजनीतिक नामों के सामने भी रखते थे। इससे उनकी स्वतंत्र पहचान बनी। लेकिन सरकार और संगठन में काम करते समय अपने मत पर टिके रहने के साथ सहयोगियों को साथ रखना भी पड़ता है। उनके राजनीतिक जीवन के कई मोड़ इस कठिन संबंध को सामने लाते हैं। उन्हें समझने के लिए उनके तर्क और उनके समय के मतभेद, दोनों को पढ़ना पड़ता है।

स्वतंत्रता के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियाँ संभालीं। भूमि सुधारों में उनकी भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। बाद में वे दो बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने गृह मंत्री, वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री की जिम्मेदारियाँ निभाईं। 28 जुलाई 1979 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। इन पदों तक पहुँचना उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन उनका पूरा परिचय इनसे नहीं बनता।

उनकी स्थायी पहचान उस सवाल से जुड़ी रही कि देश की आर्थिक व्यवस्था में किसान और छोटे उत्पादक के लिए कितनी जगह है। प्रधानमंत्री बनने से बहुत पहले वे इस प्रश्न पर काम कर रहे थे और पद छोड़ने के बाद भी उनके विचारों का महत्व बना रहा।

उनकी जीवनी का एक उल्लेखनीय पक्ष यह है कि विचार और पद हमेशा एक साथ नहीं चले। कुछ बातों पर वे सरकार में रहते हुए काम कर सके, कुछ पर दल के भीतर बहस करते रहे और कुछ उनके लेखन में अधिक विस्तार से सामने आईं। इसीलिए उनके जीवन का अध्ययन केवल कार्यकालों का हिसाब नहीं है। उनकी पुस्तकों में दर्ज चिंता और प्रशासन में उपलब्ध अवसरों के बीच का अंतर भी उस जीवन का हिस्सा है।

किसान के साथ उनके संबंध में आत्मसम्मान का स्थान गहरा था। खेती करने वाला व्यक्ति देश को अन्न देता है, लेकिन अपने ही काम से जुड़े फैसलों में उसकी बात कम सुनी जाती है—यह विरोधाभास उनकी राजनीति के केंद्र में रहा। उन्होंने ग्रामीण आदमी के अनुभव को राष्ट्रीय बहस में ऐसी जगह दी जहाँ वह अपने काम, अधिकार और भविष्य के बारे में बोल सके। यही संबंध उनके पद छोड़ने के बाद भी उनकी पहचान में बना रहा।

29 मई 1987 को उनका निधन हुआ। उनके बाद किसान राजनीति की अनेक धाराओं ने उनकी विरासत से अपना संबंध बताया। परिवार में चौधरी अजीत सिंह जी और आगे जयंत चौधरी जी ने सार्वजनिक जीवन अपनाया। लेकिन चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का दायरा परिवार से बड़ा है। वह उस बहस में मौजूद है जिसमें गाँव, खेती और मेहनत से उत्पादन करने वाले व्यक्ति के सम्मान का प्रश्न उठता है।

उनका जीवन एक ग्रामीण परिवार से निकलकर राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुँचने की यात्रा है। सत्ता के बड़े प्रश्नों के बीच उन्होंने किसान की रोजमर्रा की परेशानियों को गंभीरता से लिया। जमीन, कर्ज और उत्पादन पर उनका काम इसी अनुभव से निकला। आगे के अध्यायों में उनके विचार और राजनीतिक फैसले इसी पृष्ठभूमि में खुलते हैं।

## अध्याय 2 — किसान का नेता बनने की यात्रा

चौधरी चरण सिंह जी को किसान का नेता कहने के पीछे केवल उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं थी। यह पहचान लंबे सार्वजनिक काम से बनी। उन्होंने किसान की कठिनाई को उसके व्यक्तिगत दुर्भाग्य की तरह नहीं देखा। जमीन की व्यवस्था, कर्ज की शर्तें और सरकारी नीति किस तरह उसके जीवन को प्रभावित करती हैं, यह उनकी चिंता का विषय बना।

किसान की मेहनत खेत में दिखाई देती है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति कई ऐसी व्यवस्थाओं से तय होती है जिन पर उसका नियंत्रण सीमित होता है। फसल खराब हो जाए तो कर्ज बढ़ता है। फसल अच्छी हो, तब भी उचित दाम और भुगतान की समस्या हो सकती है। जमीन पर उसका अधिकार कमजोर हो तो वह भविष्य की योजना भी पूरे भरोसे से नहीं बना पाता। चौधरी चरण सिंह जी ने इन प्रश्नों को अपने विधायी और प्रशासनिक काम में जगह दी।

1937 में विधानसभा पहुँचने के बाद उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विषयों पर सक्रिय भूमिका निभाई। 1939 के ऋण विमोचन संबंधी विधेयक की तैयारी और उसे आगे बढ़ाने में उनका योगदान था। ग्रामीण कर्जदारों को राहत देने का यह प्रयास उस समय की एक महत्वपूर्ण समस्या से जुड़ा था। कर्ज की मार किसान के घर तक सीमित नहीं रहती। कभी उसे जमीन खोने का भय होता है, कभी अपनी उपज उचित मूल्य से कम दाम पर बेचनी पड़ती है। आर्थिक निर्भरता उसकी सामाजिक स्थिति को भी प्रभावित कर सकती है।

इसलिए कर्ज से राहत का प्रश्न उनके लिए किसान की स्वतंत्रता से जुड़ा था। ग्रामीण कर्ज की कठिनाई उसकी रकम से भी आगे जाती है। खेती में खर्च पहले होता है और आमदनी बाद में आती है। बीच में परिवार को भोजन, इलाज और सामाजिक जिम्मेदारियाँ भी निभानी पड़ती हैं। यदि उधार की शर्तें उसके प्रतिकूल हों, तो अच्छी फसल का बड़ा हिस्सा पुराना हिसाब चुकाने में निकल सकता है। किसान फिर अगली बुआई के लिए उधार लेता है। इस चक्र में राहत का प्रश्न केवल ब्याज घटाने का नहीं, परिवार को अपने श्रम पर कुछ अधिकार लौटाने का भी था।

भूमि संबंधों पर उनका काम इससे भी अधिक व्यापक था। जमींदारी व्यवस्था में वास्तविक खेती करने वाले व्यक्ति और राज्य के बीच मध्यस्थों की भूमिका थी। चौधरी चरण सिंह जी इस व्यवस्था को बदलने के पक्षधर बने। उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों की प्रक्रिया में उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। उनकी सोच में खेती करने वाले व्यक्ति का जमीन से सुरक्षित संबंध महत्वपूर्ण था। जो परिवार अपने श्रम से उत्पादन करता है, उसके पास भविष्य का भरोसा भी होना चाहिए। यह भरोसा खेत सुधारने, उत्पादन बढ़ाने और परिवार की जिंदगी व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। भूमि सुधार का अर्थ केवल मालिक का नाम बदलना नहीं था। बिखरी हुई जोतें भी खेती को कठिन बनाती थीं। अलग-अलग स्थानों पर छोटे टुकड़ों में बंटी जमीन पर समय और श्रम अधिक लग सकता है। चकबंदी का उद्देश्य ऐसी कठिनाइयों को कम करना था। चौधरी चरण सिंह जी ने इस दिशा में भी महत्वपूर्ण काम किया।

चकबंदी को खेत की बनावट से समझा जा सकता है। एक परिवार की जमीन कई जगह हो तो हर टुकड़े तक पहुँचने, पानी ले जाने और निगरानी करने में अलग मेहनत लगती है। गाँव के नक्शे पर यह छोटी बात लग सकती है, लेकिन खेती के दिन में उसका बड़ा हिस्सा चला जाता है। जोत को व्यवस्थित करने के पीछे समय और संसाधन बचाने का विचार था। साथ ही जमीन की गुणवत्ता, रास्ते और पानी के अधिकार का न्यायपूर्ण ध्यान रखना पड़ता था। सुधार की उपयोगिता उसके अमल पर भी निर्भर थी।

फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि इन सुधारों से ग्रामीण समाज की सारी असमानताएँ समाप्त हो गईं। भूमिहीन मजदूर, छोटे काश्तकार और अलग-अलग सामाजिक वर्गों की स्थिति में अंतर बना रहा। उनके योगदान का महत्व स्वीकार करने के साथ इन सीमाओं को समझना जरूरी है। किसान की समस्या को नीति के केंद्र में लाना बड़ी उपलब्धि थी। ग्रामीण न्याय का पूरा काम उससे कहीं अधिक व्यापक था। किसान का नेता बनने की उनकी यात्रा में अध्ययन और जनसंपर्क साथ चले। वे गाँव के अनुभव को आर्थिक तर्क से जोड़ते थे। उनकी पुस्तकों में यह चिंता बार-बार सामने आती है कि खेती और छोटे उत्पादन को विकास की योजना में पीछे कर देने का असर व्यापक समाज पर पड़ेगा।

यही सोच उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के कुछ प्रचलित विचारों से असहमति तक ले गई। वे बड़े उद्योगों को प्राथमिकता देने वाली आर्थिक दिशा और सामूहिक खेती के प्रस्तावों पर सवाल उठाते थे। उनकी असहमति का आधार यह था कि भारत की परिस्थितियों में छोटे कृषक और श्रम आधारित उत्पादन की भूमिका को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए।

कांग्रेस के भीतर यह मतभेद समय के साथ गहरा हुआ। 1967 में उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर नई राजनीतिक राह अपनाई। इसके बाद भारतीय क्रांति दल और आगे की राजनीतिक कोशिशों में किसान की साझा पहचान को अधिक संगठित रूप मिला। इसमें विभिन्न जातियों और समुदायों के कृषक समूहों के साथ आने की संभावना थी। किसान की यह पहचान अपने भीतर कई अंतर रखती थी। सभी किसानों के पास बराबर जमीन नहीं थी और उनकी सामाजिक हैसियत भी समान नहीं थी। फिर भी खेती के मूल्य, लागत और ग्रामीण जीवन की उपेक्षा जैसे प्रश्न सहयोग का आधार बन सकते थे। चौधरी चरण सिंह जी ने इस संभावना को राजनीतिक भाषा दी। ऐसे समाज में किसान का नेता बनने के लिए केवल जमीन के मालिक की बात कहना पर्याप्त नहीं था। खेती का काम जिन अनेक लोगों के श्रम से चलता है, उनके बीच सहयोग और तनाव साथ मौजूद रहते हैं। इसी वजह से उनकी किसान राजनीति की उपलब्धि और सीमा एक ही ग्रामीण संसार में दिखाई देती है। उसने कृषक समाज को सत्ता के सामने अधिक प्रभावी बनाया, लेकिन उसके भीतर की हर असमानता समाप्त नहीं की। इस अधूरेपन को स्वीकार करने पर ही उनके संघर्ष की वास्तविक कठिनाई समझ में आती है। उनकी लोकप्रियता में इस बात का बड़ा हिस्सा था कि उन्होंने किसान को आर्थिक जीवन के सक्रिय भागीदार के रूप में प्रस्तुत किया। उसके श्रम और फैसलों का महत्व था। राहत की मांग के साथ वह अपने अधिकार और देश के विकास की दिशा पर भी बोल सकता था। उनकी राजनीति ने इस आत्मविश्वास को सार्वजनिक स्थान दिया। यह पहचान किसी एक चुनाव से नहीं बनी थी। कर्ज, जमीन, चकबंदी, उत्पादन और ग्रामीण प्रतिनिधित्व पर लंबे काम ने उसे आकार दिया। इसी कारण उनके जीवन की चर्चा में 'किसान नेता' का संबोधन एक पद से अधिक उनके सार्वजनिक योगदान का परिचय बन जाता है।

## अध्याय 3 – उनकी आर्थिक सोच: गाँव, किसान और छोटा उत्पादक

चौधरी चरण सिंह जी की आर्थिक सोच में एक बुनियादी प्रश्न था—विकास का लाभ उस व्यक्ति तक कैसे पहुँचे जो अपनी मेहनत से उत्पादन करता है? उनके लिए खेत में काम करने वाला किसान, छोटा कारीगर और ग्रामीण उद्योग से जुड़ा परिवार अर्थव्यवस्था की गंभीर चर्चा के पात्र थे। देश की प्रगति को समझते समय इनके जीवन में आए बदलाव को देखना आवश्यक था। वे ऐसे भारत की परिस्थितियों पर विचार कर रहे थे जहाँ बड़ी आबादी खेती और ग्रामीण कामों पर निर्भर थी। उनके सामने बेरोजगारी, सीमित पूंजी और छोटे उत्पादक की कमजोर स्थिति के प्रश्न थे। इसी आधार पर उन्होंने कृषि को प्राथमिकता देने और गाँवों में आर्थिक गतिविधि बढ़ाने पर जोर दिया।

उनका तर्क था कि खेती की उपेक्षा करके व्यापक समृद्धि का रास्ता कठिन होगा। किसान की आमदनी का संबंध केवल उसके घर से नहीं है। वह बाजार से सामान खरीदता है, सेवाएं लेता है और स्थानीय कामों को सहारा देता है। ग्रामीण आय में सुधार का असर अर्थव्यवस्था के दूसरे हिस्सों तक पहुँच सकता है। भूमि का स्वामित्व उनकी सोच का महत्वपूर्ण आधार था। वे छोटे कृषक स्वामित्व को आर्थिक स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन से जोड़ते थे। जिस व्यक्ति का अपनी जमीन और उत्पादन पर अधिकार है, उसके पास अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने की कुछ ठोस क्षमता होती है। इसीलिए जमींदारी उन्मूलन उनके लिए प्रशासनिक सुधार से आगे का प्रश्न था।

छोटे खेत की तरफदारी के पीछे परिवार के श्रम का सवाल भी था। खेत में कौन-सा काम कब होना है, मिट्टी की स्थिति क्या है और उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल कैसे करना है—इन फैसलों में खेती करने वाले का अनुभव काम आता है। चौधरी चरण सिंह जी उस अनुभव को आर्थिक महत्व देते थे। खेत का आकार बढ़ जाना अपने आप उसके बेहतर संचालन का प्रमाण नहीं था। उनके लिए उस जमीन से मिलने वाला उत्पादन और काम, दोनों विचार के विषय थे। उन्होंने बड़े सामूहिक खेतों के पक्ष में दिए जाने वाले तर्कों की आलोचना की। 1959 के कांग्रेस के नागपुर प्रस्ताव के संदर्भ में उनकी असहमति विशेष रूप से सामने आई।

वे मानते थे कि अलग-अलग किसानों की जमीन और श्रम को एक बड़ी संयुक्त व्यवस्था में रख देने से उत्पादन तथा प्रबंधन की समस्याएं अपने आप हल नहीं हो जाएंगी। उनकी चिंता यह थी कि किसान की व्यक्तिगत रुचि, श्रम और निर्णय की भूमिका बनी रहनी चाहिए। परिवार द्वारा संभाली जाने वाली छोटी खेती की उपयोगिता पर उन्होंने विस्तार से लिखा। हालांकि इसका अर्थ सहयोग के प्रत्येक रूप का विरोध नहीं था। ऋण, खरीद, बिक्री या दूसरे कामों में सहयोग और जमीन के संचालन का अनिवार्य सामूहीकरण अलग प्रश्न थे। छोटे उत्पादक के पक्ष में उनका आग्रह ग्रामीण उद्योगों तक भी जाता था। वे ऐसे उत्पादन को महत्व देते थे जिसमें सीमित पूंजी के साथ अधिक लोगों को काम मिल सके। भारत की परिस्थितियों में केवल बड़ी मशीन और विशाल कारखाने को प्रगति का एकमात्र रास्ता मानने पर उन्हें आपत्ति थी। यहाँ उनके विचार को मशीन विरोधी कह देना गलत होगा। प्रश्न तकनीक के चुनाव और उसके सामाजिक परिणाम का था। कोई साधन श्रम की उत्पादकता बढ़ाए और काम करने वाले की स्थिति सुधारे तो उसका उपयोग हो सकता है। लेकिन रोजगार के अवसर कम हों, तब ऐसी तकनीकी दिशा के परिणाम भी देखने होंगे जो बड़ी संख्या में लोगों को काम से बाहर कर दे। उनकी पुस्तक “इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन” में गरीबी, कृषि और आर्थिक संगठन पर विस्तार से विचार मिलता है। “इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी: द गांधियन ब्लूप्रिंट” में भी गाँव, छोटे उत्पादन और विकास की प्राथमिकताओं से उनका संबंध सामने आता है। उनके लिए आर्थिक बहस सार्वजनिक जीवन का नियमित हिस्सा थी। इस सोच का एक पहलू आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण को लेकर चिंता था। जब उत्पादन और पूंजी कुछ बड़े केंद्रों में सिमटते हैं, तो छोटे उत्पादक की स्थिति कमजोर हो सकती है। ग्रामीण समाज में अधिक लोगों के पास उत्पादन का साधन और काम करने का अवसर हो, यह उनके आर्थिक आदर्श का हिस्सा था। इस सोच में बाजार की जरूरत समाप्त नहीं होती। छोटा किसान और कारीगर अपने उपभोग से अधिक उत्पादन बेचते हैं तथा जरूरत का बहुत-सा सामान खरीदते हैं। कठिनाई तब आती है जब सौदे की शर्तों पर उनका प्रभाव बहुत कम हो। समय पर पैसा चाहिए, इसलिए उपज रोक नहीं सकते; कच्चा माल महंगा है, इसलिए नया काम शुरू नहीं कर सकते। छोटे उत्पादन का समर्थन तभी व्यावहारिक बनता है जब उसके लिए कर्ज, परिवहन, जानकारी और बिक्री की व्यवस्था भी समझी जाए।

उनके वित्त मंत्री रहते हुए प्रस्तुत 1979-80 के बजट में ग्रामोद्योग और हथकरघा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रावधान दिखाई देते हैं। इन कदमों का महत्व इस बात में था कि छोटे और श्रम आधारित उत्पादन को सरकारी आर्थिक प्राथमिकताओं में स्थान मिले। उनके बौद्धिक आग्रह और प्रशासनिक जिम्मेदारी के बीच यह एक संबंध था। फिर भी उनके आर्थिक विचारों को हर समय और हर परिस्थिति का तैयार समाधान नहीं माना जा सकता। छोटी जोत की कठिनाइयाँ, बढ़ती आबादी, बाजार की बदलती जरूरतें और ग्रामीण आय के नए स्रोत अलग प्रश्न पैदा करते हैं। उनके विचारों की गंभीरता उन्हें सवालियों से बचाने में नहीं, बदलती परिस्थितियों में परखने में है।

गाँव को आर्थिक महत्व देने का अर्थ वहाँ रहने वालों को पुराने पेशों में बांध देना भी नहीं है। किसान का बच्चा यदि इंजीनियर, शिक्षक या कारोबारी बनना चाहे तो वह ग्रामीण प्रगति का विरोध नहीं करता। असल प्रश्न यह है कि उसका चुनाव मजबूरी से कितना मुक्त है। खेती में रहकर सम्मानजनक जीवन संभव हो और बाहर जाने पर शिक्षा तथा काम के अवसर भी मिलें। चौधरी चरण सिंह जी के छोटे उत्पादक संबंधी आग्रह से आज यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास व्यक्ति के सामने कितने विकल्प खोलता है। इसे उनके समय की किसी तैयार योजना का नाम देना, हालांकि, ठीक नहीं होगा।

उनकी आर्थिक सोच आज भी विकास के सामने कुछ सीधे प्रश्न रखती है। किसान अपनी कमाई पर कितना नियंत्रण रखता है? कारीगर को तैयार माल की कीमत में कितना हिस्सा मिलता है? ग्रामीण परिवार के पास रोजी के कितने रास्ते हैं? इन प्रश्नों से प्रगति का वह पहलू सामने आता है जो उत्पादन के कुल आंकड़ों में आसानी से छिप सकता है।

चौधरी चरण सिंह जी ने गाँव को पिछली दुनिया का अवशेष नहीं माना। उनके लिए वह भारत के आर्थिक जीवन का जीवित और महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसकी क्षमता, श्रम और जरूरतों को समझे बिना राष्ट्रीय विकास की योजना अधूरी रहती है।

## अध्याय 4 — सामाजिक न्याय और ग्रामीण भारत

चौधरी चरण सिंह जी के लिए ग्रामीण भारत का प्रश्न खेत और फसल तक सीमित नहीं था। गाँव में अधिकार किसके पास हैं, सरकारी काम में किसकी सुनवाई होती है और कौन सामाजिक स्थिति के कारण पीछे रह जाता है— इन बातों का आर्थिक जीवन से गहरा संबंध है। भूमि सुधारों और ग्रामीण प्रतिनिधित्व पर उनका काम इसी व्यापक संदर्भ में समझा जाना चाहिए। जमीन पर अधिकार केवल आमदनी का साधन नहीं होता। उससे परिवार की सामाजिक स्थिति और स्थानीय प्रभाव भी जुड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति का खेती से जीवन चलता है, लेकिन जमीन पर उसका अधिकार कमजोर है, उसकी निर्भरता बढ़ जाती है। चौधरी चरण सिंह जी के भूमि संबंधी विचारों में इस निर्भरता को कम करने की चिंता थी। जमींदारी उन्मूलन की प्रक्रिया ने ग्रामीण शक्ति संबंधों में परिवर्तन का रास्ता खोला। वास्तविक खेती करने वाले व्यक्ति और राज्य के बीच संबंध बदलने का प्रयत्न हुआ। लेकिन भूमि सुधारों से सभी भूमिहीन परिवारों को समान लाभ नहीं मिला। ग्रामीण न्याय की चर्चा में इस अंतर को स्वीकार करना जरूरी है। किसान की साझा पहचान के भीतर जमीन के मालिक, छोटे काश्तकार और मजदूर की स्थिति अलग हो सकती है। उपज का बेहतर मूल्य किसान को राहत देता है, जबकि खेतिहर मजदूर के लिए मजदूरी, नियमित काम और सम्मानजनक व्यवहार का प्रश्न भी है। दोनों के हितों में सहयोग संभव है, लेकिन वह अपने आप स्थापित नहीं हो जाता। गाँव में आर्थिक और सामाजिक अधिकार एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जिस परिवार के पास अपनी जमीन नहीं है, उसकी रोजी किसी और के यहाँ काम मिलने पर निर्भर हो सकती है। इससे शिकायत रखने की उसकी स्वतंत्रता भी सीमित हो सकती है। दूसरी ओर थोड़ी जमीन मिल जाने पर भी शिक्षा, साधन और प्रशासन तक पहुँच का अभाव बना रह सकता है। इसलिए भूमि संबंधों में परिवर्तन बड़ी शुरुआत थी, लेकिन उसके बाद सार्वजनिक संस्थाओं को अधिक सुलभ बनाने का काम बाकी रहता था। चौधरी चरण सिंह जी की सामाजिक सोच में जाति का प्रश्न भी मौजूद था। उन्होंने जातिगत संकीर्णता की आलोचना की और अंतर्जातीय विवाह को सामाजिक दूरी कम करने के साधन के रूप में महत्व दिया। जाति के नाम पर चलने वाले शिक्षण संस्थानों को सरकारी सहायता देने के प्रश्न पर भी उन्होंने आपत्ति व्यक्त की थी।

इन रुखों के पीछे यह चिंता दिखाई देती है कि सार्वजनिक संस्थाएं किसी एक जाति की सीमित पहचान में बंधकर न रह जाएँ। शिक्षा व्यक्ति को व्यापक समाज से जोड़ने का अवसर देती है। यदि संस्थान की पहचान ही सामाजिक विभाजन को मजबूत करे, तो उसका सार्वजनिक उद्देश्य प्रभावित हो सकता है। उनका जाति संबंधी दृष्टिकोण और राजनीतिक व्यवहार एक लंबे समय में विकसित हुआ। पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व तथा आरक्षण के प्रश्न पर भी उनके रुख में परिवर्तन आया। बाद के वर्षों में उन्होंने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी नीतियों का समर्थन किया। इससे स्पष्ट होता है कि उनकी सामाजिक सोच को जीवन भर एक ही स्थिति में स्थिर मानना उचित नहीं होगा। ग्रामीण परिवारों की प्रशासन में भागीदारी उनके लिए महत्वपूर्ण थी। यदि निर्णय लेने वाली व्यवस्था में गाँव के जीवन को समझने वाले लोग कम हों, तो नीति में उसकी जरूरतें पीछे रह सकती हैं। प्रतिनिधित्व की उनकी चिंता का संबंध इसी दूरी से था। हालांकि किसी ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति का पद पर पहुँचना अपने आप सभी ग्रामीण लोगों की सुनवाई सुनिश्चित नहीं करता। सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रभाव के अंतर बने रह सकते हैं। इसीलिए प्रतिनिधित्व का मूल्यांकन केवल परिचय से नहीं, काम और सार्वजनिक व्यवहार से भी होना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की प्रशासनिक पहचान में भ्रष्टाचार और पक्षपात के विरुद्ध सख्ती का उल्लेख मिलता है। ग्रामीण व्यक्ति के लिए यह प्रश्न विशेष महत्व रखता है। जमीन का रिकॉर्ड, राजस्व का काम या शिकायत की सुनवाई यदि पैसे और पहुँच पर निर्भर हो, तो कमजोर परिवार की कठिनाई बढ़ती है। निष्पक्ष प्रशासन सामाजिक न्याय का व्यावहारिक हिस्सा है। किसी गरीब परिवार के लिए सरकारी दफ्तर का एक चक्कर भी खर्च होता है। उस दिन मजदूरी छूट सकती है, आने-जाने का किराया लगता है और काम न बने तो दोबारा जाना पड़ता है। अधिकारी की देरी इसलिए सभी नागरिकों पर एक जैसा बोझ नहीं डालती। प्रशासन की सख्ती का जनपक्षीय अर्थ तभी निकलता है जब कर्मचारी के ऊपर अनुशासन के साथ आवेदक को स्पष्ट जानकारी और समय पर उत्तर मिले। चौधरी चरण सिंह जी की प्रशासनिक छवि को इस रोजमर्रा के अनुभव से जोड़कर पढ़ने पर उसका महत्व खुलता है। उनकी किसान राजनीति ने मध्यवर्ती कृषक समुदायों को अधिक राजनीतिक महत्व दिया। इससे सत्ता और प्रतिनिधित्व के पुराने ढाँचे में बदलाव आया।

लेकिन इससे नीचे की आर्थिक तथा सामाजिक स्थितियों वाले समूहों के प्रश्न पूरी तरह हल नहीं हुए। यही उनकी उपलब्धियों और सीमाओं को साथ देखने की जरूरत बताता है। महिलाओं के श्रम और अधिकार का प्रश्न भी ग्रामीण न्याय की पूरी तस्वीर में शामिल होना चाहिए। खेत, पशुधन और घर की जिम्मेदारियों में उनका योगदान रहता है, जबकि संपत्ति और निर्णय पर उनका अधिकार अलग विषय हो सकता है। किसी भी ग्रामीण राजनीतिक विरासत का मूल्यांकन करते समय इन अनुभवों को अनदेखा नहीं किया जा सकता।

महिला का खेत पर काम करना और खेती से जुड़े फैसलों में उसकी राय होना अलग अनुभव हो सकते हैं। परिवार की आमदनी में उसका योगदान दिखाई दे, फिर भी उसे किसान के रूप में पहचान कम मिले। ग्रामीण समाज के इतिहास में यह अंतर बार-बार सामने आता है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत पर आगे होने वाली चर्चा के लिए यह एक खुला प्रश्न है कि किसान की परिभाषा में उन लोगों को कितना स्थान मिलता है जिनका श्रम मौजूद है, लेकिन नाम जमीन के कागज पर नहीं है।

चौधरी चरण सिंह जी ने ग्रामीण बहुसंख्यक के आर्थिक और राजनीतिक स्थान को राष्ट्रीय बहस का विषय बनाया। जातिगत विभाजन की आलोचना और प्रतिनिधित्व की चिंता उनके सार्वजनिक जीवन में मौजूद रही। फिर भी गाँव के सभी वर्गों तक उस राजनीति की पहुँच समान नहीं थी। भूमिहीन मजदूर, महिला और कम प्रभाव वाले परिवार के अनुभव उसके अधूरे कामों की याद दिलाते हैं। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का अर्थ इन्हीं अधूरे प्रश्नों को अधिक व्यापक रूप में लेना हो सकता है। गाँव का सम्मान तभी पूरा होगा जब उसके भीतर कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाए। किसान की प्रतिष्ठा के साथ मजदूर, महिला और कम पहुँच वाले परिवार का अधिकार भी ग्रामीण न्याय की चर्चा में स्थान पाए।

## अध्याय 5 — प्रधानमंत्री तक की राजनीतिक यात्रा

चौधरी चरण सिंह जी की प्रधानमंत्री तक की यात्रा लंबे संगठनात्मक अनुभव, नीतिगत मतभेद और राजनीतिक संघर्ष से होकर गुजरी। वे सीधे राष्ट्रीय सत्ता के केंद्र में नहीं पहुँचे थे। उनकी राजनीति जिला स्तर के काम, स्वतंत्रता आंदोलन और प्रांतीय विधानसभा से शुरू हुई थी। राष्ट्रीय नेतृत्व तक आते-आते वे प्रशासन और संगठन की अनेक परिस्थितियाँ देख चुके थे। कांग्रेस उनके सार्वजनिक जीवन का शुरुआती राजनीतिक मंच थी। स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रियता के बाद वे उसी दल के विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में विभिन्न जिम्मेदारियों पर रहे। इस दौर में भूमि सुधार और खेती से जुड़े विषयों पर उनका काम आगे बढ़ा।

समय के साथ कांग्रेस के भीतर उनके मतभेद गहरे हुए। आर्थिक प्राथमिकताओं, ग्रामीण हितों और प्रशासनिक कामकाज पर उनके अपने स्पष्ट विचार थे। वे बड़े नेतृत्व से असहमत होने पर भी अपना पक्ष रखते थे। यह स्वभाव उनके समर्थकों के लिए दृढ़ता का प्रमाण था, जबकि राजनीतिक सहयोग में कभी-कभी कठिनाई भी पैदा करता था। 1967 में कांग्रेस से अलग होने का उनका फैसला निर्णायक साबित हुआ। उत्तर प्रदेश में गैर-कांग्रेसी दलों के सहयोग से संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी और 3 अप्रैल 1967 को चौधरी चरण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। यह प्रदेश की राजनीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इस सरकार में अलग-अलग विचारधाराओं वाले दल शामिल थे। कांग्रेस के विरोध ने उन्हें साथ आने का आधार दिया था, लेकिन सरकार चलाने के प्रश्न पर सबकी प्राथमिकताएँ समान नहीं थीं। साझा विरोध और साझा प्रशासन के बीच यह अंतर उस दौर में स्पष्ट हुआ। उत्तर प्रदेश की उस सरकार में कृषि की प्राथमिकताओं के साथ दलों के बीच विश्वास का प्रश्न लगातार उपस्थित था। सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या और सरकार चलाने के लिए आवश्यक सहमति एक ही बात नहीं थीं। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक फैसले लेने थे, जबकि सहयोगी अपने संगठन और मतदाताओं की अपेक्षाएँ लेकर आए थे। चौधरी चरण सिंह जी का स्पष्ट रुख उन्हें एक अलग पहचान देता था, लेकिन विभिन्न पक्षों को एक निर्णय तक लाने का काम फिर भी करना पड़ता था।

उनका पहला मुख्यमंत्री कार्यकाल 25 फरवरी 1968 तक रहा। फरवरी 1970 में वे दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और अक्टूबर 1970 तक इस पद पर रहे। दोनों कार्यकाल अपेक्षाकृत छोटे थे, लेकिन उन्होंने गठबंधन सरकार की संभावनाओं और उसकी अस्थिरता का अनुभव दिया। इसी बीच किसान आधारित राजनीतिक संगठन को अधिक व्यापक रूप देने का प्रयास आगे बढ़ा। भारतीय क्रांति दल के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस से अलग एक राजनीतिक धारा को मजबूत किया। 1974 में भारतीय लोकदल के निर्माण में उनकी केंद्रीय भूमिका रही। उद्देश्य विभिन्न विपक्षी समूहों को एक अधिक प्रभावी राजनीतिक विकल्प में संगठित करना था।

आपातकाल ने राष्ट्रीय राजनीति की दिशा बदल दी। चौधरी चरण सिंह जी भी उस दौर में कारावास में रहे। विपक्ष के नेताओं और दलों के बीच सहयोग की जरूरत बढ़ी। 1977 में जनता पार्टी के माध्यम से विभिन्न धाराएँ साथ आईं और केंद्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी।

आपातकाल के बाद बनी विपक्षी एकता में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली का व्यापक आग्रह था। लेकिन उसके भीतर समाजवादी, किसान आंदोलन से जुड़े और दूसरी राजनीतिक परंपराओं के लोग भी थे। सत्ता परिवर्तन ने उन्हें एक सरकार में पहुँचा दिया; पुराने मतभेद उसी क्षण समाप्त नहीं हुए। चौधरी चरण सिंह जी की राष्ट्रीय भूमिका इस परिस्थिति में बनी, जहाँ जनता की बड़ी उम्मीदों के साथ सरकार के भीतर सहयोग की कठिन परीक्षा भी चल रही थी।

श्री मोरारजी देसाई जी की सरकार में चौधरी चरण सिंह जी ने गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। बाद में वे उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बने। अब उनके सामने उत्तर प्रदेश से कहीं बड़ा प्रशासनिक दायरा था। लेकिन जनता पार्टी के भीतर मतभेद और नेतृत्व संबंधी तनाव बने रहे। इस सरकार की कठिनाइयाँ बताती हैं कि अलग राजनीतिक परंपराओं का विलय केवल चुनावी सफलता से पूरा नहीं होता। संगठन, विचार और व्यक्तिगत नेतृत्व के प्रश्न बाद में भी सामने आते हैं। चौधरी चरण सिंह जी इन संघर्षों के प्रमुख पक्षों में थे।

जनता पार्टी सरकार के संकट के बाद 28 जुलाई 1979 को उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस के बाहरी समर्थन ने सरकार बनने का रास्ता खोला, लेकिन यह समर्थन स्थायी नहीं रहा। लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने से पहले ही समर्थन वापस ले लिया गया और उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। वे नई सरकार बनने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहे। उनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 तक चला। इस तरह उनका प्रधानमंत्री पद का समय लगभग छह महीने का रहा, जिसमें स्वतंत्र रूप से दीर्घकालीन कार्यक्रम लागू करने की राजनीतिक गुंजाइश बहुत सीमित थी।

यह उनके जीवन का विरोधाभासी क्षण था। लंबे संघर्ष के बाद सर्वोच्च कार्यकारी पद मिला, लेकिन उसे स्थिर संसदीय आधार नहीं मिला। प्रधानमंत्री की शपथ और लोकसभा का विश्वास दो अलग संवैधानिक पड़ाव हैं। उनकी सरकार दूसरे पड़ाव तक पहुँचने से पहले संकट में आ गई। इस घटना को निजी सफलता या विफलता के एक वाक्य में समेट देने से उस समय की संसदीय राजनीति छूट जाती है, जिसमें बाहर से मिला समर्थन सरकार की बुनियाद बन सकता था और उसके हटते ही वही बुनियाद कमजोर हो सकती थी।

प्रधानमंत्री बनना उनकी लंबी राजनीतिक यात्रा का शिखर था। वहीं बहुमत का स्थायित्व न मिल पाने से सत्ता की सीमा भी सामने आ गई। लंबे प्रशासनिक अनुभव और मजबूत जनपरिचय के बावजूद सरकार चलाने के लिए सहयोगियों के समर्थन की जरूरत बनी रही। उनकी पूरी सार्वजनिक यात्रा को केवल छोटे प्रधानमंत्री कार्यकाल से मापना भी अधूरा होगा। भूमि सुधार, ग्रामीण आर्थिक विचार और किसान संगठन पर उनका काम इससे दशकों पहले शुरू हो चुका था। प्रधानमंत्री पद उस यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव था, उसका संपूर्ण अर्थ नहीं। दिल्ली की सत्ता तक पहुँचने के बाद भी उनकी पहचान किसान से जुड़ी रही। गाँव के प्रश्नों पर उनकी जिद और आर्थिक प्राथमिकताओं पर उनका अलग दृष्टिकोण भारतीय राजनीति में उनकी विशिष्ट जगह बनाता है। उनकी यात्रा सत्ता प्राप्त करने के साथ इस प्रश्न की यात्रा भी थी कि राष्ट्रीय निर्णयों में ग्रामीण भारत कितना उपस्थित है।

## अध्याय 6 — उनके प्रमुख पद, सम्मान और भारत रत्न

चौधरी चरण सिंह जी के सार्वजनिक जीवन में अनेक पद आए, लेकिन हर पद के पीछे अलग जिम्मेदारी और अलग परिस्थिति थी। विधानसभा सदस्य के रूप में कानून बनाना, मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश चलाना और केंद्रीय मंत्री के रूप में राष्ट्रीय प्रशासन संभालना एक जैसी भूमिकाएं नहीं हैं। उनके जीवन की व्यापकता इन्हीं अलग-अलग स्तरों पर दिखाई देती है। 1937 में विधानसभा पहुँचने के साथ उनकी विधायी यात्रा शुरू हुई। स्वतंत्रता से पहले ही उन्होंने ग्रामीण कर्ज और किसान हितों से जुड़े प्रश्न उठाए। बाद में उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव और मंत्री के रूप में काम किया। कृषि, राजस्व तथा अन्य विभागों की जिम्मेदारियों ने उन्हें प्रशासन के व्यावहारिक पक्ष से जोड़ा। प्रांतीय प्रशासन में बिताए वर्षों ने उन्हें सरकारी काम की अलग-अलग परतों से परिचित कराया। भूमि और राजस्व के प्रश्न सीधे किसान तक पहुँचते थे, जबकि न्याय और प्रशासन का असर उसकी शिकायत की सुनवाई पर पड़ता था। इन्हें अलग विभागों के नामों में रखा जा सकता है, लेकिन नागरिक के जीवन में इनके बीच दूरी नहीं रहती। जमीन का विवाद होने पर उसे रिकॉर्ड भी चाहिए, सुनवाई भी और निर्णय का पालन भी। उनके सार्वजनिक अनुभव की व्यापकता इसी मेल में थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में उनके दो कार्यकाल रहे। पहला 3 अप्रैल 1967 से 25 फरवरी 1968 तक और दूसरा 18 फरवरी 1970 से 1 अक्टूबर 1970 तक। ये कार्यकाल गठबंधन राजनीति की जटिल परिस्थितियों में बीते। उनके प्रशासनिक अनुभव का महत्व अवधि के साथ उस राजनीतिक परिवर्तन में भी था जिसका वे नेतृत्व कर रहे थे। राष्ट्रीय राजनीति में उन्होंने गृह मंत्री, उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री की जिम्मेदारियाँ निभाईं। वित्त मंत्री के रूप में प्रस्तुत 1979-80 का बजट उनके ग्रामीण आर्थिक आग्रह को समझने का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ग्रामोद्योग और छोटे उत्पादन जैसे विषयों को आर्थिक प्राथमिकताओं में स्थान देने की उनकी चिंता वहाँ भी दिखाई देती है। 28 जुलाई 1979 को वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 14 जनवरी 1980 तक रहे इस कार्यकाल ने उन्हें देश के सर्वोच्च कार्यकारी पद तक पहुँचाया। राजनीतिक परिस्थितियों ने इसकी अवधि सीमित कर दी, लेकिन प्रधानमंत्री के रूप में उनका स्थान भारतीय इतिहास का स्थायी हिस्सा है।

उनके पदों के साथ उनकी बौद्धिक भूमिका को भी उचित महत्व मिलना चाहिए। वे नियमित रूप से लिखते थे और अपनी आर्थिक तथा सामाजिक मान्यताओं को विस्तार से रखते थे। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी: टू ऑल्टरनेटिव्स, जॉइंट फार्मिंग एक्स-रेड, इंडियाज़ पॉवर्टी एंड इट्स सॉल्यूशन और इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी: द गांधियन ब्लूप्रिंट जैसी पुस्तकें उनके अध्ययन और सार्वजनिक तर्क का परिचय देती हैं। किसी नेता की पुस्तकें केवल उसके प्रशंसकों के लिए नहीं होतीं। उनसे असहमत व्यक्ति भी उसके विचारों को सीधे पढ़ सकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपने पक्ष को लिखित रूप में छोड़कर यही संभावना दी। इससे उनकी विरासत स्मृतियों और भाषणों से आगे विचार की दुनिया में भी बनी रही। इन पुस्तकों को पढ़ते समय उनके लिखे जाने के दौर को भी सामने रखना पड़ता है। कहीं जमींदारी समाप्त करने के विकल्प हैं, कहीं संयुक्त खेती के प्रस्ताव पर बहस है और कहीं राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं का प्रश्न। विषय बदलते हैं, लेकिन उत्पादन करने वाले व्यक्ति की स्वतंत्रता की चिंता बार-बार लौटती है। लेखन ने उन्हें तत्काल राजनीतिक विवाद से बाहर अपने तर्क विस्तार से रखने का अवसर दिया। पाठक उन तर्कों से सहमत हो या असहमत, उसके सामने विचार का पूरा आधार मौजूद रहता है। उनके प्रति किसानों के बीच सम्मान का आधार उनका लंबे समय का काम था। सार्वजनिक जीवन में मिला ऐसा विश्वास सरकारी सम्मान से अलग महत्व रखता है। किसी किसान को यह महसूस होना कि उसकी समस्या राष्ट्रीय चर्चा में जगह पा रही है, नेतृत्व के साथ गहरा संबंध बना सकता है। 9 फरवरी 2024 को चौधरी चरण सिंह जी को मरणोपरांत भारत रत्न देने की घोषणा हुई। यह देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस घोषणा ने उनके योगदान को फिर व्यापक सार्वजनिक चर्चा के केंद्र में लाया। किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े उनके जीवन के विभिन्न पक्षों को याद किया गया। 30 मार्च 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु जी ने यह सम्मान प्रदान किया। चौधरी चरण सिंह जी की ओर से उनके पौत्र जयंत चौधरी जी ने भारत रत्न ग्रहण किया। परिवार के लिए यह विशेष भावनात्मक क्षण था, और उनके विचारों से जुड़े लोगों के लिए राष्ट्रीय मान्यता का अवसर। सम्मान का महत्व केवल समारोह तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उससे नई पीढ़ी में उनके जीवन और विचारों को जानने की रुचि बढ़ सकती है। जमीन, किसान स्वामित्व और ग्रामीण उत्पादन पर उन्होंने क्या कहा था, यह प्रश्न फिर सामने आ सकता है।

राजकीय सम्मान किसी नए पाठक को उस जीवन की ओर मोड़ सकता है जिसे वह पहले केवल नाम से जानता था। नई पीढ़ी के लिए उपयोगी प्रश्न यह होगा कि उस नाम के पीछे कौन-सी बहसें थीं और वे क्यों उठीं। किसान की जमीन, गाँव का रोजगार और उत्पादन की कमाई में मेहनतकश का हिस्सा जैसे विषय समारोह के बाद भी बने रहते हैं। सम्मान की स्मृति तब अधिक समृद्ध होती है जब उसके साथ पढ़ने, सवाल पूछने और विचारों पर बातचीत करने की जगह बढ़ती है।

भारत रत्न ने उनके योगदान को राष्ट्रीय सम्मान दिया। उनके राजनीतिक फैसलों पर बहस फिर भी खुली है। भूमि सुधार और किसान के सम्मान के लिए किए गए काम की अहमियत बनी रहती है, साथ ही उनके दौर की सीमाओं और मतभेदों को समझने की गुंजाइश भी। उनका सबसे बड़ा परिचय पदों की सूची से आगे उस विषय में है जिसे उन्होंने लगातार उठाया। किसान की मेहनत का मूल्य, छोटे उत्पादक की स्वतंत्रता और ग्रामीण जीवन का सम्मान उनके काम की केंद्रीय चिंताएं थीं। औपचारिक सम्मान इस योगदान को राष्ट्रीय स्मृति में स्थान देता है; उसका जीवित अर्थ लोगों की जिंदगी से जुड़े प्रश्नों में बना रहता है।

## अध्याय 7 – मुस्लिम समाज और चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति

चौधरी चरण सिंह जी और मुस्लिम समाज के संबंध को समझने के लिए खेती, नागरिक सुरक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को साथ देखना होगा। मुस्लिम किसान की समस्या में फसल की लागत और भुगतान शामिल हैं, लेकिन उसका जीवन केवल इन्हीं प्रश्नों से नहीं बनता। प्रशासन का व्यवहार, सांस्कृतिक सम्मान और सार्वजनिक जीवन में अपनी आवाज की जगह भी उसके लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी की किसान राजनीति ने मुस्लिम कृषकों के साथ सहयोग का आर्थिक आधार दिया। खेत की उपज, कर्ज और सिंचाई के प्रश्न अलग-अलग धर्मों के किसानों को साथ ला सकते थे। लेकिन इस साझा आधार को पूरे मुस्लिम समाज का एक जैसा अनुभव मानना उचित नहीं होगा। कस्बे के कारीगर, दुकानदार, मजदूर और शिक्षित युवक की जरूरतें अलग हो सकती थीं। मसलन, अपनी जमीन पर खेती करने वाले परिवार और दूसरे के खेत में मजदूरी करने वाले परिवार का किसी किसान दल से संबंध अलग वजहों से बन सकता था। एक के लिए फसल का दाम प्रमुख था, दूसरे के लिए काम मिलने और मजदूरी का प्रश्न। कस्बे का कारीगर इन्हीं ग्रामीण परिवारों को अपना माल बेचता था, फिर भी उसके सामने कच्चे माल और बिक्री की अलग कठिनाइयाँ थीं। साझा धार्मिक पहचान इन आर्थिक अंतरों को मिटाती नहीं थी। इसी विविधता के भीतर किसान राजनीति और मुस्लिम समाज का रिश्ता विकसित हुआ।

उनके लंबे राजनीतिक जीवन में मुस्लिम समाज के साथ संबंध हर समय एक जैसे नहीं रहे। विभाजन के आसपास का भय और अविश्वास, उत्तर प्रदेश की स्थानीय परिस्थितियाँ तथा बाद के राजनीतिक सहयोग अलग संदर्भ रखते हैं। इन सबको एक ही स्थायी संबंध मान लेने से समय के साथ आए परिवर्तन छूट जाएँगे। बाद के वर्षों में अल्पसंख्यक सुरक्षा और सांस्कृतिक प्रश्नों पर उनके सार्वजनिक हस्तक्षेप अधिक स्पष्ट रूप से सामने आए। किसान के आर्थिक अधिकार की चर्चा के साथ मुस्लिम नागरिक के अपने अनुभव भी उनकी राजनीतिक सक्रियता में जगह पाने लगे।

सत्तर के दशक में भारतीय क्रांति दल की राजनीति में मुस्लिम सुरक्षा और सांस्कृतिक विषयों पर अधिक स्पष्ट सक्रियता दिखाई देती है। 1973 में चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार की आलोचना करते हुए वाराणसी की मुस्लिम-विरोधी हिंसा और उर्दू से जुड़ी संस्थाओं के अनुदान के प्रश्न उठाए। सरकार की भूमिका के बारे में उनके आरोप राजनीतिक आरोप थे। उन्हें अपने आप सिद्ध तथ्य नहीं माना जा सकता। लेकिन इन मुद्दों पर उनका हस्तक्षेप महत्वपूर्ण था। उसी दौर में भारतीय क्रांति दल ने पुलिस कार्रवाई में मुसलमानों की मौतों की न्यायिक जांच की मांग की। इसके साथ अनुसूचित जातियों के विरुद्ध भेदभाव और अपराधों का प्रश्न भी उठाया गया। इससे पार्टी की चिंता में राज्य की जवाबदेही और कमजोर वर्गों की सुरक्षा का स्थान दिखाई देता है। किसी असुरक्षित समुदाय के लिए ऐसी मांग का महत्व होता है। वह यह संदेश देती है कि सरकारी कार्रवाई भी जांच से बाहर नहीं हो सकती। लेकिन मांग उठाना और वास्तविक न्याय मिलना अलग पड़ाव हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप का महत्व स्वीकार करते हुए उसके परिणाम को भी देखना चाहिए। मुस्लिम नेतृत्व के साथ संगठित सहयोग का उदाहरण 1974 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौर में मिलता है। भारतीय क्रांति दल और मुस्लिम मजलिस के बीच चुनावी सहयोग बना। इसमें मुस्लिम राजनीतिक नेतृत्व अपनी भूमिका और अपेक्षाओं के साथ शामिल था। संबंध केवल मतदाताओं से समर्थन मांगने का नहीं, संगठनों के बीच साझेदारी का भी था। इस सहयोग में मुस्लिम नेतृत्व की स्वतंत्र पहल का महत्व भी स्वीकार करना चाहिए। किसी गठबंधन में शामिल होने वाला पक्ष अपनी अपेक्षाएँ, सामाजिक संबंध और राजनीतिक समझ लेकर आता है। उसे केवल किसी बड़े नेता द्वारा साथ ले आए समूह के रूप में देखना उसकी भूमिका को छोटा कर देता है। ऐसी साझेदारी में एक-दूसरे की भाषा और प्राथमिकताओं को समझना पड़ता है। ग्रामीण आय का मुद्दा रखने वाला नेतृत्व यदि अल्पसंख्यक नागरिक की सुरक्षा की बात भी सुने, तो बातचीत का दायरा बढ़ता है। उसी तरह मुस्लिम संगठन का खेती और क्षेत्रीय प्रशासन के प्रश्नों में हिस्सा लेना उसे केवल धार्मिक मामलों तक सीमित नहीं रहने देता। साझेदारी की संभावना इसी आदान-प्रदान में थी। उसका अर्थ किसी पक्ष की स्वतंत्र राय समाप्त होना नहीं था। चौधरी चरण सिंह जी की छोटे उद्योग और कारीगर संबंधी आर्थिक सोच का मुस्लिम समाज के कुछ वर्गों के लिए भी महत्व हो सकता था।

हथकरघा, छोटे उत्पादन और ग्रामीण रोजगार को महत्व देने वाली नीति संबंधित पेशों में काम करने वाले लोगों तक अवसर पहुँचा सकती है। लेकिन इससे किसी धार्मिक समुदाय को हुए वास्तविक लाभ की मात्रा बिना प्रमाण के तय नहीं की जा सकती।

इस संबंध की सबसे बड़ी कसौटी भरोसा था। किसान की साझा मांग लोगों को साथ ला सकती है, लेकिन सांस्कृतिक सम्मान और निष्पक्ष प्रशासन भी जरूरी हैं। किसी व्यक्ति से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आर्थिक सहयोग के लिए वह अपनी सुरक्षा या गरिमा के प्रश्न पीछे रख दे। भरोसे का एक व्यावहारिक पहलू संकट के बाहर की मौजूदगी भी है। विद्यालय, सड़क, स्थानीय रोजगार या सार्वजनिक सुविधा पर साथ काम करने से लोग एक-दूसरे को केवल तनाव के समय सामने आने वाली पहचान से अलग देख पाते हैं। राजनीतिक संबंधों का इतिहास पढ़ते हुए ऐसे साधारण प्रश्नों की अहमियत बनी रहती है। किसी समुदाय की चिंता का सम्मान करने वाला संबंध उसे हर समय एक समस्या या चुनावी गणना की तरह नहीं देखता; उसमें नागरिक के सामान्य जीवन के लिए भी स्थान होता है।

इस संबंध में किसान की साझा आर्थिक मांगों के साथ अल्पसंख्यक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी के प्रश्न जुड़ते गए। चौधरी चरण सिंह जी की ग्रामीण आर्थिक सोच ने सहयोग का आधार दिया। मुस्लिम नेतृत्व और नागरिकों की अपनी पहल ने भी उसे आगे बढ़ाया। यह संबंध दोनों पक्षों के अनुभव से बना था। इसी पृष्ठभूमि में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट-मुस्लिम किसान साझेदारी को देखा जाना चाहिए। वह केवल चुनावी गणना नहीं थी। उसमें रोजमर्रा का ग्रामीण जीवन, आर्थिक हित और नेतृत्व पर भरोसा शामिल था। उसकी ताकत और उसकी सीमाएँ, दोनों इसी सामाजिक धरातल पर बनीं।

## अध्याय 8 – पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट-मुस्लिम किसान साझेदारी

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती ने लोगों के बीच अनेक संबंध बनाए हैं। खेतों की सीमाएँ अलग हो सकती हैं, लेकिन सिंचाई, बाजार, ढुलाई और मजदूरी की व्यवस्था में लोग एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसी ग्रामीण जीवन के भीतर जाट-मुस्लिम किसान साझेदारी विकसित हुई। चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति ने उसे एक व्यापक किसान पहचान से जोड़ा। इस साझेदारी का उल्लेख करते समय शब्दों की सीमा समझना जरूरी है। जाट एक सामाजिक पहचान है और मुस्लिम धार्मिक पहचान। मुस्लिम जाट भी हैं। इसी तरह क्षेत्र में अलग-अलग धर्मों के गुर्जर और राजपूत समुदायों के बीच भी सामाजिक तथा आर्थिक समानताएं रही हैं। इसलिए प्रचलित राजनीतिक भाषा में कही जाने वाली जाट-मुस्लिम साझेदारी के भीतर कई तरह के संबंध शामिल थे। इन संबंधों का आधार केवल एक मंच या समझौता नहीं था। गाँव में साथ रहना, एक ही बाजार से जुड़ना और खेती की समस्याओं का सामना करना परिचय पैदा करता है। किसी किसान को पानी की जरूरत हो या फसल का मूल्य कम मिले, तो दूसरे धर्म का किसान भी उसी परेशानी को अपने अनुभव से समझ सकता है। चौधरी चरण सिंह जी ने इस साझा अनुभव को राजनीतिक महत्व दिया। किसान अपनी मांग रखने वाला संगठित नागरिक बन सकता था। खेती और ग्रामीण उत्पादन पर सरकारी ध्यान की मांग अलग-अलग कृषक समूहों को एक साथ ला सकती थी। उनकी राजनीति में यही संभावना प्रभावशाली बनी। लेकिन गाँव की आर्थिक निर्भरता को अपने आप बराबरी नहीं माना जा सकता। जमीन के मालिक और मजदूर के संबंध में शक्ति का अंतर हो सकता है। कुछ परिवारों का स्थानीय प्रभाव अधिक और कुछ का कम हो सकता है। किसान एकता की तस्वीर में इन अंतरों को भी जगह मिलनी चाहिए। आर्थिक संबंधों की इसी जटिलता में साझेदारी की ताकत और कठिनाई, दोनों थीं। बाजार में लेन-देन चलता रहे, इससे मेलजोल बना रह सकता है; पर उससे यह तय नहीं हो जाता कि विवाद में दोनों पक्षों की सुनवाई बराबर होगी। किसान एकता का राजनीतिक महत्व इसलिए अधिक था कि वह अलग परिवारों को एक साझा सार्वजनिक मांग में शामिल कर सकती थी।

उस एकता की सामाजिक गहराई का पता गाँव के कमजोर व्यक्ति के अनुभव से चलता था। राजनीतिक साझेदारी का अर्थ यह नहीं था कि सभी जाट या सभी मुसलमान एक ही दल के साथ थे। लोगों की अपनी पसंद, स्थानीय अनुभव और नेतृत्व से संबंध थे। चौधरी चरण सिंह जी का योगदान विभिन्न समूहों के बीच सहयोग का रास्ता बनाने में था, पूरे समाज की राजनीतिक विविधता समाप्त करने में नहीं।

उनके बाद किसान आंदोलनों में भी साझा आर्थिक मुद्दों पर सहयोग दिखाई दिया। चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व वाली भारतीय किसान यूनियन ने बिजली, पानी और फसल के दाम जैसे प्रश्नों पर बड़े आंदोलन किए। उसके साथ मुस्लिम किसान और नेता भी सक्रिय रहे। श्री गुलाम मोहम्मद जौला जी की भूमिका इस इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसान संगठन और राजनीतिक दल की भूमिकाएं अलग थीं। आंदोलन में साथ बैठने वाले लोग चुनाव में अलग पसंद रख सकते थे। किसी साझा धरने से एक दल के लिए स्थायी समर्थन का निष्कर्ष नहीं निकलता। आर्थिक सहयोग और दलीय निष्ठा एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, लेकिन उनका संबंध हर परिस्थिति में एक जैसा नहीं होता। आंदोलन में साथ आने की अपनी प्रक्रिया होती है। लोग घर और काम से समय निकालते हैं, आने-जाने का खर्च उठाते हैं और पड़ोस के व्यक्ति की मांग सुनते हैं। उस दौरान उन्हें पता चल सकता है कि जिस मुश्किल को वे अपने खेत तक सीमित समझते थे, वह पूरे इलाके में है। इससे राजनीतिक समझ बढ़ती है। फिर भी आंदोलन समाप्त होने के बाद लोगों की अन्य चिंताएं बनी रहती हैं। धर्म, स्थानीय संबंध और उम्मीदवार का व्यवहार उनकी चुनावी पसंद को अलग दिशा दे सकते हैं।

इस साझेदारी की मजबूती विश्वास पर निर्भर थी। कठिन समय में साथ खड़े होने का अनुभव उसे गहरा कर सकता था। दूसरी ओर सामाजिक तनाव और असुरक्षा उसे कमजोर कर सकते थे। आर्थिक हित साझा हों, तब भी भय बढ़ने पर लोग एक-दूसरे से दूर हो सकते हैं। 2013 की मुजफ्फरनगर और आसपास की हिंसा ने इसी विश्वास को गंभीर चोट पहुँचाई। उसका असर चुनावी परिणामों से कहीं अधिक गहरा था। मौत, विस्थापन और पड़ोस के टूटने ने परिवारों का जीवन बदला। जिन लोगों को घर छोड़ना पड़ा, उनके लिए काम और बच्चों की पढ़ाई के रास्ते भी प्रभावित हुए।

इस इतिहास का उल्लेख चौधरी चरण सिंह जी की राजनीति के बाद के सामाजिक आधार को समझने के लिए आवश्यक है। हिंसा उनके निधन के बहुत बाद हुई, लेकिन उसने उस क्षेत्र की किसान साझेदारी की कमजोरी उजागर की जिसे उनकी राजनीति से भी बल मिला था। पुराने संबंधों की स्मृति संकट में अपने आप पर्याप्त साबित नहीं हुई।

बाद के किसान आंदोलन में फिर संवाद के अवसर बने। पुराने सहयोगियों के बीच मुलाकातें हुईं और लोगों ने साझा मुद्दों पर साथ आने का प्रयास किया। इन घटनाओं से मेल-मिलाप की संभावना दिखाई देती है। फिर भी मंच पर नेताओं का साथ आना हर पीड़ित परिवार के भरोसे की बहाली नहीं माना जा सकता। स्थायी संबंध के लिए सुरक्षा, न्याय और सम्मान का महत्व बना रहता है। साझा आर्थिक मांग के साथ यह भरोसा भी चाहिए कि किसी विवाद में व्यक्ति की बात उसकी पहचान के कारण कमजोर नहीं पड़ जाएगी। प्रशासन का निष्पक्ष व्यवहार और स्थानीय नेतृत्व की जिम्मेदारी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण हैं। मेल-मिलाप में स्मृति को मिटा देना आवश्यक नहीं है। जिन परिवारों ने साथ काम किया था, वे पुराने अनुभव को याद कर सकते हैं; जिनको नुकसान हुआ, वे अपना दुख और न्याय की मांग भी रख सकते हैं। दोनों बातें एक ही संवाद में मौजूद रह सकती हैं। संबंध तभी अधिक भरोसेमंद बनते हैं जब साथ आने की शर्त पीड़ित की चुप्पी न हो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक इतिहास को समझने में यह बात किसान एकता के आर्थिक तर्क जितनी ही महत्वपूर्ण है।

चौधरी चरण सिंह जी की विरासत इस पूरे इतिहास में किसान को राजनीतिक सम्मान देने के विचार के रूप में मौजूद है। उनकी राजनीति ने दिखाया कि ग्रामीण जीवन के साझा प्रश्न अलग-अलग समुदायों को साथ ला सकते हैं। बाद के अनुभव बताते हैं कि उस सहयोग को बनाए रखने के लिए बराबरी और सामाजिक भरोसे पर भी लगातार काम करना पड़ता है। इस साझेदारी में खेती लोगों के मिलने का आधार देती थी और सामाजिक व्यवहार उस संबंध को टिकाता था। चौधरी चरण सिंह जी के बाद यही आधार चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति तक पहुँचा। उन्हें किसान के साझा हितों के साथ उन सामाजिक संबंधों को भी संभालना था जिनसे राजनीतिक भरोसा बनता है।

## भाग 2 — चौधरी अजीत सिंह जी: विरासत से आधुनिक राजनीति तक

### अध्याय 9 — चौधरी अजीत सिंह जी: संक्षिप्त जीवनी

चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन की शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उस परिवार में हुई, जिसका नाम आगे चलकर देश की किसान राजनीति की पहचान बना। उनके पिता चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों की आर्थिक कठिनाइयों और ग्रामीण समाज के सम्मान को अपने सार्वजनिक जीवन का केंद्र बनाया था। इस परिवार में जन्म लेने के बावजूद चौधरी अजीत सिंह जी ने अपनी युवावस्था में शिक्षा और तकनीकी पेशे का रास्ता चुना। राजनीति में सक्रिय होने से पहले वे पढ़ाई, विदेश प्रवास और लंबे पेशेवर जीवन से गुजर चुके थे। उनका जन्म 12 फरवरी 1939 को भदोला गाँव में हुआ, जो उस समय मेरठ जिले का हिस्सा था। उनकी शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में हुई। इसके बाद वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए और शिकागो के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अध्ययन किया। बीएससी, बीटेक और एमएस की योग्यताओं के साथ उन्होंने कंप्यूटर उद्योग में अपना पेशेवर जीवन शुरू किया। अमेरिका के कंप्यूटर उद्योग में उन्होंने पंद्रह वर्ष काम किया। यह उनके जीवन का एक लंबा और स्वतंत्र दौर था। भारत में उनके पिता का राजनीतिक कद बढ़ रहा था, जबकि वे अपने पेशे में अनुभव प्राप्त कर रहे थे। उनकी जीवनयात्रा का यह पक्ष अक्सर राजनीतिक परिचय के पीछे छूट जाता है। राजनीति में आने तक वे केवल एक प्रतिष्ठित नेता के पुत्र नहीं थे; उनके पास अपनी शिक्षा, विशेषज्ञता और वर्षों के काम का अनुभव भी था। 17 जून 1967 को उनका विवाह श्रीमती राधिका सिंह जी से हुआ। उनके परिवार में एक पुत्र और दो पुत्रियाँ हुईं। उनके पुत्र जयंत चौधरी जी ने आगे चलकर सार्वजनिक जीवन का रास्ता अपनाया। इस प्रकार जिस परिवार की राजनीतिक पहचान चौधरी चरण सिंह जी के संघर्षों से बनी थी, उसमें अगली पीढ़ियों की भागीदारी भी जुड़ती गई। भारत लौटने के बाद चौधरी अजीत सिंह जी किसान ट्रस्ट से जुड़े और उसके उपाध्यक्ष बने। तकनीकी पेशे से ग्रामीण सार्वजनिक जीवन की ओर बढ़ने में यह एक महत्वपूर्ण पड़ाव था।

कृषि और तकनीक, दोनों उनकी रुचि के विषय थे। उनके सामने अब उन लोगों की समस्याएं भी थीं जिनके जीवन और संघर्षों से उनके पिता की राजनीति का गहरा संबंध रहा था। सक्रिय राजनीति में उनका प्रवेश उस समय हुआ जब चौधरी चरण सिंह जी का स्वास्थ्य कमजोर पड़ रहा था। 1986 में वे राज्यसभा के सदस्य चुने गए और उन्होंने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। इसके साथ उनका संसदीय जीवन शुरू हुआ। लंबे पेशेवर अनुभव के बाद वे ऐसे कार्यक्षेत्र में आए थे, जहाँ विषयों की जानकारी के साथ जनसंपर्क, संगठन और राजनीतिक विश्वास की अपनी अहमियत थी। 1987 में चौधरी चरण सिंह जी के निधन ने परिवार और उनके समर्थकों के जीवन में बड़ी रिक्तता पैदा की। किसान राजनीति से जुड़े अनेक लोगों के लिए वे अपने अधिकारों की आवाज थे। उनके बाद उस राजनीतिक धारा के नेतृत्व का प्रश्न सहज नहीं रहा। पुराने सहयोगियों की अपनी भूमिका और आकांक्षाएँ थीं। संगठन के भीतर मतभेद उभरे और लोकदल में विभाजन हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी को इन्हीं परिस्थितियों में अपना राजनीतिक स्थान बनाना पड़ा। पिता की प्रतिष्ठा उनके लिए एक बड़ी पूंजी थी, लेकिन उसके साथ अपेक्षाओं का भार भी जुड़ा था। चौधरी चरण सिंह जी के समर्थक उनके पुत्र में अपने पुराने संबंध की निरंतरता देखना चाहते थे। साथ ही नए नेतृत्व को अपने काम से भरोसा पैदा करना था। यह उत्तराधिकार नाम और पद तक सीमित नहीं था। उसमें किसान आंदोलन की स्मृतियाँ, संगठन के पुराने संबंध और गाँवों की अनेक अधूरी उम्मीदें शामिल थीं। चौधरी अजीत सिंह जी 1987 में लोकदल (अ) के अध्यक्ष बने। अगले वर्ष उन्होंने जनता पार्टी की अध्यक्षता संभाली और बाद में जनता दल के महासचिव रहे। इन वर्षों में उनकी राजनीति संगठनात्मक बदलावों से होकर आगे बढ़ी। आगे चलकर राष्ट्रीय लोक दल उनकी राजनीतिक गतिविधियों का प्रमुख आधार बना। उसके माध्यम से उन्होंने किसान राजनीति और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने जनाधार को संगठित रखने का प्रयास किया। 1989 में वे बागपत से पहली बार लोकसभा पहुँचे। बागपत का चौधरी चरण सिंह जी से पुराना राजनीतिक संबंध था और चौधरी अजीत सिंह जी ने यहाँ से कई बार जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके जीवन में इस क्षेत्र का विशेष स्थान रहा। संसद और केंद्र सरकार की जिम्मेदारियों के बीच बागपत उनके राजनीतिक संबंधों का प्रमुख केंद्र बना रहा। फिर भी इस संबंध को लगातार मिलती रही सफलता की कहानी नहीं कहा जा सकता। 1998 और 2014 में उन्हें बागपत में पराजय का सामना करना पड़ा।

2019 में उन्होंने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। इन पराजयों का दौर उनके लंबे सार्वजनिक जीवन का एक कठिन पड़ाव था। उनसे यह भी स्पष्ट हुआ कि पारिवारिक प्रतिष्ठा और पुराने संबंधों के बावजूद जनता का समर्थन समय के साथ बदल सकता है। चुनावी उतार-चढ़ाव के बीच उनका राष्ट्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना रहा। उन्होंने अलग-अलग सरकारों में उद्योग, खाद्य, कृषि और नागरिक उड्डयन मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली। 1989 में वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में उद्योग मंत्री बने। इसके बाद श्री पी. वी. नरसिंह राव जी की सरकार में उन्होंने खाद्य मंत्रालय का कार्यभार संभाला। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में वे कृषि मंत्री रहे और डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। इन मंत्रालयों का दायरा व्यापक था। उद्योग मंत्रालय का संबंध उत्पादन और औद्योगिक विकास से था, जबकि खाद्य और कृषि मंत्रालय सीधे खेती, खाद्यान्न व्यवस्था और ग्रामीण जीवन से जुड़े थे। नागरिक उड्डयन की जिम्मेदारी ने उनके प्रशासनिक कार्यक्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र जोड़ा। उनके जीवन का यह विस्तार दिखाता है कि उनकी भूमिका क्षेत्रीय राजनीति के साथ राष्ट्रीय प्रशासन में भी रही।

चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति का एक प्रमुख पक्ष गठबंधन था। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक धाराओं के साथ काम किया। इससे उन्हें केंद्र की सत्ता में भागीदारी मिली, लेकिन उनके बदलते राजनीतिक संबंध आलोचना का विषय भी बने। उनके समर्थक इन फैसलों में क्षेत्रीय हितों के लिए अवसर देखते थे, जबकि आलोचक उनकी राजनीतिक निरंतरता पर प्रश्न उठाते थे। उनके सार्वजनिक जीवन में उपलब्धियों के साथ यह विवाद भी मौजूद रहा। किसान राजनीति से निकले किसी क्षेत्रीय दल के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बनाए रखना आसान काम नहीं होता। संगठन का अपना आधार होता है, लेकिन सरकार बनाने की संख्या अक्सर उसके पास नहीं होती। ऐसे में सहयोग और समझौते महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी का राजनीतिक जीवन लंबे समय तक इसी परिस्थिति में आगे बढ़ा। उन्हें अपने दल की पहचान बनाए रखते हुए बड़े राजनीतिक गठबंधनों के बीच जगह बनानी पड़ी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति के सामने सामाजिक संबंधों को संभालने की जिम्मेदारी भी थी। इस क्षेत्र में किसान एकता अलग-अलग समुदायों के सहयोग से मजबूत हुई थी।

जाट और मुस्लिम किसानों के बीच संबंध उस व्यापक सामाजिक आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। चौधरी चरण सिंह जी से जुड़ी इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए चौधरी अजीत सिंह जी को बदलते राजनीतिक वातावरण और समुदायों के बीच बढ़ती दूरियों का सामना करना पड़ा। 2013 की हिंसा के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक संबंधों को गहरी चोट पहुँची। उसका असर किसान राजनीति पर भी पड़ा। उनके जीवन के अंतिम वर्षों में सामाजिक संवाद और किसान एकता का प्रश्न फिर प्रमुखता से सामने आया। 2020-21 के किसान आंदोलन को उन्होंने समर्थन दिया और किसानों के पक्ष में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी। लंबे राजनीतिक जीवन के अंतिम दौर तक खेती और ग्रामीण समाज के प्रश्न उनकी सक्रियता से जुड़े रहे।

6 मई 2021 को बयासी वर्ष की आयु में चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया। वे कोविड-19 से संक्रमित थे। उनके निधन के साथ भारतीय राजनीति ने एक ऐसे नेता को खोया जिसने तीन दशकों से अधिक समय तक संसद, राजनीतिक संगठन और केंद्रीय मंत्रिमंडल में काम किया था। वे सात बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए और इससे पहले राज्यसभा के सदस्य भी रहे। चौधरी अजीत सिंह जी अपने पीछे एक ऐसी राजनीतिक यात्रा छोड़ गए जिसमें शिक्षा और तकनीकी अनुभव था, पिता की बड़ी विरासत थी, संगठन बनाने की कोशिशें थीं और सत्ता के साथ संघर्ष के दौर भी थे। उन्होंने उस विरासत को ऐसे समय में संभाला जब किसानों की जरूरतें, ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाएं और देश की राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थीं। उनके जीवन को समझने के लिए चौधरी चरण सिंह जी से मिला संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी अपनी यात्रा का भी उतना ही महत्व है। अमेरिका के कंप्यूटर उद्योग से भारतीय संसद तक पहुँचने वाले इस नेता को अपने जीवन में कई बार नई शुरुआत करनी पड़ी। आगे की पीढ़ी के लिए वे पार्टी और राजनीतिक संबंधों के साथ वे प्रश्न भी छोड़ गए, जिनसे उनका सार्वजनिक जीवन जूझता रहा—किसान की आवाज को प्रभावी कैसे रखा जाए, ग्रामीण समाज को विकास में उचित स्थान कैसे मिले और बदलती राजनीति के बीच लोगों का भरोसा कैसे बनाए रखा जाए।

## अध्याय 10 – तकनीकी शिक्षा से राजनीति तक

चौधरी अजीत सिंह जी का सार्वजनिक जीवन उस उम्र में शुरू हुआ जब वे पढ़ाई पूरी करने के बाद एक लंबा पेशेवर अनुभव प्राप्त कर चुके थे। राजनीति में आने से पहले उनकी अपनी पहचान थी, अपना काम था और भारत से बाहर बिताए हुए वर्षों का अनुभव था। यह बात उनके व्यक्तित्व को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। चौधरी चरण सिंह जी के पुत्र होने के कारण राजनीति उनके पारिवारिक परिवेश में अवश्य थी, लेकिन उन्होंने अपने शुरूआती जीवन का रास्ता शिक्षा और तकनीकी काम के माध्यम से बनाया। लखनऊ विश्वविद्यालय से लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर और फिर शिकागो के इलिनॉय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तक उनकी शिक्षा का विस्तार हुआ। इस यात्रा में उन्हें अलग शिक्षण पद्धतियों और सामाजिक वातावरणों से परिचित होने का अवसर मिला। विज्ञान और इंजीनियरिंग की पढ़ाई में समस्या की बनावट समझना, उसके कारण तलाशना और समाधान को व्यवहार में परखना महत्वपूर्ण होता है। उनकी तैयारी इसी अनुशासन में हुई थी। पढ़ाई के बाद उन्होंने अमेरिका के कंप्यूटर उद्योग में सत्रह वर्ष काम किया। किसी पेशे में इतना समय बिताना जीवन का एक स्वतंत्र अध्याय होता है। उनके लिए तकनीक केवल शैक्षणिक योग्यता नहीं रही; वह कामकाज का क्षेत्र बनी। जब उन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया, तब वे उस पेशेवर जीवन का अनुभव भी अपने साथ लाए। तकनीकी शिक्षा उनके अनुभव का एक पक्ष थी। राजनीति में उसके साथ अलग-अलग लोगों की जरूरतें समझने और उनके बीच रास्ता निकालने की जिम्मेदारी जुड़ी। किसी विषय की अच्छी जानकारी होने पर भी सार्वजनिक निर्णय के परिणाम सबके लिए समान नहीं होते। तकनीकी कार्य में किसी समस्या के लिए निश्चित प्रक्रिया बनाई जा सकती है। राजनीति में एक ही समस्या से प्रभावित लोगों की अपेक्षाएं अलग हो सकती हैं। किसान को अपनी उपज का उचित मूल्य चाहिए, उपभोक्ता को सस्ता खाद्यान्न, मजदूर को बेहतर मजदूरी और सरकार को अपने खर्च का संतुलन बनाए रखना होता है। इन जरूरतों के बीच रास्ता निकालने के लिए जानकारी के साथ संवाद और विश्वास भी आवश्यक हैं। चौधरी अजीत सिंह जी के सामने भारत लौटने के बाद यही सार्वजनिक संसार खुला। किसान ट्रस्ट से उनका जुड़ाव उनके पेशेवर जीवन और ग्रामीण प्रश्नों के बीच एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। कृषि और तकनीक, दोनों में उनकी रुचि थी।

आगे चलकर उनकी राजनीति को इन्हीं दो क्षेत्रों के संबंध में भी समझा जा सकता है—एक ओर खेती पर निर्भर समाज की जरूरतें और दूसरी ओर बदलती अर्थव्यवस्था में शिक्षा, तकनीक तथा नए अवसरों का महत्व। उनके पिता चौधरी चरण सिंह जी ने लंबे जनसंपर्क, संगठन और संघर्ष के माध्यम से अपना राजनीतिक स्थान बनाया था। किसानों के बीच उनकी प्रतिष्ठा दशकों के अनुभव से निकली थी। चौधरी अजीत सिंह जी को उस प्रतिष्ठा का लाभ मिला, लेकिन उसे बनाए रखने की जिम्मेदारी भी मिली। पिता के प्रति सम्मान रखने वाला कार्यकर्ता पुत्र से भी अपेक्षा रखता है। वह अपने पुराने संबंध को आगे बढ़ाना चाहता है, साथ ही नए नेतृत्व की क्षमता को अपने अनुभव से परखता है। पिता से मिले राजनीतिक परिचय में पुराने सहयोगी, अधूरे काम और समर्थकों की उम्मीदें शामिल थीं। नेतृत्व की स्वीकार्यता फिर भी जनता और कार्यकर्ताओं के बीच बननी थी। चौधरी अजीत सिंह जी को उस नाम के साथ अपनी अलग भूमिका स्थापित करनी पड़ी। 1986 में राज्यसभा की सदस्यता के साथ उनकी संसदीय यात्रा शुरू हुई। अब राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखना, विधायी काम को समझना और विभिन्न राजनीतिक धाराओं के बीच संबंध बनाना उनकी जिम्मेदारी का हिस्सा था। यह पेशेवर जीवन से अलग प्रकार की जवाबदेही थी। संसद में विषय की जानकारी जरूरी होती है, लेकिन उसके साथ उन लोगों के अनुभवों को समझना भी जरूरी है जिनके जीवन पर निर्णयों का असर पड़ता है। इसके कुछ ही समय बाद चौधरी चरण सिंह जी का निधन हो गया। इससे परिवार के साथ उस व्यापक राजनीतिक समाज के सामने भी नेतृत्व का प्रश्न खड़ा हुआ जो उनसे जुड़ा हुआ था। संगठन के भीतर मतभेद और विभाजन ने इस दौर को कठिन बनाया। चौधरी अजीत सिंह जी को ऐसी परिस्थितियों में अपनी जगह बनानी पड़ी, जहाँ उनके पिता की विरासत पर केवल पारिवारिक दावा पर्याप्त नहीं था। पुराने सहयोगियों की अपनी राजनीतिक यात्राएं और नेतृत्व की अपनी आकांक्षाएं थीं। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ था। तकनीकी क्षेत्र में उनकी योग्यता और अनुभव का मूल्यांकन उनके काम से होता था। राजनीति में उनके नाम के साथ पिता की स्मृति भी उपस्थित रहती थी। समर्थकों के लिए वह परिचय और अपनत्व का आधार थी; उनके लिए वह निरंतर तुलना की स्थिति भी बनाती थी। अपनी भूमिका स्थापित करते हुए उन्हें विरासत से संबंध बनाए रखना था और बदलते समय के प्रश्नों का उत्तर भी देना था। 1989 में लोकसभा पहुँचने के बाद जनप्रतिनिधित्व का उनका दायरा और प्रत्यक्ष हुआ।

बागपत के मतदाताओं से संबंध का अर्थ केवल संसद में उनकी ओर से बोलना नहीं था। स्थानीय समस्याएं, कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और क्षेत्र की सामाजिक परिस्थितियां भी उस संबंध का हिस्सा थीं। एक जनप्रतिनिधि के सामने छोटी दिखाई देने वाली समस्या भी संबंधित परिवार के लिए सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। सार्वजनिक जीवन में इस अंतर को समझना आवश्यक होता है। उसी वर्ष उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना उनकी यात्रा का एक और उल्लेखनीय पड़ाव था। तकनीकी शिक्षा और पेशेवर अनुभव वाले व्यक्ति के सामने अब राष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक नीति और प्रशासन का कार्यक्षेत्र था। हालांकि उनके कार्यकाल का मूल्यांकन विशिष्ट निर्णयों के आधार पर होना चाहिए, फिर भी यह जिम्मेदारी उनके जीवन के दोनों पक्षों—तकनीकी पृष्ठभूमि और राजनीतिक भूमिका—को एक साथ सामने लाती है। उद्योग और कृषि को अलग-अलग संसार मानकर देखने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी तस्वीर नहीं बनती। खेती को उपकरण, परिवहन, भंडारण और प्रसंस्करण की जरूरत होती है। ग्रामीण परिवारों को खेती के साथ दूसरे रोजगार भी चाहिए। दूसरी ओर उद्योग के लिए बाजार और श्रम उपलब्ध कराने में गाँवों की भूमिका होती है। चौधरी अजीत सिंह जी की जीवनयात्रा इन क्षेत्रों के बीच संबंधों पर विचार करने का अवसर देती है। इस बिंदु पर चौधरी चरण सिंह जी की विरासत से उनका संबंध भी अधिक स्पष्ट होता है। किसान के सम्मान और आर्थिक सुरक्षा का प्रश्न कायम था, लेकिन नई पीढ़ी की आकांक्षाओं में उच्च शिक्षा, पेशेवर रोजगार और गाँव से बाहर के अवसर भी शामिल थे। स्वयं चौधरी अजीत सिंह जी का जीवन दिखाता था कि ग्रामीण पृष्ठभूमि और आधुनिक तकनीकी शिक्षा एक ही व्यक्ति के अनुभव का हिस्सा हो सकती हैं। उनके सामने चुनौती इन अनुभवों को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की थी। व्यक्तिगत योग्यता उपयोगी होती है, लेकिन एक दल को आगे बढ़ाने के लिए कार्यकर्ता, स्थानीय नेतृत्व, नियमित संवाद और स्पष्ट प्राथमिकताएं चाहिए। किसी नेता का अनुभव तभी व्यापक सार्वजनिक महत्व प्राप्त करता है जब उसके आसपास ऐसा संगठन हो जो लोगों की समस्याएं सुने और उन्हें निर्णय की प्रक्रिया तक पहुँचाए। तकनीकी शिक्षा से राजनीति तक चौधरी अजीत सिंह जी की यात्रा इसी कारण एक पेशा छोड़कर दूसरा अपनाने की घटना भर नहीं थी। उसमें व्यक्तिगत जीवन की दिशा बदली, जवाबदेही का स्वरूप बदला और काम का पैमाना बदला। पहले उनके सामने तकनीकी क्षेत्र की जिम्मेदारियां थीं; अब उनके सामने उन लोगों की उम्मीदें थीं जो अपने भविष्य को उनके नेतृत्व से जोड़कर देख रहे थे।

आगे का प्रश्न संगठन का था। चौधरी चरण सिंह जी से मिली किसान राजनीति की विरासत को किस रूप में आगे बढ़ाया जाए, बदलते राजनीतिक वातावरण में उसके लिए जगह कैसे बनाई जाए और कार्यकर्ताओं को किस साझा उद्देश्य के आसपास संगठित किया जाए— चौधरी अजीत सिंह जी की अगली यात्रा इन्हीं प्रश्नों के बीच आगे बढ़ी। राष्ट्रीय लोक दल के निर्माण और विस्तार को समझने की शुरुआत भी यहीं से होती है।

## अध्याय 11 — राष्ट्रीय लोक दल का निर्माण और विस्तार

राष्ट्रीय लोक दल की कहानी चौधरी चरण सिंह जी के बाद किसान राजनीति को एक संगठन के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश से जुड़ी है। उनके जीवनकाल में जो कार्यकर्ता, किसान और स्थानीय नेता एक साथ आए थे, उनके सामने अब नेतृत्व और राजनीतिक दिशा का सवाल था। चौधरी अजीत सिंह जी को इन्हीं लोगों के बीच काम करना था। पिता के नाम से उनके लिए दरवाजे खुलते थे, लेकिन लोगों को साथ बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत, अपने फैसलों और अपने संगठन की जरूरत थी। यह रास्ता सीधा नहीं रहा। लोकदल में विभाजन हुआ, जनता पार्टी और जनता दल के दौर आए और चौधरी अजीत सिंह जी ने कांग्रेस में भी काम किया। इन बदलावों के बीच उनके सामने अपने समर्थकों को एक अलग राजनीतिक मंच पर संगठित रखने का प्रश्न बना रहा। 1996 में कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई। आगे इसी संगठनात्मक यात्रा से राष्ट्रीय लोक दल का स्वरूप सामने आया। 'किसान' और 'कामगार' को एक साथ रखने में उस राजनीति का आशय समझा जा सकता है। खेती के आसपास मजदूर, कारीगर, छोटे दुकानदार और कई दूसरे परिवारों की रोजी-रोटी जुड़ी होती है। किसान की आमदनी घटने का असर गाँव के बाजार पर भी पड़ता है। चौधरी अजीत सिंह जी की चुनौती इस व्यापक ग्रामीण समाज तक पहुँचने की थी। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत उन्हें इस काम का आधार देती थी, लेकिन बदलती जरूरतों के बीच संगठन को खड़ा करना उनके अपने दौर की जिम्मेदारी थी। नब्बे के दशक के आखिर तक राष्ट्रीय लोक दल एक अलग चुनावी पहचान के साथ सामने आ चुका था। 1999 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बागपत और कैराना की सीटें जीतीं। बागपत से चौधरी अजीत सिंह जी और कैराना से श्री अमीर आलम जी निर्वाचित हुए। इस शुरुआत में ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दो महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी की मौजूदगी दिखाई देती है। मुस्लिम नेतृत्व की भागीदारी भी उसके संसदीय प्रतिनिधित्व का हिस्सा थी। पार्टी की अपनी घोषणा में चौधरी चरण सिंह जी के विचारों और उद्देश्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प था। लेकिन किसी विचार को संगठन में बदलना रोज का काम होता है। गाँव में कार्यकर्ता चाहिए, कस्बे में लोगों की बात सुनने वाला नेतृत्व चाहिए और जिले में ऐसा संपर्क चाहिए जिसके जरिए स्थानीय परेशानी ऊपर तक पहुँच सके।

पार्टी के लिए पुराने संबंध शुरुआती सहारा बन सकते थे; उन्हें जीवित रखने के लिए नियमित काम जरूरी था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय लोक दल का सबसे महत्वपूर्ण आधार बना। बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में चौधरी चरण सिंह जी की राजनीतिक स्मृति और किसान आंदोलनों की परंपरा पहले से मौजूद थी। चौधरी अजीत सिंह जी की पहचान इसी पृष्ठभूमि में मजबूत हुई। यहाँ खेती का सवाल किसी एक मौसम तक सीमित नहीं रहता। गन्ने का भुगतान, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई का खर्च और मिलों से संबंध किसान परिवार के साल भर के जीवन को प्रभावित करते हैं। इन मुद्दों से जुड़ी राजनीति में जनता की कसौटी बहुत सीधी होती है। किसान देखता है कि उसकी परेशानी के समय कौन आया, किसने उसकी बात उठाई और किसके प्रयास से सुनवाई हुई। मंच का बड़ा भाषण अपनी जगह है, लेकिन रुका हुआ भुगतान और गलत आया बिजली का बिल भी राजनीतिक भरोसे को प्रभावित करते हैं। राष्ट्रीय लोक दल के सामने अपने किसान समर्थक परिचय को ऐसे ही रोजमर्रा के काम से मजबूत करने की जरूरत थी। संगठन का सामाजिक विस्तार भी उतना ही जरूरी था। जाट किसानों के बीच मजबूत आधार पार्टी की ताकत रहा, लेकिन उससे आगे बढ़ने के लिए दूसरे समुदायों की सक्रिय भागीदारी चाहिए थी। मुस्लिम किसान और स्थानीय नेता इस प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। श्री अमीर आलम जी और चौधरी कौकब हमीद जी जैसे नेताओं की भूमिका से स्पष्ट होता है कि इस धारा में मुस्लिम नेतृत्व की अपनी जगह थी। इन संबंधों को केवल मतदाताओं की संख्या में नहीं समेटा जा सकता; इनमें स्थानीय प्रभाव, पुराने परिचय और साझा राजनीतिक काम भी शामिल थे। चौधरी कौकब हमीद जी की सक्रियता हरित प्रदेश की मांग में भी दिखाई देती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का प्रश्न चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति का प्रमुख विषय बना। उनका तर्क था कि इतने बड़े प्रदेश में प्रशासन और जनता के बीच दूरी बढ़ जाती है तथा छोटे राज्यों में लोगों की जरूरतों पर अधिक ध्यान दिया जा सकता है। इस मांग के समर्थन में सभाओं, बैठकों और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों के जरिए राय बनाने की कोशिश हुई। हरित प्रदेश का मुद्दा पार्टी को खेती से आगे प्रशासन और क्षेत्रीय विकास के प्रश्नों से जोड़ता था। इसमें राजधानी से दूरी, सरकारी संस्थाओं तक पहुँच और स्थानीय जरूरतों की सुनवाई जैसी बातें थीं। हालांकि अलग राज्य नहीं बन सका और यह मांग पूरे क्षेत्र की सर्वसम्मत आवाज भी नहीं बनी।

फिर भी इससे चौधरी अजीत सिंह जी की उस राजनीतिक सोच का परिचय मिलता है जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश को प्रशासनिक रूप से अधिक अधिकार और अपनी प्राथमिकताएँ तय करने की गुंजाइश मिलनी चाहिए थी। राष्ट्रीय लोक दल ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, दोनों जगह गठबंधनों के माध्यम से अपनी भूमिका बढ़ाई। चौधरी अजीत सिंह जी का केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना और प्रदेश की सरकारों में पार्टी की भागीदारी उसके प्रभाव के महत्वपूर्ण पड़ाव थे। 2009 में पार्टी के पाँच सदस्य लोकसभा पहुँचे। एक सीमित क्षेत्र में मजबूत आधार रखने वाले दल के लिए यह उल्लेखनीय उपस्थिति थी। सत्ता में भागीदारी के साथ संगठन से अपेक्षाएँ भी बढ़ती हैं। कार्यकर्ता चाहता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो और जनता चाहती है कि सरकार तक पहुँच का लाभ उसकी समस्याएँ हल करने में मिले। मंत्री और विधायक मिलने के बाद पार्टी के सामने केवल अपनी बात उठाने की जिम्मेदारी नहीं रहती; उसे अपने काम का हिसाब भी देना पड़ता है। राष्ट्रीय लोक दल के विस्तार में यह पहलू भी शामिल था। गठबंधन ने अवसर दिए, लेकिन अलग पहचान बनाए रखना चुनौती बना रहा। जब कोई छोटा दल बड़ी पार्टी के साथ चुनाव लड़ता है तो उसे कुछ क्षेत्रों में सहयोग मिलता है, जबकि कुछ जगह अपने उम्मीदवार उतारने का अवसर छोड़ना पड़ता है। स्थानीय कार्यकर्ताओं की आकांक्षाएँ और केंद्रीय नेतृत्व की राजनीतिक जरूरतें हमेशा एक जैसी नहीं होतीं। चौधरी अजीत सिंह जी को इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ा। पार्टी के सामने एक और कठिनाई थी। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत राष्ट्रीय महत्व की थी, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल का प्रभाव मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रहा। किसी नेता के प्रति दूसरे प्रदेशों में सम्मान होना और वहाँ एक मजबूत पार्टी संगठन खड़ा होना अलग बातें हैं। संगठन के लिए स्थानीय नेतृत्व, लगातार मौजूदगी और उस क्षेत्र के अपने सवालियों से संबंध चाहिए। राष्ट्रीय लोक दल अपनी सबसे मजबूत जमीन से बाहर वैसी व्यापक पकड़ नहीं बना सका। इस सीमा का संबंध बदलते ग्रामीण समाज से भी था। किसान परिवारों की नई पीढ़ी की जरूरतों में खेती के साथ पढ़ाई, नौकरी और शहरों में काम के अवसर शामिल हो रहे थे। पुराने कार्यकर्ता जिस राजनीतिक अनुभव से पार्टी के साथ जुड़े थे, उनके बच्चों का अनुभव अलग था। केवल परिवार की पुरानी निष्ठा के आधार पर नई पीढ़ी का जुड़ाव सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। संगठन को उनसे उनकी जरूरतों की भाषा में बात करनी थी।

इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक संबंधों को पहुँची चोट ने पार्टी के सामने कठिन परिस्थिति पैदा की। 2013 की हिंसा के बाद जिस साझेदारी पर किसान राजनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा टिका था, उसमें गहरी दरार आई। यह नुकसान किसी एक दल तक सीमित नहीं था, लेकिन राष्ट्रीय लोक दल उससे विशेष रूप से प्रभावित हुआ। साझा आर्थिक मुद्दों के साथ अब सुरक्षा, न्याय और आपसी भरोसे का प्रश्न भी सामने था। बाद के किसान आंदोलन में फिर संवाद और सहयोग के अवसर बने। चौधरी अजीत सिंह जी तथा जयंत चौधरी जी किसानों के प्रश्नों पर सक्रिय रहे। फिर भी किसी आंदोलन में लोगों का साथ आना अपने आप स्थायी संगठन में नहीं बदल जाता। उस संबंध को आगे निभाना पड़ता है—गाँव में, कार्यकर्ताओं के बीच और लोगों की मुश्किल के समय।

राष्ट्रीय लोक दल के निर्माण में चौधरी अजीत सिंह जी का योगदान एक राजनीतिक मंच को बनाए रखने का था, जहाँ किसान, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रश्नों को प्रमुख स्थान मिला। उनकी कोशिशों में सफलता के दौर भी आए और संगठन की सीमाएं भी सामने आईं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जी की विरासत को अपने समय की राजनीति में स्थान देने का प्रयास किया। आगे जयंत चौधरी जी के सामने इसी संगठन को नई पीढ़ी और नई परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आई।

## अध्याय 12 – केंद्रीय मंत्री के रूप में चौधरी अजीत सिंह जी का कार्य और राजनीतिक भूमिका

चौधरी अजीत सिंह जी की पहचान किसान राजनीति से जुड़ी थी, लेकिन केंद्र सरकार में उनकी जिम्मेदारियां कई क्षेत्रों तक फैली हुई थीं। उन्होंने उद्योग, खाद्य, कृषि और नागरिक उड्डयन जैसे मंत्रालय संभाले। इन मंत्रालयों की समस्याएं और काम करने की परिस्थितियां अलग थीं। कहीं उत्पादन और निवेश का सवाल था, कहीं अनाज की उपलब्धता और किसान की आमदनी का, तो कहीं आर्थिक संकट से जूझ रही विमान सेवाओं को संभालने का। इन जिम्मेदारियों ने उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन के अलग-अलग पहलुओं से जोड़ा। इन मंत्रालयों में उनके निर्णय तत्कालीन सरकारों की व्यापक नीति का हिस्सा थे। संबंधित विभाग, राज्य सरकारें और मंत्रिमंडल भी उनमें शामिल थे। कहीं चौधरी अजीत सिंह जी ने पहल की, कहीं प्रस्ताव रखा और कहीं सामूहिक निर्णय को लागू करने का दायित्व संभाला। दिसंबर 1989 में वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में उद्योग मंत्री बने। उस समय देश की औद्योगिक व्यवस्था में सरकारी अनुमति, नियंत्रण और सार्वजनिक क्षेत्र की बड़ी भूमिका थी। किसी उद्योग के विस्तार का संबंध पूंजी के साथ सरकारी प्रक्रियाओं से भी होता था। तकनीकी शिक्षा और कंप्यूटर उद्योग में लंबे अनुभव के बाद इस मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलना उनके जीवन का महत्वपूर्ण पड़ाव था। नवंबर 1990 में सरकार के अंत के साथ उनका पहला केंद्रीय कार्यकाल समाप्त हो गया। इस सीमित अवधि में उन्हें देश भर के उद्योगों, कामगारों और निवेश से जुड़े प्रश्नों पर प्रशासनिक अनुभव मिला। इसके बाद फरवरी 1995 से मई 1996 तक उन्होंने श्री पी. वी. नरसिंह राव जी की सरकार में खाद्य मंत्री के रूप में काम किया। खाद्य मंत्रालय की जिम्मेदारी खेत और उपभोक्ता के बीच की पूरी व्यवस्था से जुड़ी होती है। किसान अपनी उपज का उचित मूल्य चाहता है, जबकि आम परिवार चाहता है कि उसकी जरूरत का अनाज पहुँच के भीतर रहे। खरीद, भंडारण और वितरण की व्यवस्था में किसी एक स्तर की कमजोरी का असर दूसरे स्तरों पर भी पड़ता है। चौधरी अजीत सिंह जी के लिए यह मंत्रालय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन सवालों के करीब था जिनसे उनकी राजनीति जुड़ी हुई थी। अनाज पैदा हो जाना अपने आप में पर्याप्त नहीं है। उसे खरीदने की व्यवस्था हो, सुरक्षित रखा जाए और जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाया जाए, तभी उत्पादन का पूरा सामाजिक लाभ मिलता है।

खाद्य मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारी इसी व्यवस्था के संचालन से संबंधित थी। जुलाई 2001 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में उन्हें कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। किसान परिवार की पृष्ठभूमि और किसान राजनीति से उनके संबंध के कारण इस नियुक्ति से स्वाभाविक रूप से अपेक्षाएं जुड़ीं। अब उन्हें कृषि से जुड़े प्रश्नों पर सरकार के भीतर सीधे काम करने का अवसर मिला था। उनके कृषि मंत्री रहते हुए 2002 का सूखा एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आया। वर्षा की कमी ने खेती को प्रभावित किया और कई राज्यों में राहत की जरूरत पड़ी। ऐसे समय किसान की परेशानी केवल कम पैदावार तक सीमित नहीं रहती। बीज और खाद पर हुआ खर्च फंस जाता है, मजदूरी के अवसर घटते हैं और अगली फसल के लिए रकम जुटाना कठिन हो जाता है। कर्ज की अदायगी और घर के खर्च का दबाव अलग बना रहता है। इस परिस्थिति में चौधरी अजीत सिंह जी ने सूखा प्रभावित राज्यों को सहायता देने के नियमों में ढील की जरूरत उठाई। उत्तर प्रदेश की स्थिति पर बोलते हुए उन्होंने कर्ज वसूली स्थगित करने और प्रभावित परिवारों के बच्चों की स्कूल फीस फिलहाल रोकने की बात भी कही। इससे उनके हस्तक्षेप का एक महत्वपूर्ण पक्ष सामने आता है। वे सूखे के असर को खेत के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति से जोड़कर देख रहे थे। उसी दौर में उन्होंने कृषि लागत एवं मूल्य आयोग से खरीफ फसलों के समर्थन मूल्य संबंधी सिफारिशों पर सूखे की परिस्थिति को ध्यान में रखकर दोबारा विचार करने को कहा। किसानों के लिए अतिरिक्त राहत और बोनस का प्रश्न भी चर्चा में था। यह सरकारी व्यवस्था के भीतर किसान की बढ़ी हुई कठिनाई को जगह दिलाने का प्रयास था। हालांकि किसी प्रस्ताव पर जोर देने और उसके पूरी तरह लागू हो जाने में अंतर रहता है, फिर भी ऐसे हस्तक्षेप से मंत्री की प्राथमिकताओं का पता चलता है।

उनके कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय बीज नीति, 2002 सामने आई। इसमें बेहतर किस्मों के विकास, गुणवत्ता वाले बीजों की समय पर उपलब्धता, बीज उत्पादन की सुविधाओं और गुणवत्ता की निगरानी जैसे विषय शामिल थे। बीज का सवाल किसान के लिए बहुत बुनियादी है। खराब बीज का नुकसान केवल उसकी कीमत भर नहीं होता; उससे जमीन की तैयारी, सिंचाई, खाद और पूरे मौसम की मेहनत प्रभावित हो सकती है। बीज नीति का अमल राज्य सरकारों, गुणवत्ता की निगरानी और स्थानीय आपूर्ति से जुड़ा था। बेहतर बीज का भरोसा किसान तक तभी पहुँच सकता था जब बिक्री और जांच की व्यवस्था भी ठीक चले।

इस कार्यकाल में सूखे की तत्काल राहत और खेती की लंबे समय की जरूरतों साथ मौजूद थीं। दिसंबर 2011 में वे डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। यह कृषि से अलग कार्यक्षेत्र था और इसकी अपनी कठिनाइयां थीं। विमान कंपनियों की आर्थिक स्थिति, ईंधन की लागत, हवाई अड्डों की सुविधाएं और यात्रियों की सुरक्षा मंत्रालय के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न थे। एयर इंडिया की वित्तीय हालत भी गंभीर चिंता का विषय थी। अप्रैल 2012 में सरकार ने एयर इंडिया के लिए आर्थिक पुनर्गठन और उसकी स्थिति सुधारने की योजना को मंजूरी दी। इसका उद्देश्य कंपनी को वित्तीय सहारा देते हुए उसके संचालन में सुधार लाना था। योजना में सहायता के साथ निर्धारित लक्ष्यों की शर्त भी जुड़ी थी। चौधरी अजीत सिंह जी ने संबंधित मंत्री के रूप में इस फैसले को सामने रखा और उसकी जिम्मेदारी संभाली। यह एक कठिन सरकारी निर्णय था। राष्ट्रीय विमान कंपनी को सहारा देने में सार्वजनिक धन लगना था, इसलिए उसके उपयोग और परिणाम पर सवाल उठना स्वाभाविक था। कंपनी की समस्याएं पहले से चली आ रही थीं और उनका समाधान भी एक घोषणा से संभव नहीं था। इस योजना को कंपनी को संकट से बाहर निकालने के प्रयास के रूप में देखा जाना चाहिए। इसकी मंजूरी को ही सभी समस्याओं के समाप्त हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उनके नागरिक उड्डयन मंत्री रहते हुए 2012 में विदेशी विमान कंपनियों को भारतीय विमान कंपनियों में निर्धारित शर्तों के अंतर्गत 49 प्रतिशत तक निवेश की अनुमति देने का फैसला हुआ। इस कदम के पीछे क्षेत्र में पूंजी और व्यावसायिक सहयोग बढ़ाने की अपेक्षा थी। आर्थिक दबाव का सामना कर रही विमान कंपनियों के लिए निवेश के नए रास्ते खोलना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में शामिल था। इसी दौर में भारतीय विमान कंपनियों को विमान ईंधन सीधे आयात करने की अनुमति देने जैसे कदम उठाए गए। चौधरी अजीत सिंह जी ने छोटे तथा दूरस्थ स्थानों तक हवाई संपर्क बढ़ाने, कम लागत वाले हवाई अड्डों और इस क्षेत्र में कौशल विकास की जरूरत पर भी जोर दिया। ये आगे के काम की प्राथमिकताएं थीं; इनके उल्लेख से सभी प्रस्ताव पूरे हो जाने का निष्कर्ष नहीं निकलता। नागरिक उड्डयन में उनकी भूमिका से उनके सार्वजनिक जीवन का विस्तार दिखाई देता है। किसान राजनीति से जुड़े नेता के रूप में उन्होंने ऐसे मंत्रालय का काम संभाला जिसका संबंध देश के व्यापार, पर्यटन, रोजगार और परिवहन से था।

उनके सामने जिम्मेदारी थी कि क्षेत्र की आर्थिक जरूरतों के साथ सुरक्षा और सार्वजनिक हित का ध्यान रखा जाए।

केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी यात्रा गठबंधन राजनीति से भी जुड़ी रही। उन्होंने अलग-अलग विचारधाराओं वाली सरकारों में काम किया। इससे राष्ट्रीय लोक दल को केंद्र में भागीदारी मिली और चौधरी अजीत सिंह जी को अपनी बात रखने के अवसर मिले। लेकिन सरकार में शामिल रहने का अर्थ सामूहिक फैसलों की जिम्मेदारी उठाना भी था। अपने समर्थकों की अपेक्षाओं और गठबंधन की सीमाओं के बीच उन्हें लगातार काम करना पड़ा। उनके मंत्रित्व का मूल्यांकन केवल इस आधार पर नहीं हो सकता कि वे कितनी सरकारों में शामिल रहे। सूखे के समय किसान की राहत का प्रश्न उठाना, बीज व्यवस्था से जुड़ी नीति के दौर में कृषि मंत्रालय संभालना और संकटग्रस्त विमानन क्षेत्र में आर्थिक फैसलों की जिम्मेदारी लेना उनके काम के अलग-अलग पहलू थे। इनसे एक ऐसे नेता की तस्वीर सामने आती है जिसकी राजनीतिक जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारियां पूरे देश से संबंधित थीं। इन राष्ट्रीय भूमिकाओं के बीच खेती और ग्रामीण समाज से उनका संबंध बना रहा। उनके समर्थकों की बड़ी संख्या ऐसे परिवारों से आती थी जिनके लिए गन्ने का भुगतान, खेती की लागत और रोजमर्रा की आमदनी सबसे जरूरी प्रश्न थे। दिल्ली में उनकी जिम्मेदारियां चाहे जिस मंत्रालय की रही हों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति की परीक्षा इन्हीं सवालोंने पर होती रही।

## अध्याय 13 — किसान, गन्ना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल के साथ किसान परिवार की कई उम्मीदें जुड़ी होती हैं। उसी की आमदनी से अगली बुआई का इंतजाम होता है, बच्चों की फीस जाती है, घर की मरम्मत होती है और पुराना कर्ज चुकाया जाता है। खेत में खड़ा गन्ना देखकर परिवार आने वाले खर्चों का हिसाब लगाता है। लेकिन फसल अच्छी होने और उसका पैसा हाथ में आने के बीच कभी-कभी इतना लंबा इंतजार होता है कि पूरा हिसाब बिगड़ जाता है। चौधरी अजीत सिंह जी की किसान राजनीति को इस इंतजार के बीच समझना चाहिए। उनके सामने ऐसे लोगों की समस्याएं थीं जो मेहनत करने और अपनी फसल बेच देने के बाद भी भुगतान के लिए परेशान रहते थे। किसान की शिकायत सीधी थी—जिस उपज को पैदा करने में उसने अपना पैसा, समय और श्रम लगाया, उसका दाम पाने के लिए उसे बार-बार आवाज क्यों उठानी पड़े? चौधरी चरण सिंह जी ने किसान को देश की आर्थिक व्यवस्था में सम्मान और उचित स्थान दिलाने का प्रश्न उठाया था। चौधरी अजीत सिंह जी के दौर में वही प्रश्न खेती की बढ़ती लागत, गन्ने के मूल्य, मिलों के बकाये और सरकारी फैसलों के रूप में सामने आता रहा। परिस्थितियाँ बदल रही थीं, लेकिन किसान की एक पुरानी परेशानी बनी हुई थी। अपनी उपज की कीमत तय करने और समय पर भुगतान पाने में उसकी भूमिका सीमित थी। गन्ने की खेती में किसान का संबंध चीनी मिल से बहुत गहरा हो जाता है। खेत तैयार करने से लेकर कटाई और ढुलाई तक खर्च होता है। फसल तैयार होने पर उसे आपूर्ति और पेराई की व्यवस्था से तालमेल बैठाना पड़ता है। उसके बाद भुगतान का प्रश्न आता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसान अकेला पक्ष नहीं होता, लेकिन देरी का बोझ सीधे उसके घर पर पड़ता है। मिल के खाते में दर्ज बकाया किसान के लिए किसी कागज पर लिखी रकम भर नहीं है। वह उसकी रुकी हुई कमाई है। घर का खर्च और अगली फसल की जरूरतें भुगतान आने तक रुक नहीं सकतीं। ऐसे में किसान को अपनी ही कमाई की प्रतीक्षा करते हुए उधार लेना पड़ सकता है। इस स्थिति की तकलीफ वही परिवार पूरी तरह समझता है जिसे पैसा मिलना बाकी हो, लेकिन ब्याज आज से चुकाना पड़े। इसीलिए गन्ने की राजनीति में दो मांगें हमेशा साथ रहती हैं—उचित दाम और समय पर भुगतान। केवल मूल्य बढ़ जाने से समस्या हल नहीं होती, यदि पैसा लंबे समय तक अटका रहे। इसी तरह समय पर मिलने वाला भुगतान भी पर्याप्त नहीं होगा, यदि उससे लागत और परिवार की जरूरतें पूरी न हों।

किसान के लिए दोनों बातें एक ही आर्थिक सवाल के हिस्से हैं। नवंबर 2009 का गन्ना आंदोलन चौधरी अजीत सिंह जी की भूमिका का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। केंद्र सरकार की नई गन्ना मूल्य व्यवस्था के विरोध में किसान सड़कों पर उतरे। विवाद में फसल के दाम के साथ यह प्रश्न भी शामिल था कि केंद्र द्वारा तय मूल्य से अधिक राज्य द्वारा घोषित मूल्य के अंतर का भुगतान कौन करेगा। आंदोलनकारियों को आशंका थी कि नई व्यवस्था से किसान के हित प्रभावित होंगे। राष्ट्रीय लोक दल ने इस विरोध में सक्रिय भूमिका निभाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हुए और 19 नवंबर को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली पहुँचे। इस आंदोलन में चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व वाली पार्टी के साथ चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की भारतीय किसान यूनियन और राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन भी शामिल थे। गन्ने का सवाल अलग-अलग संगठनों को एक मंच पर ले आया था। इस घटना में चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक कार्यशैली का एक पक्ष साफ दिखाई देता है। उन्होंने किसान की मांग को स्थानीय विरोध तक सीमित नहीं रहने दिया। संसद के भीतर और बाहर उस पर दबाव बना। कई विपक्षी दलों के नेता किसानों के समर्थन में आए। खेती से जुड़ा एक प्रश्न राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना और सरकार को उस पर तत्काल बातचीत करनी पड़ी। इसके बाद सरकार ने विवादित प्रावधान हटाने की घोषणा की। राज्य द्वारा अधिक गन्ना मूल्य घोषित किए जाने पर उसके भुगतान की जिम्मेदारी मिलों पर रखने का रास्ता सामने आया। चौधरी अजीत सिंह जी ने इस फैसले का स्वागत किया। यह किसानों के संयुक्त दबाव का महत्वपूर्ण परिणाम था। इसमें उनकी भूमिका प्रमुख थी, साथ ही दूसरे किसान संगठनों और आंदोलन में आए लोगों की मेहनत भी शामिल थी। इस सफलता का अर्थ यह नहीं था कि गन्ना किसानों की सभी परेशानियाँ समाप्त हो गईं। मूल्य और भुगतान के प्रश्न बाद में भी उठते रहे। फिर भी 2009 का आंदोलन बताता है कि संगठित किसान अपनी समस्या को सरकार की प्राथमिकता बना सकता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने उस अवसर पर किसान की नाराजगी को राजनीतिक बातचीत और सरकारी निर्णय तक पहुँचाने में भूमिका निभाई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेती का असर खेत के बाहर भी दिखाई देता है। किसान के पास पैसा आने पर कस्बे की दुकान, कृषि उपकरण की मरम्मत करने वाला कारीगर, ढुलाई का काम करने वाला व्यक्ति और कई छोटे कारोबार उससे जुड़ते हैं।

भुगतान में देरी का असर इन संबंधों पर भी पड़ता है। इसीलिए गन्ने का बकाया पूरे इलाके की आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करने वाला प्रश्न बन जाता है। लेकिन ग्रामीण समाज के भीतर सबकी स्थिति एक जैसी नहीं होती। बड़े किसान की परेशानी और छोटी जोत वाले किसान की परेशानी में अंतर हो सकता है। जिसके पास बचत या आमदनी का दूसरा साधन है, वह कुछ समय इंतजार कर सकता है। जिस परिवार की अगली बुआई पिछली फसल के भुगतान पर टिकी हो, उसके लिए वही देरी कहीं अधिक कठिन होती है। खेती से जुड़े मजदूरों की अपनी जरूरतें हैं। उनके लिए नियमित काम, उचित मजदूरी और समय पर मेहनताना जरूरी है। किसान को उसकी उपज का बेहतर दाम मिले, इसके साथ मजदूर की स्थिति पर भी ध्यान रहना चाहिए। किसान राजनीति तभी अधिक लोगों की आवाज बनती है जब वह जमीन के मालिक के साथ उन हाथों को भी जगह दे जो खेत में काम करते हैं। इस पूरे जीवन में महिलाओं की भूमिका भी अक्सर चर्चा से बाहर रह जाती है। खेत, पशुधन और घर की जिम्मेदारियों में उनका श्रम शामिल होता है। भुगतान रुकने पर घर का सीमित पैसा कैसे चलेगा, कौन-सा खर्च टाला जाएगा और किस जरूरत को पहले पूरा किया जाएगा—इन फैसलों का बोझ भी वे उठाती हैं। गन्ने के दाम की बहस के पीछे परिवार के भीतर चलने वाली यह खींचतान भी मौजूद रहती है। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति की जमीन ऐसे ही ग्रामीण समाज में थी। उनके लिए किसान का प्रश्न केवल मंत्रालय या संसद का विषय नहीं था। यही उनके समर्थकों के जीवन का मुख्य आधार था। इसलिए केंद्रीय मंत्री के रूप में उनकी जिम्मेदारियां बदलती रहीं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनसे जुड़ी अपेक्षाओं में खेती और गन्ने का स्थान बना रहा। इस इलाके की किसान राजनीति में हिंदू और मुस्लिम किसानों के साझा हित भी महत्वपूर्ण रहे हैं। सिंचाई की कमी, बिजली का खर्च या भुगतान में देरी अलग-अलग धर्मों के किसानों को प्रभावित कर सकती है। इन सवालों पर साथ काम करने की गुंजाइश रहती है। चौधरी अजीत सिंह जी के सामने इस आर्थिक साझेदारी को सामाजिक भरोसे के साथ बनाए रखने की जिम्मेदारी भी थी। हालांकि साझा परेशानी अपने आप स्थायी एकता पैदा नहीं करती। उसके लिए संपर्क, निष्पक्ष व्यवहार और मुश्किल समय में साथ खड़े होने का अनुभव चाहिए। जिस समाज में डर या अविश्वास बढ़ जाए, वहाँ केवल फसल का सवाल उठाकर पुराने संबंध तुरंत नहीं लौटाए जा सकते। किसान की आमदनी और उसकी सुरक्षा, दोनों उसके जीवन के वास्तविक प्रश्न हैं।

समय के साथ किसान परिवारों की नई पीढ़ी की इच्छाएं भी बदल रही थीं। वे खेती के साथ अच्छी पढ़ाई, नौकरी और दूसरे कामों के अवसर चाहते थे। उनके लिए गाँव से संबंध बनाए रखना और बाहर की दुनिया में जगह बनाना साथ-साथ चलने वाली जरूरतें थीं। इससे किसान राजनीति के सामने शिक्षा, रोजगार और ग्रामीण उद्योग जैसे विषयों को अधिक महत्व देने की चुनौती आई। चौधरी अजीत सिंह जी का अपना जीवन इस बदलाव से अनजान नहीं था। वे तकनीकी शिक्षा और लंबे पेशेवर अनुभव के बाद राजनीति में आए थे। उनके सामने किसान की मौजूदा परेशानी के साथ उसके बच्चों के भविष्य का प्रश्न भी था। खेती को सहारा देना जरूरी था, और ग्रामीण परिवारों के लिए आमदनी के दूसरे रास्ते खुलना भी उतना ही महत्वपूर्ण था।

उनकी किसान राजनीति में उपलब्धियाँ भी थीं और अधूरे काम भी। उन्होंने गन्ने के प्रश्न पर लोगों को संगठित किया, सरकार पर दबाव बनाया और राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मांग रखी। इसके बावजूद भुगतान की देरी, लागत और आय की अनिश्चितता जैसी परेशानियाँ बनी रहीं। यही उस क्षेत्र की कठिनाई भी थी जिसमें वे काम कर रहे थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चौधरी अजीत सिंह जी का स्थान समझने के लिए इन दोनों बातों को साथ रखना होगा। वे किसानों की हर समस्या का समाधान नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने उनकी मांगों को राजनीतिक आवाज देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गन्ने का मूल्य और भुगतान उनके लिए ऐसे विषय थे जिनसे हजारों परिवारों का रोज का जीवन जुड़ा था। इसी संबंध ने उनकी राजनीति को खेत, गाँव और कस्बे से जोड़े रखा।

## अध्याय 14 — चौधरी अजीत सिंह जी और मुस्लिम समाज

चौधरी अजीत सिंह जी और मुस्लिम समाज के संबंध की जड़ें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सामाजिक जीवन और किसान राजनीति में थीं। उन्हें चौधरी चरण सिंह जी से ऐसे राजनीतिक संबंध विरासत में मिले थे जिनमें अलग-अलग समुदायों के लोग शामिल थे। इन संबंधों के पीछे खेती के साझा सवाल, पुराने कार्यकर्ताओं की मेहनत और नेतृत्व के प्रति विश्वास था। लेकिन समय बदलने के साथ इन्हें निभाने की परिस्थितियां भी बदल गईं। चौधरी अजीत सिंह जी को पुराने अपनत्व के साथ नई पीढ़ी की अपेक्षाओं और नई राजनीतिक दूरियों का सामना करना पड़ा। मुस्लिम समाज को एक ही तरह की जरूरतों वाला समूह मानकर इस संबंध को समझना कठिन होगा। जमीन का मालिक किसान, खेत में मजदूरी करने वाला व्यक्ति, कस्बे का दुकानदार और पढ़ाई पूरी करके नौकरी तलाशता युवक अपने-अपने अनुभव लेकर राजनीति को देखते हैं। उनके बीच धर्म का संबंध है, लेकिन आर्थिक स्थिति और सामाजिक पहुँच में अंतर भी है। चौधरी अजीत सिंह जी की किसान राजनीति से इन वर्गों का जुड़ाव इसलिए अलग-अलग आधारों पर बना। मुस्लिम किसान के लिए गन्ने का भुगतान, बिजली, सिंचाई और खेती की लागत उतने ही जरूरी प्रश्न थे जितने दूसरे किसानों के लिए। इन मुद्दों ने साझा राजनीतिक काम की गुंजाइश दी। जब मिल में भुगतान अटकता था या फसल का मूल्य विवाद का विषय बनता था, तब किसान की आर्थिक स्थिति उसके सामने होती थी। राष्ट्रीय लोक दल की किसान संबंधी सक्रियता को इसी धरातल पर मुस्लिम किसानों के बीच जगह मिली। लेकिन खेती से जुड़े प्रश्न मुस्लिम समाज की पूरी जरूरतों को समेट नहीं सकते थे। सुरक्षा, प्रशासन का व्यवहार, शिक्षा और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की अपनी अहमियत थी। रोजी-रोटी की चिंता के साथ यह भरोसा भी जरूरी था कि परेशानी आने पर उसकी बात सुनी जाएगी। इसीलिए किसी किसान नेता के साथ मुस्लिम समाज का संबंध केवल कृषि संबंधी मांगों से नहीं आंका जा सकता। उसके सार्वजनिक रुख और संकट के समय उसकी मौजूदगी का भी महत्व होता है। चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में मुस्लिम नेताओं को राजनीतिक संगठन और जनप्रतिनिधित्व में स्थान मिला। 1999 में राष्ट्रीय लोक दल के टिकट पर कैराना से श्री अमीर आलम जी का लोकसभा पहुँचना इसका एक स्पष्ट उदाहरण था। उसी चुनाव में बागपत से चौधरी अजीत सिंह जी निर्वाचित हुए थे।

पार्टी की संसदीय मौजूदगी में शुरुआत से मुस्लिम नेतृत्व की भागीदारी दिखाई देती है। श्री अमीर आलम जी की जीत को केवल चौधरी अजीत सिंह जी द्वारा अवसर देने की घटना मानना भी अधूरा होगा। किसी उम्मीदवार के पीछे उसके अपने सामाजिक संबंध, स्थानीय काम और समर्थकों की मेहनत होती है। पार्टी और स्थानीय नेतृत्व मिलकर जनाधार बनाते हैं। इस संबंध में दोनों की भूमिका स्वीकार करने से ही राजनीतिक साझेदारी का सही अर्थ सामने आता है। चौधरी कौकब हमीद जी की भूमिका भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण थी। वे उस राजनीतिक धारा के सक्रिय नेताओं में शामिल थे जो चौधरी अजीत सिंह जी के साथ आगे बढ़ी। हरित प्रदेश की मांग में उनकी भागीदारी उल्लेखनीय रही। वर्ष 2000 में उन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रदेश के विभाजन का प्रस्ताव रखा, जिसमें हरित प्रदेश का प्रश्न भी शामिल था। इससे स्पष्ट होता है कि मुस्लिम नेतृत्व की भूमिका केवल समुदाय से जुड़े विषयों तक सीमित नहीं थी। वह प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और क्षेत्रीय विकास के सवाल में भी भागीदार था। इस भूमिका में मुस्लिम नेतृत्व का सार्वजनिक दायरा साफ दिखाई देता है। खेती, प्रशासन और पूरे क्षेत्र का विकास उसके भी विषय थे। चौधरी अजीत सिंह जी के साथ जुड़े नेताओं की भागीदारी को केवल समुदाय से मत जुटाने तक सीमित करने से उनके काम का बड़ा हिस्सा छूट जाएगा। राष्ट्रीय लोक दल की राजनीति में इस सहयोग की संभावनाएं थीं, लेकिन उसकी सीमाएं भी थीं। कुछ प्रभावशाली नेताओं की मौजूदगी से पूरे समुदाय के हर वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो जाती। गाँव का भूमिहीन परिवार और कस्बे का छोटा कारीगर संगठन तक अपनी बात कैसे पहुँचाता है, यह अलग प्रश्न है। प्रतिनिधित्व की गहराई इस बात से भी तय होती है कि कम प्रभावशाली लोगों के लिए नेतृत्व तक पहुँचने के कितने रास्ते खुले हैं। चौधरी अजीत सिंह जी की गठबंधन राजनीति ने मुस्लिम समाज के साथ उनके संबंध को कई बार कठिन सवालों के सामने रखा। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार में भी काम किया और कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार में भी। अलग-अलग दलों के साथ सहयोग उनके राजनीतिक जीवन का हिस्सा था। ऐसे फैसलों को समर्थक अपनी अपेक्षाओं और अनुभवों के आधार पर देखते थे। किसी को सत्ता में भागीदारी से काम होने की उम्मीद होती थी, तो किसी के मन में सहयोगी दल की राजनीति को लेकर चिंता हो सकती थी। इन परिस्थितियों में नेतृत्व और समर्थकों के बीच बातचीत का महत्व बढ़ जाता है।

चुनावी समझौते का हिसाब कुछ सीटों और पदों से लगाया जा सकता है, लेकिन सामाजिक भरोसे का हिसाब उतना सीधा नहीं होता। लंबे समय से साथ खड़ा व्यक्ति यह भी जानना चाहता है कि नए राजनीतिक संबंध में उसकी चिंता का क्या स्थान रहेगा। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति के सामने यह प्रश्न बार-बार आया।

2013 की मुजफ्फरनगर और आसपास की हिंसा ने इन संबंधों को गंभीर चोट पहुँचाई। जिन गाँवों में लोग एक-दूसरे के परिचित थे, वहाँ भय और दूरी ने जगह बना ली। घर छोड़ने वाले परिवारों के सामने सुरक्षा के साथ रोजी-रोटी और बच्चों के भविष्य की चिंता थी। ऐसी परिस्थिति में किसान एकता की पुरानी स्मृति का अपना महत्व था, लेकिन उससे तत्काल सब कुछ ठीक नहीं हो सकता था। चौधरी अजीत सिंह जी और राष्ट्रीय लोक दल के लिए यह राजनीतिक तथा सामाजिक, दोनों स्तरों पर कठिन दौर था। जिस साझा ग्रामीण आधार से पार्टी को ताकत मिलती थी, उसी में दराar आई थी। इस नुकसान को केवल चुनाव में मिली हार तक सीमित करना उचित नहीं होगा। उसका बड़ा हिस्सा लोगों के आपसी संबंधों और भरोसे में था। उसे लौटाने के लिए पीड़ितों की बात सुनना और उनकी असुरक्षा को समझना आवश्यक था। बाद के किसान आंदोलन में पुराने संबंधों को फिर से जोड़ने के अवसर बने। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी के लंबे समय के सहयोगी श्री गुलाम मोहम्मद जौला जी इस प्रयास में महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। 2013 के बाद वे भारतीय किसान यूनियन से अलग हो गए थे। उनके अनुभव में पुराने सहयोग की स्मृति भी थी और संबंध टूटने की तकलीफ भी। 2021 में श्री गुलाम मोहम्मद जौला जी ने बताया कि चौधरी अजीत सिंह जी ने उनसे हिंदू-मुस्लिम सहयोग को मजबूत करने की बात की थी। किसान आंदोलन के दौरान जौला जी और टिकैत परिवार के बीच फिर संपर्क बना और वे महापंचायत में साथ आए। यह टूटे संवाद को दोबारा शुरू करने का महत्वपूर्ण अवसर था। हालांकि मंच पर साथ आने और गाँव के हर प्रभावित परिवार का भरोसा लौटने के बीच लंबा रास्ता बाकी था। चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन के अंतिम दौर में यह प्रयास उनके सामने मौजूद जिम्मेदारी को स्पष्ट करता है। किसान राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक संबंधों की देखभाल भी जरूरी थी। साझा आर्थिक मांग तभी अधिक मजबूत हो सकती थी जब उसके साथ खड़े लोगों को एक-दूसरे पर भरोसा हो।

मुस्लिम समाज के साथ उनके संबंध में अपनत्व, प्रतिनिधित्व, उम्मीद और शिकायत—सभी के लिए जगह थी। उनके साथ जुड़े लोगों को अपनी भूमिका मिली, लेकिन समाज के भीतर मौजूद हर आर्थिक और सामाजिक कठिनाई का समाधान नहीं हुआ। उनके राजनीतिक फैसलों पर सहमति भी रही और सवाल भी उठे। यही किसी लंबे लोकतांत्रिक संबंध की वास्तविकता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने किसान राजनीति के भीतर मुस्लिम समाज के लिए एक राजनीतिक स्थान बनाए रखने में भूमिका निभाई। यह संबंध उनके पिता की विरासत से शुरू हुआ, उनके अपने सहयोगियों और फैसलों से आगे बढ़ा और बदलती परिस्थितियों में कई बार परखा गया। आगे जयंत चौधरी जी के सामने जो विरासत आई, उसमें पार्टी और नेतृत्व के साथ यह भरोसा भी शामिल था—और जहाँ भरोसा कमजोर पड़ा था, वहाँ उसे दोबारा अर्जित करने की जिम्मेदारी भी।

## अध्याय 15 — गठबंधन राजनीति, सफलताएँ और चुनौतियाँ

चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक यात्रा में गठबंधनों का बड़ा स्थान रहा। वे अलग-अलग दलों के साथ आए, सरकारों में शामिल हुए और मतभेद होने पर अलग रास्ते पर भी चले। उनके इन फैसलों को लेकर समर्थकों और आलोचकों की राय अक्सर अलग रही। समर्थक मानते थे कि सीमित संसदीय ताकत के बावजूद वे अपने क्षेत्र और पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति में जगह बनाते हैं। आलोचक बदलते साथियों को उनकी राजनीतिक अस्थिरता से जोड़ते थे। उनके लंबे सार्वजनिक जीवन को समझने के लिए इन दोनों नजरियों के पीछे की परिस्थितियों को देखना जरूरी है। चौधरी अजीत सिंह जी की सबसे मजबूत राजनीतिक जमीन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थी। इस क्षेत्र के बाहर भी उनका परिचय और सम्मान था, लेकिन उनकी पार्टी की चुनावी ताकत पूरे देश में समान रूप से नहीं फैली थी। राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बनाए रखने के लिए उन्हें दूसरे दलों के सहयोग की जरूरत पड़ती थी। यही स्थिति अनेक क्षेत्रीय दलों के सामने रही है। अपने क्षेत्र में मजबूत समर्थन होने के बावजूद वे अकेले केंद्र की सरकार नहीं बना सकते। ऐसे में गठबंधन उनके लिए सत्ता और निर्णय की प्रक्रिया तक पहुँचने का रास्ता बनता है। लेकिन इस रास्ते की अपनी कठिनाइयाँ होती हैं। सहयोगी दलों की प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। चुनाव में सीटों का बंटवारा करना पड़ता है और सरकार में सामूहिक फैसलों की जिम्मेदारी उठानी होती है। कभी अपने कार्यकर्ता को समझाना पड़ता है कि जिस दल का कल तक विरोध किया जा रहा था, आज उसके साथ चुनाव क्यों लड़ा जाएगा। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति इन सवालों से बार-बार गुजरी। उनके शुरुआती राष्ट्रीय राजनीतिक दौर में जनता दल का महत्वपूर्ण स्थान था। 1989 में वे लोकसभा पहुँचे और श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में उद्योग मंत्री बने। इससे उन्हें केंद्रीय प्रशासन में काम करने का अवसर मिला। उस समय उनका राजनीतिक जीवन संगठन के नेतृत्व से आगे बढ़कर राष्ट्रीय सरकार की जिम्मेदारी तक पहुँच चुका था। यह सरकार लंबी नहीं चली। नवंबर 1990 में उसके समाप्त होने के साथ उनका उद्योग मंत्री का कार्यकाल भी समाप्त हुआ। इस अनुभव में गठबंधन की एक बुनियादी सीमा दिखाई देती है। किसी मंत्री की योजनाएं और काम सरकार के बने रहने पर भी निर्भर करते हैं। राजनीतिक समर्थन हटने पर मंत्रालय का कार्यकाल अचानक समाप्त हो सकता है।

चौधरी अजीत सिंह जी को अपने पहले ही केंद्रीय कार्यकाल में इस अस्थिरता का सामना करना पड़ा। बाद में वे कांग्रेस के साथ आए और श्री पी. वी. नरसिंह राव जी की सरकार में खाद्य मंत्री बने। 1996 का लोकसभा चुनाव उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर जीता, लेकिन उसी वर्ष कांग्रेस से अलग होकर भारतीय किसान कामगार पार्टी बनाई। 1997 में बागपत के उपचुनाव में वे इस नए दल के उम्मीदवार के रूप में फिर निर्वाचित हुए। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का महत्वपूर्ण मोड़ था। एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टी के भीतर काम करने के बाद उन्होंने अपना अलग संगठन खड़ा करने का रास्ता चुना। अलग दल होने से उन्हें अपनी प्राथमिकताएं तय करने की स्वतंत्रता मिली, लेकिन संगठन, उम्मीदवार और संसाधन जुटाने की जिम्मेदारी भी बढ़ी। राष्ट्रीय लोक दल तक पहुँचने वाली उनकी यात्रा को इसी पृष्ठभूमि में समझा जा सकता है।

जुलाई 2001 में वे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली सरकार में कृषि मंत्री बने और मई 2003 तक इस पद पर रहे। किसान राजनीति से जुड़े नेता के लिए कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी विशेष महत्व रखती थी। उन्हें सरकार के भीतर उन विषयों पर काम करने का अवसर मिला जिनसे उनके समर्थकों का जीवन सीधे जुड़ा था। इस कार्यकाल में सूखे जैसी गंभीर चुनौती भी सामने आई। उनका इस सरकार में शामिल होना बताता है कि उन्होंने राजनीतिक सहयोग के दरवाजे अलग-अलग दलों के लिए खुले रखे। यही उनके पक्ष और विपक्ष में कही जाने वाली बातों का आधार भी बना। एक ओर इसे क्षेत्रीय दल के लिए अवसर तलाशने की क्षमता माना गया। दूसरी ओर यह प्रश्न उठता रहा कि बदलते गठबंधनों के बीच पार्टी की अपनी वैचारिक पहचान कितनी स्पष्ट रहती है।

दिसंबर 2011 में वे कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बने। इस प्रकार उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक-दूसरे की प्रतिस्पर्धी राजनीतिक धाराओं के साथ काम किया। उनके लिए केंद्र की राजनीति में भागीदारी के रास्ते बने रहे। लेकिन हर नई भागीदारी के साथ पुराने समर्थकों को अपने फैसले का अर्थ समझाने की जरूरत भी बनी रही। किसी गठबंधन की सफलता का पहला प्रमाण अक्सर मंत्री पद या जीती हुई सीटों में दिखाई देता है। मगर उसकी पूरी कीमत और उपयोगिता इतनी भर नहीं होती।

यह भी देखना पड़ता है कि उससे पार्टी का संगठन कितना मजबूत हुआ, नए क्षेत्रों में कितनी जगह बनी और जनता की किन समस्याओं पर काम आगे बढ़ा। चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन में सत्ता तक पहुँचने की क्षमता स्पष्ट थी। उस पहुँच को स्थायी संगठनात्मक विस्तार में बदलना अधिक कठिन साबित हुआ। 2009 में राष्ट्रीय लोक दल के पाँच सदस्य लोकसभा पहुँचे। सीमित क्षेत्रीय आधार वाले दल के लिए यह महत्वपूर्ण संसदीय उपस्थिति थी। लेकिन इसके बाद का दौर उतना अनुकूल नहीं रहा। 2014 में चौधरी अजीत सिंह जी बागपत से चुनाव हार गए। 2019 में उन्होंने मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ा, जहाँ भी उन्हें पराजय मिली। राष्ट्रीय राजनीति का लंबा अनुभव और पुराने सामाजिक संबंध इन कठिनाइयों को रोक नहीं सके। इन पराजयों का कारण किसी एक गठबंधन या एक फैसले में तलाशना जल्दबाजी होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सामाजिक वातावरण बदल चुका था। दूसरे दलों का संगठन मजबूत हुआ था और मतदाताओं की प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया था। 2013 की हिंसा से सामाजिक संबंधों को पहुँची चोट ने किसान राजनीति के साझा आधार को प्रभावित किया। चौधरी अजीत सिंह जी को ऐसे समय में काम करना पड़ा जब पुराने राजनीतिक समीकरण पहले की तरह भरोसेमंद नहीं रहे थे। गठबंधन ऊपर के स्तर पर तय हो सकता है, लेकिन उसे जमीन पर निभाने वाले कार्यकर्ता होते हैं। वर्षों से किसी दल के विरुद्ध काम कर रहा स्थानीय कार्यकर्ता अचानक उसी दल के उम्मीदवार के लिए कितनी सहजता से काम करेगा, यह केवल घोषणा से तय नहीं होता। इसी तरह दो दलों के नेतृत्व के साथ आ जाने से उनके सभी मतदाता एक दिशा में वोट देंगे, इसकी गारंटी नहीं होती। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति के उतार-चढ़ाव इस अंतर को भी सामने लाते हैं। उनकी पार्टी के लिए सामाजिक विविधता बनाए रखना एक और जिम्मेदारी थी। जाट किसानों के बीच आधार के साथ मुस्लिम नेताओं और दूसरे समुदायों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण थी। किसी नए सहयोगी को चुनते समय इन समूहों की अपेक्षाएं एक जैसी नहीं हो सकती थीं। एक समूह सत्ता में हिस्सेदारी की संभावना देख सकता था, जबकि दूसरा अपनी सुरक्षा या प्रतिनिधित्व को लेकर सवाल कर सकता था। नेतृत्व को इन दोनों की बात सुननी पड़ती थी। ऐसी परिस्थितियों में साफ बातचीत का महत्व बढ़ जाता है। समर्थक केवल चुनावी लाभ का हिसाब नहीं चाहता। वह यह भी समझना चाहता है कि नए समझौते में उसके मुद्दों का क्या होगा। किसान पूछता है कि भुगतान और लागत की समस्या पर क्या काम होगा।

युवा रोजगार और शिक्षा की बात सुनना चाहता है। अल्पसंख्यक परिवार अपने सम्मान और सुरक्षा के बारे में भरोसा चाहता है। गठबंधन तभी लंबे समय तक उपयोगी बन सकता है जब इन अपेक्षाओं से उसका संबंध बना रहे।

चौधरी अजीत सिंह जी ने कई अवसरों पर अपनी सीमित संसदीय ताकत से अधिक राजनीतिक महत्व हासिल किया। उन्होंने केंद्र में महत्वपूर्ण मंत्रालय संभाले और राष्ट्रीय लोक दल को बड़े दलों के बीच बातचीत की जगह दिलाई। यह उनके राजनीतिक अनुभव और संबंधों की एक उपलब्धि थी। साथ ही उनकी पार्टी अपने सबसे मजबूत क्षेत्र से बाहर व्यापक और टिकाऊ विस्तार नहीं कर सकी। सत्ता में भागीदारी और संगठन की मजबूती के बीच यह दूरी उनके राजनीतिक जीवन की प्रमुख चुनौती रही। गठबंधनों ने राष्ट्रीय राजनीति में काम करने के अवसर दिए, लेकिन बदलते सहयोगियों के बीच पार्टी की पहचान और सामाजिक भरोसा दबाव में भी आए। चौधरी अजीत सिंह जी की यात्रा इन दोनों अनुभवों को साथ छोड़ती है। जयंत चौधरी जी को आगे जो संगठन मिला, उसके पीछे गठबंधन की यह लंबी यात्रा भी थी। उसमें राष्ट्रीय राजनीति तक पहुँच बनाने का अनुभव था और यह सीख भी कि नेतृत्व के स्तर पर बना समझौता तभी मजबूत रहता है जब गाँव और कस्बे का कार्यकर्ता उसका कारण समझ सके। चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत में सत्ता के रास्ते खोजने की क्षमता के साथ जनता का भरोसा बनाए रखने की यह अधूरी जिम्मेदारी भी शामिल थी।

## अध्याय 16 — चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक विरासत

चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद राष्ट्रीय लोक दल के सामने नेतृत्व का प्रश्न था, लेकिन उनकी विरासत इससे कहीं बड़ी थी। उसमें चौधरी चरण सिंह जी से चले आ रहे राजनीतिक संबंध थे, किसानों के बीच वर्षों का काम था और ऐसे कार्यकर्ताओं की उम्मीदें थीं जिन्होंने अच्छे और कठिन, दोनों दौर में पार्टी का साथ दिया था। जयंत चौधरी जी को इन सबके बीच आगे बढ़ना था। चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने पिता की विरासत ऐसे समय में संभाली थी जब उनके साथ काम कर चुके नेताओं के रास्ते अलग हो रहे थे। किसान राजनीति के पुराने संगठन में मतभेद थे और नेतृत्व के कई दावेदार थे। उनके सामने पहले से तैयार, एकजुट व्यवस्था नहीं थी। उन्हें अपने समर्थकों को संगठित करना पड़ा और बदलते राजनीतिक संबंधों के बीच अपनी जगह बनानी पड़ी। इस प्रयास का एक स्थायी रूप राष्ट्रीय लोक दल के रूप में सामने आया। राष्ट्रीय लोक दल का बने रहना उनकी विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। किसी बड़े नेता के निधन के बाद उससे जुड़ा राजनीतिक समूह बिखर भी सकता है। चौधरी अजीत सिंह जी ने संगठन बनाया, चुनाव लड़े, सरकारों में भागीदारी की और कार्यकर्ताओं के लिए एक राजनीतिक मंच बनाए रखा। इस मंच ने चौधरी चरण सिंह जी की किसान संबंधी विचारधारा को बाद के वर्षों की बहस में मौजूद रखा। हालांकि संगठन का अस्तित्व और उसका लगातार विस्तार अलग बातें हैं। राष्ट्रीय लोक दल की ताकत मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में केंद्रित रही। दूसरे क्षेत्रों में वह वैसी व्यापक पकड़ नहीं बना सका। चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत को समझते समय इस सीमा का भी महत्व है। उन्होंने जिस राजनीतिक आधार को बनाए रखा, उसे अधिक विस्तृत और मजबूत संगठन में बदलने का काम आगे की पीढ़ी के लिए बाकी रहा। उनका दूसरा महत्वपूर्ण योगदान किसान के प्रश्न को राष्ट्रीय राजनीति तक पहुँचाने में था। गन्ने का मूल्य, भुगतान में देरी और खेती की कठिनाइयां उनके सार्वजनिक जीवन से जुड़ी रहीं। नवंबर 2009 का गन्ना आंदोलन इसका स्पष्ट उदाहरण है। उस समय वे किसान संगठनों और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर सरकार पर दबाव बनाने में सक्रिय रहे। इससे पता चलता है कि उनका प्रभाव मंत्री पद तक सीमित नहीं था।

विपक्ष में रहते हुए भी वे किसी मुद्दे पर व्यापक सहयोग जुटा सकते थे। इस भूमिका में किसान की अपनी मेहनत और संगठन की शक्ति भी शामिल थी। किसी आंदोलन का पूरा श्रेय अकेले नेता को नहीं दिया जा सकता। किसान खेत और घर का काम छोड़कर आता है, कार्यकर्ता व्यवस्था संभालता है और स्थानीय नेतृत्व लोगों को जोड़ता है। चौधरी अजीत सिंह जी की भूमिका इन कोशिशों को राष्ट्रीय राजनीतिक स्तर पर आवाज देने की थी। उनके काम को इसी संबंध में देखने से उसका वास्तविक महत्व समझ में आता है। उनकी विरासत का एक और पक्ष उनकी शिक्षा और पेशेवर पृष्ठभूमि है। लंबे समय तक कंप्यूटर उद्योग में काम करने के बाद वे राजनीति में आए थे। ग्रामीण परिवार से निकले व्यक्ति का उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना और विदेश में पेशेवर जीवन बनाना उनकी अपनी उपलब्धि थी। बाद में उन्होंने सार्वजनिक जीवन अपनाया, लेकिन उनके अनुभव का वह हिस्सा भी उनके परिचय में बना रहा। उनका जीवन ग्रामीण युवाओं की बदलती आकांक्षाओं से भी जुड़ा है। किसान परिवार अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, उन्हें अच्छे अवसर देना चाहता है। परिवार का खेती से संबंध बना रहे, फिर भी बच्चे दूसरे क्षेत्रों में आगे बढ़ें—इन दोनों इच्छाओं में कोई विरोध आवश्यक नहीं है। चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन में गाँव की पृष्ठभूमि, आधुनिक शिक्षा और सार्वजनिक जिम्मेदारी साथ दिखाई देती हैं। केंद्रीय मंत्री के रूप में उनका काम भी इस विरासत का हिस्सा है। उन्होंने उद्योग, खाद्य, कृषि और नागरिक उड्डयन जैसे अलग-अलग मंत्रालय संभाले। कृषि मंत्री रहते हुए सूखे से प्रभावित किसानों की राहत का प्रश्न उठाया। नागरिक उड्डयन मंत्री के रूप में आर्थिक संकट और निवेश से जुड़े फैसलों की जिम्मेदारी निभाई। इन भूमिकाओं ने उनके सार्वजनिक जीवन को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आगे राष्ट्रीय प्रशासन से जोड़ा। इन मंत्रालयों का अनुभव उनके राजनीतिक परिचय का हिस्सा बना, लेकिन ग्रामीण जीवन की कई पुरानी कठिनाइयाँ बनी रहीं। सरकार में उनकी पहुँच और परिवारों के जीवन में अपेक्षित बदलाव के बीच का अंतर भी उनकी विरासत में दर्ज है। उनकी गठबंधन राजनीति ने राष्ट्रीय लोक दल को कई बार सत्ता में भागीदारी दिलाई। उन्होंने अलग-अलग राजनीतिक धाराओं के साथ काम किया और केंद्र की राजनीति में अपना स्थान बनाए रखा। यह उनकी राजनीतिक क्षमता का एक पक्ष था। लेकिन बदलते गठबंधनों ने समर्थकों के सामने सवाल भी रखे।

पार्टी की पहचान, उसके सामाजिक आधार और सहयोगी दलों की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाए रखना आसान नहीं रहा। आगे की पीढ़ी को इस अनुभव से दोनों बातें मिलीं। सहयोग से प्रभाव बढ़ सकता है, लेकिन उसके कारण और परिणाम कार्यकर्ताओं तथा समर्थकों को समझ आने चाहिए। केवल नेतृत्व का फैसला पर्याप्त नहीं होता। जिस व्यक्ति ने वर्षों तक किसी झंडे के नीचे काम किया हो, उसकी अपनी राजनीतिक समझ और भावनाएं होती हैं। उसे विश्वास में रखना संगठन के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।

चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत में मुस्लिम समाज के साथ राजनीतिक सहयोग का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनके संगठन में मुस्लिम नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया और क्षेत्रीय मुद्दों पर काम किया। किसान राजनीति का साझा आधार इन संबंधों को सहारा देता था। खेती, व्यापार और स्थानीय जीवन के प्रश्नों पर अलग-अलग समुदायों के साथ काम करने की गुंजाइश बनी रही। 2013 की हिंसा के बाद इन्हीं संबंधों को गहरी चोट पहुँची। इस दौर ने दिखाया कि वर्षों का राजनीतिक सहयोग भी सामाजिक अविश्वास के सामने कमजोर पड़ सकता है। बाद के किसान आंदोलन में फिर संपर्क और संवाद के अवसर बने। चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन के अंतिम दौर में हिंदू-मुस्लिम सहयोग को मजबूत करने की चिंता इसी अनुभव से जुड़ी थी। यह काम केवल चुनावी जरूरत नहीं था; किसान राजनीति के सामाजिक आधार का प्रश्न भी था। उनके बाद इस संबंध को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी जयंत चौधरी जी के सामने आई। पुराना सम्मान एक शुरुआती सहारा हो सकता है, लेकिन नई परिस्थितियों में भरोसा अपने व्यवहार से अर्जित करना पड़ता है। जिन परिवारों ने असुरक्षा या दूरी का अनुभव किया हो, उनके लिए राजनीतिक आश्वासन का अर्थ तभी बनता है जब उसे काम और लगातार संवाद का साथ मिले। चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत में कार्यकर्ताओं का स्थान भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बड़े राजनीतिक नामों के पीछे ऐसे लोग होते हैं जो अपने गाँव और कस्बे में वर्षों तक संबंध निभाते हैं। चुनाव हारने पर भी वे लोगों के बीच रहते हैं। पार्टी की कठिन घड़ी में उनका धैर्य संगठन को टूटने से बचाता है। राष्ट्रीय लोक दल के उतार-चढ़ाव में ऐसे कार्यकर्ताओं की भूमिका को परिवार के राजनीतिक इतिहास से अलग नहीं किया जा सकता। कठिन चुनावी दौर भी उनके जीवन की कहानी में शामिल है।

बागपत और बाद में मुजफ्फरनगर की पराजयों ने यह स्पष्ट किया कि पुराने संबंधों को लगातार नया आधार देना पड़ता है। नई पीढ़ी के मतदाता अपने अनुभव से निर्णय लेते हैं। उनके लिए किसी परिवार का इतिहास महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन वे शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा और भविष्य के अवसरों पर भी जवाब चाहते हैं। इसीलिए चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत को आगे बढ़ाने का अर्थ उनके समय की राजनीति को ज्यों का त्यों दोहराना नहीं हो सकता। उनके दौर से मिले संगठन, अनुभव और संबंधों को नई जरूरतों के अनुरूप काम में लाना होगा। किसान की आय के साथ उसके बच्चों की पढ़ाई, कौशल, रोजगार और छोटे कारोबार के प्रश्न भी सामने हैं। ग्रामीण जीवन बदल रहा है और उससे जुड़ी राजनीति को यह बदलाव समझना होगा।

चौधरी चरण सिंह जी ने किसान को देश की आर्थिक और राजनीतिक चर्चा के केंद्र में लाने का संघर्ष किया। चौधरी अजीत सिंह जी ने उस धारा को अपने समय में संगठन और प्रतिनिधित्व देने का प्रयास किया। उनकी राह में सफलता भी आई, आलोचना भी और पराजय भी। इसके बावजूद किसान तथा ग्रामीण समाज से जुड़ा उनका राजनीतिक परिचय बना रहा। जयंत चौधरी जी के सामने अब इसी इतिहास के साथ आगे बढ़ने का कार्य था। उन्हें अपने दादा और पिता का नाम मिला, लेकिन नई पीढ़ी की अपेक्षाओं का उत्तर अपने काम से देना था। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक विरासत का अगला अध्याय इसी जगह से शुरू होता है—जहाँ पुराने संबंधों के प्रति जिम्मेदारी और आने वाले समय की तैयारी एक साथ सामने खड़ी होती हैं।

## भाग 3 — जयंत चौधरी जी: नई पीढ़ी, नई भाषा

### अध्याय 17 — जयंत चौधरी जी: जीवन और राजनीतिक यात्रा

जयंत चौधरी जी के सार्वजनिक जीवन के साथ दो पीढ़ियों का इतिहास जुड़ा हुआ है। उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी ने किसान को देश की राजनीति में सम्मान और आवाज दिलाने के लिए लंबा संघर्ष किया। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी ने उस राजनीतिक धारा को संगठन और संसदीय प्रतिनिधित्व के माध्यम से आगे बढ़ाया। जयंत चौधरी जी इसी परिवार की तीसरी पीढ़ी के रूप में राजनीति में आए। उन्हें एक परिचित नाम मिला, लेकिन उस नाम से जुड़ी उम्मीदों का उत्तर अपने काम से देना था। उनका जन्म 27 दिसंबर 1978 को हुआ। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह जी थे और माता श्रीमती राधिका सिंह जी थीं। परिवार का संबंध पश्चिमी उत्तर प्रदेश से था, जबकि उनके पिता की शिक्षा और पेशेवर जीवन का एक लंबा हिस्सा विदेश में बीता था। जयंत चौधरी जी की अपनी शिक्षा भी भारत से आगे विदेश तक पहुँची। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्ययन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस से अकाउंटिंग और फाइनेंस में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि का संबंध अर्थव्यवस्था और वित्त से था। सार्वजनिक जीवन में आने के बाद उनके सामने इन्हीं विषयों के मानवीय पहलू भी थे। सरकारी खर्च, निवेश और आर्थिक विकास की चर्चा के पीछे लोगों के रोजमर्रा के सवाल होते हैं— पढ़ाई का खर्च कैसे निकलेगा, खेती से कितना बचेगा और नौकरी कहाँ मिलेगी। राजनीति में किसी विषय की जानकारी के साथ उन लोगों का अनुभव समझना भी जरूरी होता है जिनके जीवन पर फैसलों का असर पड़ता है। 14 अगस्त 2003 को उनका विवाह श्रीमती चारु सिंह जी से हुआ। इसके बाद के वर्षों में उनका सार्वजनिक जीवन धीरे-धीरे अधिक सक्रिय हुआ। चौधरी अजीत सिंह जी उस समय राष्ट्रीय राजनीति और राष्ट्रीय लोक दल के नेतृत्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। जयंत चौधरी जी ने पिता के जीवनकाल में ही चुनाव, जनसंपर्क और संसदीय काम का अनुभव प्राप्त करना शुरू कर दिया था। 2009 में वे मथुरा से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। यह उनकी राजनीतिक यात्रा का पहला बड़ा संसदीय पड़ाव था। अब उनकी भूमिका परिवार के राजनीतिक परिचय से आगे बढ़कर एक निर्वाचन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की थी।

जनता ने उन्हें अपनी समस्याएं संसद तक पहुँचाने और सरकार से जवाब मांगने की जिम्मेदारी दी थी। मथुरा का प्रतिनिधित्व करते हुए उनके सामने ग्रामीण और शहरी, दोनों तरह के प्रश्न थे। खेती और जमीन के साथ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पर्यावरण जैसे विषय भी महत्वपूर्ण थे। संसद में उनके प्रश्नों में कृषि मशीनीकरण, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन और यमुना की सफाई जैसे मुद्दे शामिल रहे। इससे उनके शुरुआती संसदीय काम का दायरा दिखाई देता है। यमुना से जुड़े प्रश्न मथुरा के लिए विशेष महत्व रखते हैं। नदी का संबंध वहाँ के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन से है, लेकिन उसके प्रदूषण का प्रश्न नागरिक सुविधाओं और पर्यावरण से भी जुड़ा है। इसी तरह प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी का विषय किसी एक विद्यालय तक सीमित नहीं रहता। वह बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से संबंधित होता है। ऐसे सवाल उठाना जनप्रतिनिधि के उस काम का हिस्सा है जिसमें स्थानीय अनुभव को व्यापक सरकारी जिम्मेदारी से जोड़ा जाता है। उनकी राजनीतिक यात्रा लगातार चुनावी सफलता की यात्रा नहीं रही। 2014 में वे मथुरा से चुनाव हार गए। 2019 में उन्होंने बागपत से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहाँ भी सफलता नहीं मिली। बागपत का उनके परिवार से पुराना राजनीतिक संबंध था, इसलिए यह हार विशेष महत्व रखती थी। इससे स्पष्ट हुआ कि विरासत के साथ चुनाव लड़ने वाला नेता भी बदलते जनमत से बाहर नहीं है। चुनाव हारने के बाद उनका काम संगठन और जनसंपर्क के बीच जारी रहा। राष्ट्रीय लोक दल अपनी राजनीतिक जगह बनाए रखने की चुनौती से जूझ रहा था और पार्टी में उनकी जिम्मेदारी बढ़ रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और सामाजिक संबंधों की बदलती स्थिति भी उनके सामने थी। यहाँ खेती से जुड़े सवालों के साथ समुदायों के बीच भरोसा बनाए रखना आवश्यक था। चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी से जुड़ी किसान राजनीति की स्मृति मौजूद थी, लेकिन नई पीढ़ी के मतदाताओं के अपने अनुभव और अपेक्षाएँ थीं। जयंत चौधरी जी को दोनों के बीच काम करना था। 2020-21 के किसान आंदोलन ने उनके सार्वजनिक जीवन को एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया। उन्होंने आंदोलन का समर्थन किया और किसानों के प्रश्नों को उठाया। उस समय कृषि कानूनों पर राष्ट्रीय बहस चल रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसानों की सभाओं और संपर्कों ने राजनीतिक गतिविधि को नई गति दी। राष्ट्रीय लोक दल के लिए यह अपने मूल जनाधार से संवाद का महत्वपूर्ण अवसर था।

इसी बीच 6 मई 2021 को चौधरी अजीत सिंह जी का निधन हो गया। जयंत चौधरी जी के लिए यह व्यक्तिगत शोक के साथ बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी का समय था। पिता की मौजूदगी में काम करने और उनके बाद पूरे संगठन का नेतृत्व संभालने की परिस्थितियां अलग होती हैं। अब कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं और पार्टी के भविष्य से जुड़े फैसले सीधे उनके सामने थे। 25 मई 2021 को राष्ट्रीय लोक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उन्हें पार्टी का अध्यक्ष चुना। यह जिम्मेदारी ऐसे समय मिली जब देश कोरोना महामारी से गुजर रहा था। अनेक परिवार बीमारी और शोक से प्रभावित थे। संगठन को आगे बढ़ाने के साथ जनता की इन परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील रहना भी आवश्यक था। पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद उनके सामने पुराने और नए नेतृत्व को साथ लेकर चलने का प्रश्न था। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के पास वर्षों का अनुभव था। युवा कार्यकर्ता अपनी भूमिका और अवसर चाहते थे। संगठन को दोनों की जरूरत थी। किसी पुराने राजनीतिक दल में नई पीढ़ी का नेतृत्व इसी तालमेल से मजबूत होता है। 2022 में जयंत चौधरी जी उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव में उन्हें समाजवादी पार्टी का समर्थन मिला। लोकसभा के बाद अब उन्हें संसद के उच्च सदन में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे राष्ट्रीय मुद्दों पर अपनी बात रखने और पार्टी की ओर से संसदीय भूमिका निभाने का एक नया रास्ता खुला। उनकी यात्रा का अगला बड़ा मोड़ 2024 में आया, जब राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल हुआ। यह उनके नेतृत्व में लिया गया महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला था। इससे पार्टी के संबंधों और आगे की भूमिका में बदलाव आया। इस निर्णय को लेकर समर्थन भी सामने आया और सवाल भी उठे। उनकी राजनीति को समझने में दोनों का स्थान है। गठबंधन बदलने का अर्थ केवल चुनावी साथी बदलना नहीं होता। उसके साथ कार्यकर्ताओं को नई परिस्थितियों में काम करना पड़ता है और समर्थक अपनी अपेक्षाओं के आधार पर फैसले को देखते हैं। जयंत चौधरी जी के सामने भी अपने निर्णय और उससे मिलने वाले अवसरों को जनता के भरोसे से जोड़ने की जिम्मेदारी थी। जून 2024 में उन्हें केंद्र सरकार में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मिला। इसके साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी भी दी गई। 11 जून को उन्होंने इन पदों का कार्यभार संभाला। उनके सार्वजनिक जीवन में यह एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अब वे सांसद और पार्टी अध्यक्ष के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में भी जिम्मेदार थे।

इन मंत्रालयों का संबंध ग्रामीण और शहरी युवाओं के भविष्य से है। पढ़ाई पूरी करने के बाद काम का अवसर, रोजगार के योग्य प्रशिक्षण और अपना छोटा कारोबार शुरू करने की तैयारी अनेक परिवारों की चिंता है। किसान परिवार का युवक हो या कस्बे के छोटे दुकानदार की बेटी, दोनों के लिए शिक्षा के बाद आगे बढ़ने का रास्ता मायने रखता है। जयंत चौधरी जी को ऐसे विषयों पर काम करने का अवसर मिला जिनका प्रभाव उनकी पार्टी के पारंपरिक क्षेत्र से बहुत आगे तक जा सकता है। मंत्री बनने पर उनके सामने योजनाओं के संचालन की सीधी जिम्मेदारी आई। प्रशिक्षण की गुणवत्ता, संस्थानों की पहुँच और पढ़ाई के बाद आजीविका से उसका संबंध अब उनके प्रशासनिक काम के विषय भी थे।

जयंत चौधरी जी की इस यात्रा में पारिवारिक विरासत के साथ आधुनिक शिक्षा, संसद का अनुभव, चुनावी पराजय और संगठन का नेतृत्व जुड़े। जून 2024 में मंत्री पद मिलने पर उसमें प्रशासनिक जिम्मेदारी का नया अध्याय शुरू हुआ। उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी से मिले संबंधों को आज की जरूरतों से कैसे जोड़ा जाए। किसान की आमदनी अब भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसी परिवार के बच्चे शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर भी चाहते हैं। पुराने समर्थक अपनत्व और भरोसा चाहते हैं, जबकि नई पीढ़ी अपने भविष्य का स्पष्ट रास्ता देखना चाहती है। जयंत चौधरी जी की आगे की राजनीति इन्हीं अपेक्षाओं के बीच अपना आकार लेती है।

## अध्याय 18 – दादा और पिता की विरासत से जयंत चौधरी जी का संबंध

जयंत चौधरी जी के नाम के साथ जब चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी का उल्लेख होता है, तो उसमें पारिवारिक परिचय से अधिक बातें शामिल होती हैं। किसान परिवारों की उम्मीदें, पुराने कार्यकर्ताओं के अनुभव और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक संबंध भी इस परिचय का हिस्सा हैं। कुछ लोगों ने उनके दादा के साथ काम किया था, कुछ उनके पिता के साथ जुड़े और कुछ जयंत चौधरी जी के दौर में पहली बार राष्ट्रीय लोक दल के करीब आए। इन अलग-अलग पीढ़ियों को साथ लेकर चलना उनकी जिम्मेदारी है। चौधरी चरण सिंह जी की विरासत का सबसे मजबूत आधार किसान के जीवन की उनकी समझ थी। वे खेती करने वाले व्यक्ति को देश की आर्थिक व्यवस्था में उचित स्थान दिलाना चाहते थे। उनकी चिंता थी कि विकास की प्राथमिकताएं तय करते समय गाँव और छोटे उत्पादक की जरूरतें पीछे न छूट जाएँ। किसान का प्रश्न उनके लिए फसल के दाम से आगे जमीन, कर्ज, उत्पादन और आर्थिक स्वतंत्रता तक जाता था। जयंत चौधरी जी का इस विचार से संबंध उनके परिवार के इतिहास के माध्यम से बना, लेकिन सार्वजनिक जीवन में उसे निभाने के लिए अपनी समझ और अपना काम जरूरी है। चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सम्मान रखने वाला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उनके पौत्र से भी उम्मीद करता है। वह देखना चाहता है कि किसान के सवाल आज की राजनीति में किस तरह उठाए जा रहे हैं और फैसलों में उनकी कितनी जगह है। यहीं विरासत एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। किसी परिवार का नाम लोगों को पहली बार सुनने के लिए तैयार कर सकता है। आगे का विश्वास व्यवहार से बनता है। कार्यकर्ता अपनी बात सुने जाने की उम्मीद करता है। किसान कठिन समय में साथ चाहता है। युवा अपने लिए अवसर देखना चाहता है। इन अपेक्षाओं का उत्तर केवल पुराने कामों को याद करके नहीं दिया जा सकता। चौधरी अजीत सिंह जी से मिली विरासत का स्वरूप कुछ अलग था। उन्होंने अपने पिता की राजनीतिक धारा को बदलते दलों, गठबंधनों और चुनावी परिस्थितियों के बीच आगे बढ़ाया। राष्ट्रीय लोक दल उनके प्रयासों का महत्वपूर्ण परिणाम था। जयंत चौधरी जी को इस संगठन में काम करने का अवसर पिता के जीवनकाल में ही मिल गया था।

उन्होंने चुनाव लड़ा और संसद पहुँचे। बाद में उन्हें पराजय का सामना भी करना पड़ा। इस तरह नेतृत्व की पूरी जिम्मेदारी आने से पहले वे राजनीति के कई अनुभवों से गुजर चुके थे। उनके पिता का जीवन उन्हें संगठन के महत्व से परिचित कराता है। किसी बड़े विचार को लोगों के बीच बनाए रखने के लिए कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेतृत्व की जरूरत होती है। गाँव में पार्टी की पहचान अक्सर उस व्यक्ति से बनती है जो परेशानी के समय उपलब्ध रहता है। शीर्ष नेतृत्व के भाषण के बाद लोगों से बातचीत वही करता है। चुनाव के बाद भी उसे उन्हीं लोगों के बीच रहना होता है। राष्ट्रीय लोक दल की विरासत में ऐसे संबंधों की बड़ी जगह है। जयंत चौधरी जी के लिए पुराने कार्यकर्ताओं का अनुभव उपयोगी है, लेकिन संगठन को नई पीढ़ी के लिए भी जगह बनानी है। युवा केवल सभा में भीड़ बढ़ाने के लिए नहीं जुड़ता। वह अपनी बात रखने, काम की जिम्मेदारी लेने और आगे बढ़ने का अवसर चाहता है। पुराने संबंधों को सम्मान देते हुए नए लोगों के लिए रास्ता खोलना नेतृत्व की कठिन, मगर जरूरी जिम्मेदारी है। चौधरी अजीत सिंह जी की तरह जयंत चौधरी जी ने भी विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की। पिता ने तकनीकी क्षेत्र में पढ़ाई और काम किया था, जबकि जयंत चौधरी जी की शिक्षा अकाउंटिंग और फाइनेंस में हुई। दोनों के जीवन में ग्रामीण पृष्ठभूमि और आधुनिक शिक्षा का संबंध दिखाई देता है। इससे यह समझने में मदद मिलती है कि किसान परिवार की अगली पीढ़ी की इच्छाएं कितनी व्यापक हो सकती हैं। गाँव का परिवार चाहता है कि उसकी खेती सुरक्षित रहे और बच्चे पढ़कर आगे भी बढ़ें। कोई नौकरी करना चाहता है, कोई अपना कारोबार और कोई खेती में ही बेहतर तरीके अपनाना चाहता है। इन इच्छाओं को किसान राजनीति से अलग नहीं रखा जा सकता। यदि खेती की कमाई से बच्चे की पढ़ाई चलती है, तो शिक्षा का प्रश्न भी उसी परिवार की आर्थिक स्थिति का हिस्सा है। यदि पढ़ाई के बाद रोजगार नहीं मिलता, तो उसका असर फिर घर और खेत पर लौटता है। जयंत चौधरी जी के सामने अपने दादा की ग्रामीण आर्थिक सोच को इन जरूरतों से जोड़ने का अवसर है। किसान की आमदनी, छोटे उत्पादक की सुरक्षा और ग्रामीण युवाओं के रोजगार के बीच गहरा संबंध है। कौशल विकास और शिक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियां मिलने के बाद यह संबंध उनके प्रशासनिक काम से भी जुड़ गया। अब प्रश्न यह है कि प्रशिक्षण और पढ़ाई के अवसर उन परिवारों तक कितनी सहजता से पहुँचते हैं जिनके पास जानकारी, पैसा या संस्थागत पहुँच कम है।

विरासत से संबंध का एक दूसरा पहलू सामाजिक है। चौधरी चरण सिंह जी की किसान राजनीति ने अलग-अलग समुदायों के बीच सहयोग की संभावना पैदा की थी। चौधरी अजीत सिंह जी के संगठन में भी विभिन्न समुदायों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की भूमिका रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम किसानों के संबंध इस इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। जयंत चौधरी जी को यह साझा आधार मिला, साथ ही समय के साथ उसमें पैदा हुई दूरियां भी मिलीं। इन संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पुराने अपनत्व को याद करना उपयोगी है, लेकिन जिन परिवारों ने डर या असुरक्षा का अनुभव किया हो, उनके अपने सवाल होते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी बात पूरी गंभीरता से सुनी जाए। सामाजिक भरोसा धीरे-धीरे बनता है। रोजमर्रा का व्यवहार, स्थानीय नेतृत्व का रुख और मुश्किल समय में साथ खड़े होने का अनुभव उसमें महत्व रखते हैं। इसी तरह ग्रामीण समाज के भीतर मौजूद आर्थिक अंतर भी ध्यान मांगते हैं। जमीन के मालिक किसान, छोटी जोत वाले परिवार और भूमिहीन मजदूर की स्थिति एक जैसी नहीं है। महिलाओं का श्रम और युवाओं की जरूरतें भी अलग से समझनी पड़ती हैं। किसान की साझा पहचान तभी अधिक व्यापक बन सकती है जब उसके भीतर इन अनुभवों के लिए जगह हो। जयंत चौधरी जी के सामने विरासत को अधिक लोगों की भागीदारी तक पहुँचाने का यह काम भी है। चौधरी अजीत सिंह जी के गठबंधनों से राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बनाने के अवसर मिले थे, लेकिन हर परिवर्तन के बाद समर्थकों से संवाद की जरूरत भी सामने आई। जयंत चौधरी जी के अपने राजनीतिक सहयोगों के सामने भी यह प्रश्न बना रहा। परिवार के पिछले फैसले किसी नए निर्णय का अपने आप उत्तर नहीं बन सकते। हर समय की परिस्थितियां अलग होती हैं। समर्थक जानना चाहते हैं कि आज के सहयोग से उनके मुद्दों पर क्या काम होगा और पार्टी अपनी पहचान कैसे बनाए रखेगी। यहाँ नेतृत्व को अपने फैसलों की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होती है। विरासत अनुभव देती है, लेकिन निर्णय और उसके परिणाम नए नेतृत्व के अपने होते हैं। 2024 में चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिलने का अवसर परिवार और उनके विचारों से जुड़े लोगों के लिए विशेष महत्व रखता था। राष्ट्रपति भवन में जयंत चौधरी जी ने अपने दादा की ओर से यह सम्मान प्राप्त किया। उस क्षण में तीन पीढ़ियों का संबंध एक साथ दिखाई देता था—सम्मान चौधरी चरण सिंह जी के जीवन और योगदान का था, और उसे प्राप्त करने के लिए उनके पौत्र उपस्थित थे।

ऐसा सम्मान किसी विरासत को फिर से पढ़ने का अवसर भी देता है। चौधरी चरण सिंह जी की चर्चा उनके विचारों, लेखन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनकी चिंता तक पहुँचे, तो उसका महत्व बढ़ता है। उनके नाम से जुड़ी राजनीतिक जिम्मेदारी भी यही है कि किसान और छोटे उत्पादक के प्रश्न सार्वजनिक बहस में बने रहें। जयंत चौधरी जी का अपने दादा और पिता से संबंध इसी व्यापक अर्थ में देखा जाना चाहिए। उन्हें एक परिवार का इतिहास मिला है, लेकिन उस इतिहास से जुड़े लोग आज की परिस्थितियों में जी रहे हैं। उनकी फसल आज बिकनी है, बच्चे की फीस आज भरनी है और रोजगार की जरूरत आज है। पुराने नेतृत्व के प्रति सम्मान के साथ वे नए नेतृत्व से वर्तमान का उत्तर चाहते हैं।

चौधरी चरण सिंह जी ने किसान के अधिकार और आर्थिक सम्मान की बात स्थापित की। चौधरी अजीत सिंह जी ने उस धारा को संगठन तथा राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ाया। जयंत चौधरी जी के सामने अब उसे ऐसे समय में आगे ले जाने का काम है जब गाँवों की जरूरतें और अवसर दोनों बदल रहे हैं। उनकी विरासत से निकटता की असली पहचान इसी काम में बनेगी—लोगों की बात सुनने, जिम्मेदारी निभाने और अपने फैसलों के परिणाम स्वीकार करने में।

## अध्याय 19 – जयंत चौधरी जी की राजनीतिक सोच और प्राथमिकताएँ

जयंत चौधरी जी की राजनीति को समझने के लिए उनके सामने खड़े लोगों को देखना होगा। इनमें वह किसान है जो अपनी फसल का भुगतान चाहता है, वह नौजवान है जो पढ़ाई के बाद काम तलाश रहा है और वह छोटा कारोबारी है जिसकी कमाई से पूरा घर चलता है। उनके परिवार की राजनीति लंबे समय से ग्रामीण समाज से जुड़ी रही है। अब उसी समाज की जरूरतों में बदलाव आया है। खेत की चिंता अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ शिक्षा, नौकरी, हुनर और कारोबार की चिंताएं भी जुड़ गई हैं। उनके संसदीय प्रश्नों और सार्वजनिक भूमिका में कृषि के साथ शिक्षा तथा रोजगार की चिंता दिखाई देती है। गाँव का परिवार इन विषयों को अलग-अलग नहीं जीता। खेती की आमदनी से पढ़ाई चलती है और बच्चे को काम मिलने पर घर की आर्थिक स्थिति बदल सकती है। चौधरी चरण सिंह जी ने गाँव और छोटे उत्पादक को आर्थिक नीति में उचित स्थान देने की बात की थी। जयंत चौधरी जी के सामने उस चिंता को आज की परिस्थितियों में समझने का प्रश्न है। अब किसान परिवार का कोई सदस्य खेती करता है, कोई शहर में नौकरी और कोई छोटा कारोबार। परिवार की जमीन गाँव में हो सकती है, लेकिन उसकी आय के स्रोत कई जगह फैले हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में ग्रामीण विकास की बात में खेती के साथ दूसरे कामों के अवसर भी शामिल होने चाहिए। अर्थव्यवस्था और वित्त की उनकी शिक्षा इस चर्चा की पृष्ठभूमि है। सार्वजनिक काम में बजट की राशि से आगे उसके उपयोग का प्रश्न आता है। संस्थान तक पहुँच, प्रशिक्षण की गुणवत्ता और शिकायत की सुनवाई जैसी व्यवस्थाएँ तय करती हैं कि घोषित अवसर का वास्तविक उपयोग कौन कर पाएगा। लोकसभा के अपने कार्यकाल में उन्होंने कृषि मशीनीकरण के साथ प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन जैसे प्रश्न उठाए। इन विषयों से उनकी दिलचस्पी का दायरा दिखाई देता है। खेती में बेहतर साधन और विद्यालय में अच्छा शिक्षक, दोनों परिवार के भविष्य को प्रभावित करते हैं। पहले का संबंध उत्पादन से है और दूसरे का अगली पीढ़ी की तैयारी से। शिक्षा की चर्चा में सबसे बड़ी मुश्किल अक्सर उसके बाद का रास्ता होता है। परिवार अपनी क्षमता से अधिक खर्च करके बच्चे को पढ़ाता है।

पढ़ाई पूरी होने के बाद जब काम नहीं मिलता तो परेशानी केवल बेरोजगार युवक की नहीं रहती। पूरे घर की उम्मीदें प्रभावित होती हैं। इसीलिए रोजगार की बात में डिग्री, प्रशिक्षण और काम के वास्तविक अवसरों का संबंध समझना जरूरी है। कौशल विकास और उद्यमशीलता की जिम्मेदारी मिलने के बाद जयंत चौधरी जी के सामने इस संबंध पर सीधे काम करने का अवसर आया। हुनर सीखने वाला युवक जानना चाहता है कि उसके प्रशिक्षण की बाजार में जरूरत है या नहीं। वह यह भी जानना चाहता है कि काम कहाँ मिलेगा, शुरुआती कमाई कितनी हो सकती है और आगे बढ़ने की गुंजाइश क्या है। किसी कार्यक्रम की उपयोगिता इन्हीं सवाल के उत्तर से तय होती है। यहाँ छोटे कारोबार का प्रश्न भी जुड़ता है। हर युवा सरकारी नौकरी में नहीं जा सकता और हर परिवार के पास बड़ा व्यवसाय शुरू करने की पूंजी नहीं होती। कोई मरम्मत का काम सीख सकता है, कोई खाद्य प्रसंस्करण, कोई सिलाई या कंप्यूटर से जुड़ी सेवा। लेकिन हुनर के बाद औजार, जगह, पूंजी और ग्राहक की जरूरत पड़ती है। प्रशिक्षण और आजीविका के बीच यह दूरी कम होना जरूरी है। जयंत चौधरी जी की प्रशासनिक भूमिका को इसी व्यावहारिक कसौटी पर देखना होगा। किसान का प्रश्न उनकी राजनीति में बना हुआ है। किसान आंदोलन के समर्थन में उनकी भागीदारी इस संबंध का स्पष्ट उदाहरण रही। मगर किसान की बात केवल आंदोलन के समय करने से पूरी नहीं होती। पानी की उपलब्धता, खेती की लागत, बाजार तक पहुँच और भुगतान जैसी समस्याएं लगातार मौजूद रहती हैं। जनप्रतिनिधि और संगठन का काम है कि इन पर संपर्क बना रहे, चाहे विषय उस समय बड़ी खबर हो या नहीं। इसमें छोटे किसान की स्थिति पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समान मूल्य मिलने के बावजूद सभी किसानों की आर्थिक हालत एक जैसी नहीं होती। जिसके पास छोटी जोत है और कम बचत है, उसके लिए बीमारी, फसल का नुकसान या भुगतान की देरी अधिक कठिन साबित हो सकती है। ग्रामीण समाज की बात करते समय जमीन और संसाधनों के इस अंतर को समझना जरूरी है। जयंत चौधरी जी के संसदीय प्रश्नों में यमुना की सफाई, नदियों में प्रदूषण और जल प्रबंधन जैसे विषय भी रहे हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि उनके सार्वजनिक काम में पर्यावरण और स्थानीय जीवन के प्रश्नों की जगह रही है। नदी का प्रदूषण धार्मिक आस्था के साथ स्वास्थ्य, खेती और नगर व्यवस्था को भी प्रभावित करता है।

पानी की समस्या को केवल एक विभाग की जिम्मेदारी मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। उनकी राजनीति का एक महत्वपूर्ण पक्ष अलग-अलग समुदायों के बीच संबंध भी है। राष्ट्रीय लोक दल की किसान राजनीति ऐसे सहयोग से मजबूत हुई जिसमें लोगों ने साझा आर्थिक प्रश्नों पर साथ काम किया। जयंत चौधरी जी को यह अनुभव विरासत में मिला है। इसके साथ उन दूरियों को भी समझना है जो समय-समय पर समाज में पैदा हुई हैं। किसी समुदाय से संवाद करने का अर्थ उसकी पूरी आबादी को एक जैसी राय वाला समूह मान लेना नहीं होता। मुस्लिम किसान, कारीगर, दुकानदार, छात्र और कामकाजी महिला की जरूरतें अलग हो सकती हैं। यही विविधता दूसरे समुदायों में भी मौजूद है। शिक्षा और कौशल की कोई व्यवस्था सबके लिए खुली हो सकती है, लेकिन जानकारी, दूरी, आर्थिक स्थिति या सामाजिक परिस्थिति के कारण उसका लाभ सबको समान रूप से नहीं मिलता। सार्वजनिक नीति की गंभीरता इस बात में है कि इन बाधाओं को पहचाना जाए। राजनीतिक सहयोग और गठबंधन के प्रश्न पर भी जयंत चौधरी जी की प्राथमिकताएं परखी जाती हैं। 2024 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के साथ जाने का उनका फैसला पार्टी की दिशा में बड़ा परिवर्तन था। सरकार में भागीदारी से काम के अवसर मिले, साथ ही जवाबदेही बढ़ी। समर्थकों के लिए यह जानना स्वाभाविक है कि इस भागीदारी का असर उनके जीवन से जुड़े प्रश्नों पर क्या पड़ता है। सरकार में भागीदारी के बाद पार्टी से अपेक्षाएं भी बढ़ती हैं। समर्थक जानना चाहते हैं कि उनकी चिंताएं किस स्तर पर उठीं और उन पर क्या काम हुआ। पद मिलने से खुला रास्ता उन्हीं परिणामों के माध्यम से लोगों के अनुभव से जुड़ता है। उनके सामने संगठन को अधिक लोगों की भागीदारी वाला बनाने की जिम्मेदारी भी है। पुराना कार्यकर्ता अनुभव लेकर आता है और नया कार्यकर्ता नई जरूरतों की समझ लेकर। युवा तथा महिलाएं तभी टिकाऊ ढंग से जुड़ेंगे जब उन्हें काम और निर्णय में उचित स्थान मिलेगा। किसी नेता के आसपास भीड़ होना और उसके संगठन में लोगों को जिम्मेदारी मिलना अलग बातें हैं।

इस राजनीतिक यात्रा में किसान, शिक्षा, कौशल और रोजगार की चिंताएं एक-दूसरे के पास आती हैं। इनके बीच व्यावहारिक संबंध बनाना आगे के काम का विषय है।

ग्रामीण परिवार के लिए इनका अलग-अलग मंत्रालयों में बंटा होना उसकी जरूरत को अलग-अलग नहीं करता। उनके सामने खड़ा युवा अपने परिवार की जमीन से संबंध भी रखना चाहता है और अपने लिए नया रास्ता भी तलाशता है। उसकी जरूरत को समझने वाली राजनीति को खेत और कक्षा, प्रशिक्षण और रोजगार, गाँव और शहर के बीच संबंध बनाना होगा। जयंत चौधरी जी की जिम्मेदारियों का बड़ा हिस्सा अब इसी काम से जुड़ा है।

## अध्याय 20 — युवा, शिक्षा, कौशल और रोजगार

किसी साधारण परिवार में बच्चे की पढ़ाई पूरे घर का साझा सपना होती है। पिता अपनी आमदनी में से कुछ बचाता है, माँ कई जरूरतें टालती है और बच्चा इस उम्मीद के साथ आगे बढ़ता है कि पढ़ाई पूरी होने पर उसकी जिंदगी बेहतर होगी। गाँव और छोटे कस्बों में यह उम्मीद और भी बड़ी होती है। वहाँ एक युवक या युवती को अच्छा काम मिल जाने से घर की आर्थिक हालत के साथ अगली पीढ़ी की पढ़ाई का रास्ता भी बदल सकता है। लेकिन पढ़ाई से रोजगार तक पहुँचने का रास्ता हर किसी के लिए आसान नहीं होता। प्रमाणपत्र हाथ में आ जाता है, फिर भी नौकरी की तलाश चलती रहती है। कई युवाओं को समझ नहीं आता कि उन्होंने जो पढ़ा है, उसका उपयोग कहाँ होगा। कुछ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में वर्ष लगा देते हैं। कुछ घर की जरूरतों के कारण जो काम मिलता है, वही करने लगते हैं। इस अनुभव में निराशा के साथ परिवार के प्रति जिम्मेदारी का दबाव भी होता है।

जयंत चौधरी जी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका के संदर्भ में यह विषय विशेष महत्व रखता है। जून 2024 में उन्हें कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। इन दोनों क्षेत्रों का संबंध युवाओं के जीवन के लगातार जुड़े हुए पड़ावों से है। विद्यालय और कॉलेज बुनियाद तैयार करते हैं, प्रशिक्षण काम की तैयारी में मदद करता है और रोजगार उस तैयारी को आजीविका में बदलता है। उनकी अपनी शिक्षा विदेश तक हुई, लेकिन उनके सामने जिम्मेदारी उन युवाओं की भी है जिनके लिए अपने जिले से बाहर पढ़ने जाना कठिन होता है। किसी के पास फीस के पैसे नहीं हैं, किसी के घर से संस्थान बहुत दूर है और किसी को सही समय पर जानकारी ही नहीं मिलती। इसलिए अच्छे अवसर उपलब्ध होने के साथ उन तक पहुँच का प्रश्न भी जरूरी है। इस विषय से उनका संबंध मंत्री बनने के बाद ही शुरू नहीं हुआ। लोकसभा के अपने कार्यकाल में उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन से जुड़े प्रश्न उठाए थे। इन प्रश्नों की जड़ में विद्यालय की रोजमर्रा की स्थिति है। भवन और नामांकन के साथ शिक्षक, पढ़ाई की निरंतरता और बच्चों की समझ पर ध्यान देना पड़ता है।

किसी युवक को तकनीकी प्रशिक्षण देते समय यह मान लेना कठिन है कि उसकी पिछली पढ़ाई ने उसे पूरी तैयारी दी होगी। संभव है कि वह काम सीखने में तेज हो, लेकिन लिखित निर्देश समझने में कठिनाई महसूस करे। कोई गणना कर सकता है, पर अंग्रेजी में लिखी मशीन की जानकारी उसके लिए बाधा हो सकती है। ऐसे युवाओं को अतिरिक्त सहायता देने से उनकी क्षमता सामने आ सकती है। भाषा या पुराने शैक्षणिक अवसर की कमी को उनकी योग्यता का अंतिम प्रमाण नहीं मानना चाहिए। हुनर की चर्चा में हाथ से काम करने वाले व्यक्ति के सम्मान का प्रश्न भी आता है। बिजली का काम जानने वाला, मशीन ठीक करने वाला, बढ़ई, दर्जी और दूसरे कारीगर हमारे रोजमर्रा के जीवन की जरूरत पूरी करते हैं। फिर भी कई परिवार इन कामों को मजबूरी में अपनाया गया रास्ता समझते हैं। इस धारणा को बदलने के लिए भाषण के साथ काम की अच्छी परिस्थितियां, उचित कमाई और आगे बढ़ने के अवसर चाहिए। जयंत चौधरी जी के सामने कौशल विकास की जिम्मेदारी इसी व्यापक अर्थ में आती है। प्रशिक्षण केंद्र में किसी पाठ्यक्रम का पूरा हो जाना एक पड़ाव है। उसके बाद युवक काम कर पा रहा है या नहीं, सीखे हुए हुनर का उपयोग हो रहा है या नहीं और उसकी कमाई में सुधार आया है या नहीं—इन बातों से प्रशिक्षण की असली उपयोगिता समझ में आती है। 11 जुलाई 2024 को मेरठ में जन शिक्षण संस्थानों के क्षेत्रीय सम्मेलन में जयंत चौधरी जी ने भाग लिया। इस अवसर पर कौशल प्रशिक्षण और युवाओं तक उसकी पहुँच पर चर्चा हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आयोजित यह कार्यक्रम उनके नए मंत्रालय और उनके परिचित ग्रामीण क्षेत्र के बीच संवाद का एक अवसर था।

प्रशिक्षण की योजना बनाते समय स्थानीय जरूरतों को समझना आवश्यक है। जिस क्षेत्र में कृषि उपकरणों का इस्तेमाल अधिक है, वहाँ उनकी मरम्मत और रखरखाव का हुनर उपयोगी हो सकता है। जहाँ खाद्य पदार्थों का उत्पादन होता है, वहाँ प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण से जुड़े काम की गुंजाइश हो सकती है। हर जिले में एक ही तरह का पाठ्यक्रम खोल देने से समान परिणाम मिलने की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नई तकनीक के साथ पुराने हुनर का संबंध भी महत्वपूर्ण है। कोई कारीगर वर्षों से अच्छा काम करता है, लेकिन हिसाब रखने, ग्राहक तक पहुँचने या अपने उत्पाद की तस्वीर और जानकारी भेजने में पीछे रह जाता है। उसे अपने काम को फिर से शुरू करने की जरूरत नहीं है।

थोड़ी अतिरिक्त सीख उसके मौजूदा हुनर की उपयोगिता और पहुँच बढ़ा सकती है। ऐसे प्रशिक्षण में व्यक्ति के पहले से मौजूद अनुभव की कद्र होनी चाहिए।

काम सीखने का एक हिस्सा वास्तविक कार्यस्थल पर भी पूरा होता है। प्रशिक्षण केंद्र में अभ्यास और ग्राहक की जरूरत के अनुसार समय पर काम पूरा करना अलग अनुभव हैं। जहाँ सुरक्षित और उचित व्यवस्था हो, वहाँ अनुभवी कारीगर या संस्था के साथ काम सीखने से युवाओं को लाभ मिल सकता है। लेकिन इस दौरान उनके श्रम का सम्मान और सीखने का स्पष्ट अवसर होना जरूरी है। केवल सस्ता श्रम उपलब्ध कराना प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं हो सकता। रोजगार की गुणवत्ता का प्रश्न भी यहीं जुड़ता है। किसी युवक को दूर शहर में काम मिल जाए, लेकिन किराये, भोजन और आने-जाने के बाद बहुत कम पैसा बचे, तो परिवार की उम्मीद पूरी नहीं होती। काम के घंटे, सुरक्षा और आगे की संभावना भी महत्व रखते हैं। इसलिए केवल नौकरी मिलने की संख्या से पूरी तस्वीर नहीं बनती। युवक उस काम में टिक पा रहा है या नहीं, यह भी देखना पड़ता है। युवतियों के सामने कई बार अतिरिक्त बाधाएं होती हैं। संस्थान की दूरी, सुरक्षित आवागमन, परिवार की आर्थिक स्थिति और घर की जिम्मेदारियां उनकी भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। कई युवतियाँ प्रशिक्षण लेना चाहती हैं, लेकिन समय और स्थान उनके अनुकूल नहीं होते। इन बातों को ध्यान में रखकर व्यवस्था बने तो अधिक लोगों के लिए अवसर खुल सकते हैं। उनके प्रशिक्षण के विकल्प भी सीमित नहीं होने चाहिए। किसी युवती की रुचि कंप्यूटर, मशीन, लेखांकन या तकनीकी काम में हो सकती है। उसे अपनी क्षमता के अनुसार रास्ता चुनने की गुंजाइश मिलनी चाहिए। इसी तरह युवक को भी केवल परंपरागत अपेक्षाओं के आधार पर किसी काम की ओर धकेलना उचित नहीं है। अच्छी व्यवस्था विकल्प समझने और अपना निर्णय लेने में सहायता करती है। उद्यमशीलता की जिम्मेदारी में अपना छोटा काम शुरू करने वालों का प्रश्न आता है। हुनर सीखने के बाद दुकान या कार्यस्थल, उपकरण और शुरुआती खर्च की जरूरत पड़ सकती है। सबसे कठिन बात कई बार पहला ग्राहक मिलना होती है। व्यवसाय चलाने के लिए काम जानने के साथ लागत, बिक्री और बचत का हिसाब समझना भी आवश्यक है। इन जरूरतों को समझे बिना हर बेरोजगार युवक से अपना कारोबार शुरू करने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं होगा। ग्रामीण परिवारों के लिए स्थानीय अवसरों का विशेष महत्व है।

जो युवा बाहर जाना चाहता है, उसे तैयारी और जानकारी मिले। जो अपने इलाके में रहकर काम करना चाहता है, उसके सामने भी रास्ते हों। परिवार की जिम्मेदारी, बुजुर्गों की देखभाल और खेती से संबंध के कारण सबके लिए बाहर जाना संभव नहीं होता। विकास का लाभ तभी व्यापक होगा जब अवसर कुछ बड़े शहरों तक सीमित न रहें। जयंत चौधरी जी के सामने शिक्षा, कौशल और रोजगार को जोड़ने की जिम्मेदारी इसलिए बड़ी है कि इन क्षेत्रों में कई संस्थाओं को साथ काम करना पड़ता है। मंत्रालय, राज्य सरकार, शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और रोजगार देने वाले प्रतिष्ठान—हर स्तर की अपनी भूमिका है। कहीं जानकारी अटकने या तालमेल टूटने का नुकसान अंत में प्रशिक्षार्थी को उठाना पड़ता है। उनकी किसान राजनीति की पृष्ठभूमि इस काम को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संदर्भ देती है। किसान का परिवार अपनी अगली पीढ़ी के लिए बेहतर जीवन चाहता है। खेत की आमदनी सुधरे और बच्चे के पास खेती के अलावा भी विकल्प हों, ये दोनों इच्छाएं साथ चल सकती हैं। शिक्षा और कौशल उस परिवार के लिए भविष्य में अधिक स्वतंत्रता से निर्णय लेने का साधन बन सकते हैं।

इस जिम्मेदारी का असर अंततः युवाओं के अनुभव में दिखाई देगा। किसी को अपनी पढ़ाई का उपयोग करने का अवसर मिले, किसी का पुराना हुनर बेहतर कमाई से जुड़े और कोई युवती अपने मन का काम सीखकर आगे बढ़ सके—ऐसे परिवर्तन ही नीतियों को लोगों के जीवन से जोड़ते हैं। जयंत चौधरी जी के इस कार्यक्षेत्र को समझने की सबसे ठोस कसौटी भी यही है।

## अध्याय 21 — किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जयंत चौधरी जी का दृष्टिकोण

किसान परिवार की हालत केवल खेत में खड़ी फसल देखकर नहीं समझी जा सकती। अच्छी पैदावार के बावजूद घर पर कर्ज हो सकता है। जमीन अपनी हो सकती है, लेकिन सिंचाई, खाद, मजदूरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च जुटाना कठिन हो सकता है। बाहर से संपन्न दिखाई देने वाले गाँव के भीतर भी ऐसे परिवार होते हैं जिनकी पूरी आर्थिक व्यवस्था एक भुगतान या एक फसल पर टिकी होती है। जयंत चौधरी जी की किसान संबंधी राजनीति को इसी ग्रामीण जीवन के बीच देखना चाहिए। उनके दादा चौधरी चरण सिंह जी ने खेती और छोटे उत्पादक को आर्थिक नीति में उचित स्थान देने का प्रश्न उठाया था। चौधरी अजीत सिंह जी ने गन्ने के मूल्य, भुगतान और किसानों की दूसरी मांगों को राजनीतिक मंच दिया। जयंत चौधरी जी के सामने इन प्रश्नों के साथ नई परिस्थितियाँ हैं। खेती करने वाली पीढ़ी की चिंता और उसके बच्चों की आकांक्षाएँ कई बार अलग दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों का संबंध एक ही घर की आर्थिक सुरक्षा से है।

उनके सार्वजनिक जीवन में किसान के प्रश्न की जगह स्पष्ट रही है। कृषि कानूनों के विरोध में हुए आंदोलन का उन्होंने समर्थन किया। अपने शुरुआती संसदीय कार्यकाल में कृषि मशीनीकरण और पानी के उपयोग जैसे विषयों पर प्रश्न उठाए। इन हस्तक्षेपों से उनके काम की दिशा का परिचय मिलता है। हालांकि उनकी ग्रामीण आर्थिक सोच को किसी एक आंदोलन या वक्तव्य में समेटना उचित नहीं होगा। उसे उनके अलग-अलग कामों और जिम्मेदारियों के बीच समझना पड़ता है। किसान आंदोलन में भागीदारी का एक महत्व किसानों की बात सुने जाने की मांग से जुड़ा था। सरकार की नीति कागज पर चाहे जितनी व्यवस्थित दिखाई दे, उसका असर उस व्यक्ति के अनुभव से भी समझना पड़ता है जो खेती करता है। उसे अपनी जमीन, स्थानीय बाजार और भुगतान की व्यवस्था की व्यावहारिक जानकारी होती है। इसलिए कृषि संबंधी निर्णयों में किसान की भागीदारी केवल औपचारिक बातचीत तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। यह भागीदारी भी कुछ बड़े किसानों की राय से पूरी नहीं होती। छोटी जोत वाले किसान, बटाई पर खेती करने वाले और खेतिहर मजदूर की स्थिति अलग होती है।

किसी के पास मशीन खरीदने की क्षमता है, किसी को उसे किराये पर लेना पड़ता है। कोई फसल रोककर बेच सकता है, किसी को तत्काल नकद चाहिए। एक ही नीति इन सब पर अलग असर डाल सकती है। जयंत चौधरी जी के सामने किसान की साझा पहचान के भीतर मौजूद इन अंतरों को समझने की जिम्मेदारी है। राजनीतिक सभा में सब एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन रोजमर्रा की जरूरतों में फर्क बना रहता है। छोटे किसान को कभी बड़ी नई योजना से पहले समय पर सिंचाई, पास में मरम्मत की सुविधा या अपनी उपज की तौल में भरोसा चाहिए होता है। इन साधारण दिखाई देने वाली जरूरतों का उसकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने का भुगतान इसी तरह का प्रश्न है। किसान अपनी फसल दे चुका होता है, लेकिन पैसा आने में देरी हो तो अगली बुआई और घर का खर्च प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में घोषित मूल्य और वास्तव में उपलब्ध आमदनी के बीच अंतर पैदा हो जाता है। जिस रकम का उपयोग किसान आज नहीं कर सकता, उससे वह आज की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। इसलिए ग्रामीण आय की चर्चा में भुगतान के समय को महत्व देना आवश्यक है। किसान को उचित दाम मिले, उसके साथ उसे अपनी कमाई का इस्तेमाल करने की स्वतंत्रता भी मिले। देर से आया भुगतान कई बार उस अतिरिक्त उधार की भरपाई भी नहीं कर पाता जो परिवार ने इंतजार के दौरान लिया होता है। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति में यह प्रश्न प्रमुख रहा और जयंत चौधरी जी के लिए भी यह विरासत का एक ठोस विषय है। खेती की लागत का दूसरा पहलू साधनों तक पहुँच है। नई मशीन से काम आसान हो सकता है, लेकिन हर किसान उसे खरीद नहीं सकता। यदि किसी इलाके में किराये पर मशीन उपलब्ध हो, उसका रखरखाव ठीक हो और जरूरत के समय वह मिल सके, तो छोटे किसान को भी लाभ हो सकता है। कृषि मशीनीकरण पर विचार करते समय मशीन की संख्या के साथ उसकी वास्तविक पहुँच देखनी पड़ती है। इससे गाँव में रोजगार के दूसरे रास्ते भी जुड़ते हैं। उपकरण चलाने, उनकी मरम्मत करने और नियमित देखभाल का काम स्थानीय युवा सीख सकते हैं। खेती और कौशल विकास के बीच यह एक व्यावहारिक संबंध है। जयंत चौधरी जी की प्रशासनिक जिम्मेदारियों के संदर्भ में ऐसे संबंध महत्वपूर्ण हैं।

प्रशिक्षण की दिशा स्थानीय जरूरतों से मिले तो किसान को सुविधा और युवा को काम, दोनों की संभावना बन सकती है।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था का दायरा खेती से आगे जाता है। दूध बेचने वाला परिवार, छोटा दुकानदार, ढुलाई करने वाला व्यक्ति और कारीगर भी गाँव की आर्थिक गतिविधि का हिस्सा हैं। किसान के पास पैसा आता है तो उसका एक हिस्सा इसी स्थानीय व्यवस्था में खर्च होता है। कमाई घटने या भुगतान रुकने पर असर दूसरे कामों तक पहुँच सकता है। इसलिए किसान की आर्थिक स्थिति पूरे इलाके के कारोबार से जुड़ी होती है। यहीं चौधरी चरण सिंह जी की छोटे उत्पादक के प्रति चिंता आज के संदर्भ में महत्व रखती है। गाँव में उत्पादन हो, उसका कुछ प्रसंस्करण पास में हो और स्थानीय लोगों को उससे काम मिले, तो कमाई के अधिक रास्ते बन सकते हैं। लेकिन केवल प्रसंस्करण इकाई खोल देना पर्याप्त नहीं होगा। उसे नियमित आपूर्ति, बिजली, प्रशिक्षित लोग और बाजार भी चाहिए। इन जरूरतों के बिना लगाई गई पूंजी फंस सकती है। कौशल प्रशिक्षण और स्थानीय कृषि सेवाओं के बीच ऐसा संबंध बन सकता है। इसे जयंत चौधरी जी के कार्यकाल की सिद्ध उपलब्धि नहीं माना जा सकता; यह उनके प्रशासनिक कार्यक्षेत्र और किसान राजनीति के बीच काम की एक संभावना है। उसका परिणाम संस्थानों, स्थानीय मांग और प्रशिक्षित युवाओं के बीच वास्तविक तालमेल पर निर्भर होगा। पानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक और बुनियादी प्रश्न है। समय पर सिंचाई न मिले तो बाकी मेहनत प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर पानी के अनुचित उपयोग का असर आने वाले वर्षों की खेती पर पड़ सकता है। जयंत चौधरी जी ने अपने संसदीय काम में पानी के उपयोग और नदियों से जुड़े प्रश्न उठाए थे। यह रुचि खेती को पर्यावरण और सार्वजनिक व्यवस्था के साथ रखकर देखने की गुंजाइश देती है। किसान के लिए पानी का विषय बहुत व्यावहारिक होता है। उसे जानना है कि सिंचाई कब मिलेगी, उसका खर्च कितना होगा और फसल बचाने का साधन क्या है। लंबे समय के सुधारों के साथ इन तत्काल जरूरतों को भी समझना पड़ता है। जल संरक्षण की जिम्मेदारी किसान पर डालते समय उसके लिए उपलब्ध तकनीक, सलाह और आर्थिक सहायता की स्थिति देखनी होगी। ग्रामीण परिवार की सुरक्षा में स्वास्थ्य और शिक्षा का खर्च भी शामिल है। फसल से हुई बचत एक गंभीर बीमारी में खत्म हो सकती है। बच्चे की पढ़ाई के लिए लिया गया उधार कई वर्षों तक चल सकता है।

इसलिए किसान की आय बढ़ाने की कोशिश के साथ ऐसी सार्वजनिक सुविधाएं भी जरूरी हैं जो परिवार को अचानक आने वाले बड़े खर्च से बचा सकें।

इस जीवन में महिलाओं का योगदान अक्सर आर्थिक चर्चा में पूरी तरह दिखाई नहीं देता। खेती, पशुधन और घर की जिम्मेदारियां कई परिवारों में उनके श्रम से चलती हैं। प्रशिक्षण, जानकारी और संस्थागत सहायता तक उनकी पहुँच बढ़ने से पूरे परिवार को लाभ हो सकता है। ग्रामीण विकास को केवल परिवार के पुरुष मुखिया तक पहुँचाकर पूरा नहीं माना जा सकता। युवा पीढ़ी के सामने खेती में रहने या बाहर काम करने का प्रश्न भी है। कुछ युवा खेती को बेहतर तरीके से करना चाहते हैं, कुछ दूसरी नौकरी या व्यवसाय में जाना चाहते हैं। दोनों विकल्पों के लिए अवसर होने चाहिए। गाँव से बाहर जाना मजबूरी ही हो और गाँव में रहना बेरोजगारी का दूसरा नाम बन जाए, ऐसी स्थिति परिवार की स्वतंत्रता कम कर देती है। जयंत चौधरी जी की ग्रामीण राजनीति के सामने इसी स्वतंत्रता को बढ़ाने का प्रश्न है। किसान अपनी उपज बेचने, बच्चे को पढ़ाने और अगली फसल लगाने का निर्णय कम असुरक्षा के साथ कर सके। युवा अपने लिए काम चुने और छोटे उत्पादक को बाजार तक पहुँच मिले। इन उद्देश्यों का संबंध एक-दूसरे से है, हालांकि इन्हें हासिल करने के साधन अलग-अलग होंगे।

उनकी जिम्मेदारी की सीमाएं भी स्पष्ट रहनी चाहिए। कौशल विकास या शिक्षा मंत्रालय अकेले फसल का मूल्य, सिंचाई और कृषि बाजार की हर समस्या हल नहीं कर सकता। संसद सदस्य, पार्टी नेता और मंत्री के रूप में उनकी भूमिकाएं अलग हैं। कहीं उन्हें सीधे प्रशासनिक काम करना है और कहीं दूसरे विभागों तथा राज्य सरकारों के सामने विषय उठाना है। किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के प्रति उनके रुख की असली पहचान इसी निरंतर काम में बनेगी। आंदोलन के समय साथ खड़ा होना महत्वपूर्ण है; उसके बाद भुगतान, पानी, प्रशिक्षण और स्थानीय रोजगार के प्रश्नों पर संपर्क बनाए रखना भी जरूरी है। गाँव का परिवार किसी बड़े आर्थिक निष्कर्ष से पहले अपने जीवन में आया फर्क देखता है। उसकी अनिश्चितता कुछ कम हो और उसकी मेहनत से बेहतर जीवन की गुंजाइश बने, तो राजनीति से उसका संबंध अधिक भरोसेमंद होता है।

## अध्याय 22 – सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व

गाँव में एक ही रास्ते से होकर विद्यालय जाने वाले दो बच्चों की मंजिल हमेशा एक जैसी नहीं होती। एक के घर में पढ़ाई के लिए जगह है, जरूरत पड़ने पर मदद करने वाला व्यक्ति है और आगे की शिक्षा का खर्च उठाने की क्षमता है। दूसरे को पढ़ाई के साथ घर का काम संभालना पड़ सकता है। दोनों के लिए प्रवेश का नियम समान हो, तब भी उनकी परिस्थितियाँ समान नहीं हो जातीं। सामाजिक न्याय का सवाल इसी अंतर से शुरू होता है। जयंत चौधरी जी की राजनीति में इस प्रश्न का महत्व उनकी पारिवारिक विरासत और उनकी अपनी सार्वजनिक जिम्मेदारियों, दोनों से जुड़ा है। चौधरी चरण सिंह जी ने ग्रामीण समाज और किसान को आर्थिक तथा राजनीतिक निर्णयों में उचित स्थान देने की बात की थी। जयंत चौधरी जी के सामने उसी ग्रामीण समाज के भीतर अवसरों और प्रभाव के अंतर को समझने की जिम्मेदारी भी है। गाँव को उसका अधिकार मिले और गाँव के भीतर कमजोर व्यक्ति की आवाज भी सुनी जाए, तभी प्रतिनिधित्व अधिक व्यापक बनता है। किसान की पहचान लोगों को साझा मांग पर एक साथ ला सकती है। लेकिन इस पहचान के भीतर जमीन, आमदनी और सामाजिक पहुँच के अंतर बने रहते हैं। बड़े किसान की बात अधिकारी तक आसानी से पहुँच सकती है, जबकि छोटी जोत वाला व्यक्ति कई बार अपनी परेशानी बताने में भी संकोच करता है। भूमिहीन मजदूर की जरूरत कुछ और होती है। इन सबको एक मंच पर लाने के बाद भी यह देखना जरूरी है कि बातचीत में किसकी बात अधिक सुनी जा रही है। राष्ट्रीय लोक दल जैसी पार्टी के लिए यह प्रश्न विशेष महत्व रखता है, क्योंकि उसकी राजनीति का बड़ा आधार ग्रामीण समाज रहा है। जयंत चौधरी जी को संगठन में पुराने संबंधों को निभाने के साथ उन लोगों तक भी पहुँचना है जिनकी राजनीतिक पकड़ कम है। इसमें छोटे किसान, मजदूर, कारीगर, महिलाएं और पहली बार सार्वजनिक जीवन में आने वाले युवा शामिल हो सकते हैं। उनकी भागीदारी का अर्थ केवल किसी कार्यक्रम में उपस्थित होना नहीं है। अपनी बात रखने और निर्णय को प्रभावित करने की गुंजाइश भी होनी चाहिए। प्रतिनिधित्व की चर्चा अक्सर चुनावी टिकट पर आकर ठहर जाती है। टिकट महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे विधानमंडल और संसद तक पहुँचने का रास्ता खुलता है।

लेकिन किसी समुदाय का एक व्यक्ति चुन लिया जाए तो उस समुदाय के सभी वर्गों की समस्याएं अपने आप सामने नहीं आ जातीं। चुने हुए प्रतिनिधि और साधारण परिवार के बीच नियमित संपर्क बना रहना भी जरूरी है। पार्टी के भीतर भी यही बात लागू होती है। जिला और स्थानीय स्तर पर कौन जिम्मेदारी संभालता है, बैठक में कौन बोल सकता है और शिकायत किस तरह ऊपर पहुँचती है—इन व्यवस्थाओं से संगठन का वास्तविक स्वरूप तय होता है। पद देने के बाद काम करने की स्वतंत्रता और आवश्यक सहयोग न मिले तो प्रतिनिधित्व अधूरा रह जाता है। किसी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी मिले, तो उसके सुझावों और अनुभव को गंभीरता से लेने की जगह भी होनी चाहिए।

जयंत चौधरी जी की शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां सामाजिक न्याय के इस प्रश्न को और ठोस बनाती हैं। शिक्षा का अवसर व्यक्ति के आगे बढ़ने में मदद कर सकता है, लेकिन उसके लिए प्रवेश मिलना ही पर्याप्त नहीं है। पढ़ाई जारी रखने का खर्च, संस्थान तक पहुँच, भाषा और परिवार की परिस्थिति भी असर डालती है। योजना के नियमों में पात्र होना और उसका लाभ ले पाना कई बार अलग अनुभव होते हैं। अपने लोकसभा कार्यकाल में उन्होंने प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन से जुड़े प्रश्न उठाए थे। इन विषयों का सीधा संबंध अवसरों के अंतर से है। जिस परिवार के पास निजी सहायता लेने की क्षमता नहीं है, उसके बच्चे के लिए विद्यालय की पढ़ाई और शिक्षक की उपलब्धता विशेष महत्व रखती है। सार्वजनिक शिक्षा की कमजोरी का बोझ अक्सर उसी बच्चे पर अधिक पड़ता है जिसके पास दूसरा रास्ता कम है। कौशल प्रशिक्षण में भी ऐसी ही परिस्थितियां सामने आती हैं। कोई युवक जानकारी मिलने पर तुरंत आवेदन कर सकता है। दूसरा आवेदन की प्रक्रिया, जरूरी कागज या आने-जाने के खर्च में उलझ सकता है। किसी को परिवार का सहयोग मिलता है, जबकि किसी को प्रशिक्षण के दौरान कमाई बंद होने का डर रहता है। इन बाधाओं को समझकर व्यवस्था बने तो कार्यक्रम अधिक लोगों तक पहुँच सकता है। यहाँ भाषा भी अहम है। स्थानीय भाषा में समझाया गया पाठ उस व्यक्ति के लिए रास्ता खोल सकता है जो काम सीखने में सक्षम है, लेकिन कठिन शब्दों के कारण पीछे रह जाता है। सवाल पूछने का अवसर और प्रशिक्षक का धैर्य भी सीखने पर असर डालते हैं। किसी की झिझक को उसकी क्षमता की कमी मान लेना गलत होगा।

महिलाओं की भागीदारी में अवसर और पहुँच का अंतर कई रूपों में दिखाई देता है। प्रशिक्षण केंद्र तक सुरक्षित आना-जाना, घर की जिम्मेदारियों के अनुकूल समय और आगे काम करने की परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण हो सकती हैं। ऐसी जरूरतों को ध्यान में रखना सुविधा देने का हिस्सा है। इससे महिलाओं को अपने निर्णय लेने और अपनी क्षमता का उपयोग करने की अधिक गुंजाइश मिलती है।

राजनीतिक संगठन में भी महिलाओं की मौजूदगी तभी अर्थपूर्ण होती है जब वे केवल निर्धारित कार्यक्रमों तक सीमित न रहें। खेती, शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और रोजगार के विषयों पर उनका अनुभव संगठन के काम को बेहतर बना सकता है। निर्णय लेने वाली बैठकों में उनकी सक्रिय भूमिका से उन समस्याओं की पहचान हो सकती है जो सामान्य राजनीतिक चर्चा में पीछे रह जाती हैं। मुस्लिम समाज के संदर्भ में भी प्रतिनिधित्व को इसी विस्तार से समझना जरूरी है। समुदाय के भीतर सभी परिवारों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति एक जैसी नहीं होती। एक प्रभावशाली व्यक्ति की सरकार या पार्टी तक पहुँच हो सकती है, जबकि छोटे कारीगर और मजदूर परिवार की परेशानी वहाँ तक नहीं पहुँचती। मुस्लिम प्रतिनिधित्व की गंभीर चर्चा में इन अंतरों के लिए जगह होनी चाहिए। इसी तरह दलित और पिछड़े समाज के भीतर भी अलग-अलग अनुभव होते हैं। शिक्षा, जमीन, स्थानीय प्रभाव और आर्थिक संसाधन व्यक्ति की स्थिति को प्रभावित करते हैं। केवल बड़े सामाजिक नामों में लोगों को रख देने से उनकी वास्तविक जरूरतें पूरी तरह सामने नहीं आतीं। राजनीतिक नेतृत्व को गाँव और मोहल्ले के स्तर पर सुनना पड़ता है। इस सुनवाई में प्रशासन के व्यवहार का बड़ा स्थान है। कोई व्यक्ति शिकायत लेकर जाए तो उसकी बात बिना अपमान के सुनी जाए। वह अपनी परेशानी बता सके और उसे प्रक्रिया समझ में आए। यह अनुभव नागरिक के भरोसे को प्रभावित करता है। अच्छे नियमों के साथ उनका निष्पक्ष और सम्मानजनक पालन भी आवश्यक है। जयंत चौधरी जी के लिए सामाजिक न्याय का प्रश्न उनके गठबंधन संबंधी फैसलों से भी जुड़ता है। अलग-अलग सामाजिक समूह किसी राजनीतिक निर्णय को अपने अनुभव के आधार पर देखते हैं। कुछ लोगों को उससे काम के अवसर बढ़ने की उम्मीद हो सकती है, जबकि दूसरे अपनी चिंताओं के लिए आश्वासन चाहते हैं। नेतृत्व की जिम्मेदारी दोनों को सुनने की है। सवाल करने वाले समर्थक से संवाद टूट जाए तो संगठन अपने ही अनुभवों का एक हिस्सा खो देता है।

समान भागीदारी के सामने इन सभी स्तरों पर अलग बाधाएं हैं। कहीं संगठन में प्रवेश कठिन है, कहीं अवसर की जानकारी नहीं पहुँचती और कहीं सुनवाई कमजोर है। इनके बारे में सामान्य परिवारों का अनुभव सामने आए तो राजनीतिक दावों और वास्तविक स्थिति के बीच का अंतर अधिक साफ हो सकता है।

सामाजिक न्याय का एक व्यावहारिक अर्थ यह भी है कि किसी परिवार का भविष्य केवल इस बात पर निर्भर न रहे कि उसकी पहचान किससे है। जानकारी और अवसर पाने के लिए प्रभावशाली व्यक्ति की सिफारिश जरूरी न हो। पात्र व्यक्ति अपने अधिकार और उपलब्ध सुविधाओं को समझ सके तथा उनका उपयोग कर सके। ऐसी व्यवस्था से राजनीतिक संपर्क के बाहर खड़े लोगों का भी भरोसा बढ़ता है। चौधरी चरण सिंह जी की ग्रामीण चिंता और चौधरी अजीत सिंह जी के संगठनात्मक अनुभव से आगे बढ़ते हुए जयंत चौधरी जी के सामने भागीदारी का दायरा बढ़ाने की जिम्मेदारी है। किसान की आवाज के साथ मजदूर की बात, अनुभवी कार्यकर्ता के साथ नए युवक का सुझाव और नेतृत्व के साथ साधारण सदस्य का अनुभव भी महत्व पाए। इस तरह प्रतिनिधित्व व्यक्ति से आगे बढ़कर संगठन के रोजमर्रा के व्यवहार में दिखाई दे सकता है।

## अध्याय 23 — राष्ट्रीय लोक दल का संगठन और नई पीढ़ी का नेतृत्व

किसी राजनीतिक दल की असली उम्र उसके कार्यकर्ताओं की यादों में भी दर्ज होती है। कोई बताता है कि वह पहली बार चौधरी चरण सिंह जी की सभा में कब गया था। किसी ने चौधरी अजीत सिंह जी के साथ चुनाव और आंदोलन देखे होते हैं। नए कार्यकर्ता का परिचय जयंत चौधरी जी के दौर से शुरू होता है। राष्ट्रीय लोक दल में ये अलग-अलग अनुभव एक साथ मौजूद हैं। पार्टी की निरंतरता इन्हीं लोगों से बनती है, लेकिन समय के साथ उनके काम करने के तरीके और अपेक्षाएं बदलती हैं। मई 2021 में जयंत चौधरी जी ने राष्ट्रीय लोक दल की अध्यक्षता ऐसे समय संभाली जब पार्टी अपने संस्थापक चौधरी अजीत सिंह जी को खो चुकी थी। परिवार के शोक के साथ संगठन के भविष्य की चिंता जुड़ी हुई थी। पुराने कार्यकर्ताओं को नेतृत्व की निरंतरता चाहिए थी और नए नेतृत्व के सामने पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी थी। जयंत चौधरी जी पहले से सार्वजनिक जीवन में सक्रिय थे, फिर भी अध्यक्ष बनने के बाद उनकी जवाबदेही का दायरा बढ़ गया। पिता की मौजूदगी में पार्टी में काम करने और उनके बाद अंतिम निर्णय की जिम्मेदारी उठाने में अंतर होता है। अब असहमति सुनना, जिम्मेदारियां बांटना, चुनावी सहयोग तय करना और कार्यकर्ताओं का विश्वास बनाए रखना सीधे उनके नेतृत्व से जुड़ गया। उन्हें ऐसा संगठन मिला जिसकी अपनी राजनीतिक पहचान थी, लेकिन जिसने कठिन चुनावी दौर भी देखे थे। राष्ट्रीय लोक दल की पहचान लंबे समय तक चौधरी परिवार और किसान राजनीति से गहराई से जुड़ी रही है। इस संबंध ने पार्टी को अपनत्व और निरंतरता दी। गाँवों में परिवार के नाम से पुराने परिचय खुलते थे। मगर इसी व्यवस्था में एक प्रश्न भी बना रहता है—स्थानीय स्तर पर कितना नेतृत्व तैयार हुआ और वह अपने बल पर कितना काम कर सकता है? अध्यक्ष हर गाँव की समस्या नहीं सुन सकता। किसी किसान का भुगतान अटका है, किसी छात्र को दस्तावेज बनवाने में परेशानी है या किसी मोहल्ले की सार्वजनिक सुविधा बंद है, तो पहली मुलाकात स्थानीय कार्यकर्ता से होती है। पार्टी के बारे में व्यक्ति की राय उस मुलाकात से भी बनती है। कार्यकर्ता बात समझता है या टाल देता है, सही जानकारी देता है या ऐसा आश्वासन दे देता है जिसे निभाना संभव नहीं—इन छोटी लगने वाली बातों का असर लंबे समय तक रहता है। स्थानीय संगठन और शीर्ष नेतृत्व के बीच संबंध इसलिए महत्वपूर्ण है।

ऊपर तक केवल प्रशंसा पहुँचे तो नेतृत्व अपने जनाधार की कठिनाइयों से अनजान रह सकता है। जिले की स्थिति, कार्यकर्ताओं की नाराजगी और जनता के सवाल ईमानदारी से सामने आएँ तो निर्णय अधिक वास्तविक जानकारी पर लिए जा सकते हैं। संगठन में असहमति के लिए जगह होना उसकी कमजोरी नहीं माना जाना चाहिए।

जयंत चौधरी जी के सामने पुरानी और नई पीढ़ी के बीच तालमेल का प्रश्न भी है। पुराने कार्यकर्ता स्थानीय संबंधों और राजनीतिक अनुभव की समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि किस मुद्दे पर गाँव में क्या प्रतिक्रिया हो सकती है और किन परिवारों से लंबे समय का संपर्क रहा है। युवा कार्यकर्ता नए सवाल, नई तकनीक और अपने समय का अनुभव लेकर आता है। दोनों में से किसी एक को कम महत्व देने से पार्टी अपने ही ज्ञान का एक हिस्सा खो देती है। नई पीढ़ी का नेतृत्व केवल कम उम्र के लोगों को पद देने से नहीं बनता। निर्णय लेने, काम की जिम्मेदारी उठाने और उसके परिणाम का हिसाब देने से नेतृत्व विकसित होता है। किसी युवा को हर बार केवल स्वागत, प्रचार या भीड़ जुटाने का काम मिले तो उसकी भूमिका सीमित रह जाती है। संगठन में उसके अनुभव और सुझावों का उपयोग किस तरह होता है, यह अधिक महत्वपूर्ण है। आज सार्वजनिक संवाद के साधन भी बदल चुके हैं। मोबाइल पर सूचना तेजी से पहुँचती है और किसी नेता की बात गाँव से बाहर दूर तक जा सकती है। इससे नए लोगों को सार्वजनिक चर्चा में जगह मिली है। लेकिन संदेश फैलाने की क्षमता और स्थानीय समस्या समझने की क्षमता अलग हैं। किसी कार्यक्रम की तस्वीर बहुत लोगों तक पहुँच सकती है, जबकि उसके बाद उठी शिकायत पर काम अधूरा रह जाए। राष्ट्रीय लोक दल जैसे ग्रामीण आधार वाले संगठन के लिए इन दोनों तरह के काम का संबंध महत्वपूर्ण है। डिजिटल संवाद पार्टी का परिचय दे सकता है, लेकिन लोगों से नियमित संपर्क का अपना स्थान है। खेत, बाजार, विद्यालय और स्थानीय कार्यालयों में जो अनुभव होता है, वह केवल ऑनलाइन प्रतिक्रिया से पूरी तरह सामने नहीं आता। नई पीढ़ी के नेतृत्व की उपयोगिता इस बात में भी है कि वह दोनों तरह की जानकारी को समझ सके। पार्टी के भीतर महिलाओं की भूमिका का प्रश्न भी संगठन की प्रकृति से जुड़ा है। परिवारों की शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सुरक्षा संबंधी समस्याओं का उनका अनुभव राजनीतिक चर्चा को अधिक व्यापक बना सकता है।

उनकी भागीदारी केवल महिला संबंधी कार्यक्रमों तक सीमित रहे तो संगठन अनेक विषयों पर उनकी समझ से वंचित रह जाता है। जिम्मेदारी और निर्णय में उनकी मौजूदगी से नेतृत्व का दायरा बढ़ता है। सामाजिक विविधता राष्ट्रीय लोक दल के लिए भी एक महत्वपूर्ण कसौटी है। किसान राजनीति के साथ अलग-अलग समुदायों और आर्थिक स्थितियों वाले लोग जुड़े हैं। किसी प्रभावशाली स्थानीय व्यक्ति का साथ उपयोगी हो सकता है, लेकिन पूरे इलाके की राय उसी के माध्यम से समझ लेना पर्याप्त नहीं है। साधारण सदस्य और कम पहुँच वाले परिवार का अनुभव कई बार अलग तस्वीर सामने लाता है। यह अंतर चुनाव के समय अधिक स्पष्ट होता है। किसी टिकट को लेकर नेतृत्व का आकलन और स्थानीय कार्यकर्ताओं की राय अलग हो सकती है। गठबंधन में सीट छोड़ने का फैसला राष्ट्रीय स्तर पर उचित समझा जा सकता है, लेकिन उस क्षेत्र में वर्षों से काम कर रहे कार्यकर्ता के लिए उसे स्वीकार करना कठिन हो सकता है। ऐसे निर्णयों में संवाद और कारणों की स्पष्टता का महत्व बढ़ जाता है। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में 2024 का गठबंधन परिवर्तन और उसके बाद केंद्र सरकार में उनकी भागीदारी संगठन के लिए एक नया दौर लेकर आई। सत्ता में मौजूदगी से कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अपेक्षाएं बढ़ती हैं। लोग चाहते हैं कि उनकी बात अधिक आसानी से सुनी जाए और काम आगे बढ़े। साथ ही सरकारी अधिकारों की सीमाएं समझाना भी नेतृत्व की जिम्मेदारी होती है। मंत्री पद मिलने से हर विभाग का काम किसी एक नेता के हाथ में नहीं आ जाता। कार्यकर्ता इस अंतर को न समझे तो जनता को गलत भरोसा दिया जा सकता है। सही प्रक्रिया बताना, संबंधित कार्यालय तक शिकायत पहुँचाना और उसके बाद स्थिति जानना भी उपयोगी सार्वजनिक काम है। संगठन की विश्वसनीयता कई बार छोटे, निभाए गए वादों से अधिक मजबूत होती है। पार्टी और सरकार की भूमिकाओं का अंतर भी बना रहना चाहिए। सरकारी योजना का लाभ पात्रता के आधार पर मिलता है; पार्टी की सदस्यता उसकी शर्त नहीं हो सकती। राजनीतिक कार्यकर्ता जानकारी देने और प्रक्रिया समझाने में सहायता कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक सुविधा को अपने दल का निजी उपकार बताना नागरिक के अधिकार को छोटा कर देता है। जिम्मेदार संगठन इस सीमा का सम्मान करता है। राष्ट्रीय लोक दल का अधिक व्यापक संगठन बनना उसके परिचित क्षेत्रों से बाहर स्थानीय नेतृत्व के विकास पर भी निर्भर करता है।

चौधरी चरण सिंह जी के प्रति सम्मान या जयंत चौधरी जी की राष्ट्रीय पहचान किसी नए क्षेत्र में परिचय का आधार हो सकती है। उसके बाद उस इलाके के अपने प्रश्नों पर काम करने वाले लोगों की जरूरत होती है। बाहर से मिली पहचान और भीतर से बने संगठन के बीच यही अंतर है। जयंत चौधरी जी के सामने संगठन की यह जिम्मेदारी केवल अगले चुनाव तक सीमित नहीं है। उनके बाद भी काम कर सकने वाले स्थानीय नेताओं और जिम्मेदार कार्यकर्ताओं का तैयार होना पार्टी की लंबी उम्र से जुड़ा है। चौधरी अजीत सिंह जी ने जिस राजनीतिक मंच को बनाए रखा, उसकी अगली मजबूती लोगों को जिम्मेदारी देने और संस्थागत कामकाज विकसित करने में होगी। राष्ट्रीय लोक दल की अगली पीढ़ी का नेतृत्व इसी रोजमर्रा के काम में तैयार होगा। वरिष्ठ कार्यकर्ता का अनुभव और नए सदस्य की पहल एक-दूसरे को जगह दें, तभी संगठन शीर्ष नेतृत्व से आगे अपनी क्षमता बना सकता है।

## अध्याय 24 — उत्तर प्रदेश से आगे: उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों में संभावनाएँ

पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच संबंध प्रदेश की सीमा पर समाप्त नहीं हो जाते। परिवारों का आना-जाना, पढ़ाई, कारोबार, खेती और रोजगार लोगों को एक-दूसरे से जोड़ते हैं। सहारनपुर से हरिद्वार और देहरादून की ओर जाने वाले रास्ते केवल यातायात के रास्ते नहीं हैं। उनके आसपास ऐसे संबंध भी हैं जो वर्षों में बने हैं। फिर भी इन सामाजिक संबंधों को अपने आप राजनीतिक समर्थन मान लेना ठीक नहीं होगा। किसी क्षेत्र से परिचय होना और वहाँ जनता का भरोसा प्राप्त करना अलग बातें हैं। राष्ट्रीय लोक दल का मजबूत आधार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहा है। उत्तराखंड और आसपास के क्षेत्रों के संदर्भ में उसकी संभावनाओं की चर्चा करते समय इस वास्तविकता को ध्यान में रखना चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी की किसान संबंधी सोच का महत्व किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। लेकिन उनके विचारों के प्रति सम्मान और राष्ट्रीय लोक दल की स्थानीय राजनीतिक उपस्थिति को एक ही बात नहीं माना जा सकता। उत्तराखंड को समझने की शुरुआत उसकी भौगोलिक और सामाजिक विविधता से होती है। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के मैदानी इलाकों का जीवन पहाड़ी जिलों से कई मामलों में अलग है। खेती की परिस्थितियाँ, बाजार तक पहुँच और रोजगार के अवसरों में अंतर है। एक ही प्रदेश के भीतर लोगों की प्राथमिकताएँ बदल जाती हैं। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनुभव को ज्यों का त्यों यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। मैदानी क्षेत्रों में खेती और उससे जुड़े कारोबार ग्रामीण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। यहाँ किसान की लागत, सिंचाई, फसल की बिक्री और भुगतान जैसे प्रश्न परिचित हैं। इन विषयों पर चौधरी चरण सिंह जी और चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीति से तुलना की जा सकती है। छोटे उत्पादक की आर्थिक स्थिति और उसकी मेहनत का उचित मूल्य जैसे विचार इन क्षेत्रों को समझने में भी उपयोगी हैं। लेकिन किसान की स्थिति केवल फसल के नाम से तय नहीं होती। जमीन कितनी है, पानी की व्यवस्था क्या है और बाजार कितनी दूर है—इन बातों का असर पड़ता है। किसी परिवार के पास अपनी खेती के साथ नौकरी की आमदनी हो सकती है, जबकि दूसरा पूरी तरह खेत पर निर्भर हो सकता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की चर्चा में इन अंतरों के लिए जगह रखनी होगी।

पहाड़ी क्षेत्रों में दूरी का अर्थ भी बदल जाता है। मानचित्र पर पास दिखाई देने वाला स्थान रोजमर्रा के जीवन में आसानी से पहुँचने योग्य हो, यह आवश्यक नहीं। विद्यालय, अस्पताल, प्रशिक्षण केंद्र और बाजार तक आने-जाने में लगने वाला समय तथा खर्च परिवार के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। किसी सुविधा का जिले में मौजूद होना और उसका गाँव के व्यक्ति के लिए उपयोगी होना अलग स्थितियाँ हैं। जयंत चौधरी जी की शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ी जिम्मेदारियों को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम अच्छा हो, लेकिन वहाँ पहुँचने और रहने का खर्च परिवार की क्षमता से बाहर हो, तो अवसर सीमित रह जाता है। स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षण और उसके बाद काम की वास्तविक संभावना, दोनों महत्वपूर्ण हैं। उत्तराखंड में पर्यटन और तीर्थयात्रा से जुड़े काम भी आजीविका का हिस्सा हैं। इनसे परिवहन, आवास, भोजन और स्थानीय सेवाओं के अवसर बनते हैं। मगर केवल पर्यटकों की संख्या बढ़ने से हर स्थानीय परिवार की आय समान रूप से नहीं बढ़ती। काम का मौसम, मजदूरी, सुरक्षा और वर्ष के बाकी समय की आमदनी भी देखनी पड़ती है। किसी युवा को प्रशिक्षण देने के बाद उसके सामने उपलब्ध काम की पूरी तस्वीर होनी चाहिए। छोटे कारोबार के लिए भी यही बात लागू होती है। स्थानीय उत्पाद बनाने वाला व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है, लेकिन उसे ग्राहक तक पहुँचने, पैकिंग, ढुलाई और भुगतान की व्यवस्था में कठिनाई हो सकती है। ऐसे में केवल उत्पादन बढ़ाने की सलाह पर्याप्त नहीं होती। सामान कहाँ बिकेगा और बेचने के बाद कितना बचेगा, यह भी उतना ही जरूरी सवाल है। इन परिस्थितियों में छोटे उत्पादक के पक्ष में चौधरी चरण सिंह जी की चिंता का एक व्यापक अर्थ सामने आता है। आर्थिक विकास का लाभ उस व्यक्ति तक पहुँचे जो सीमित साधनों से अपना काम करता है। इसमें किसान के साथ कारीगर और छोटा व्यवसायी भी शामिल हो सकता है। हालांकि उनके समय की परिस्थितियाँ और आज की अर्थव्यवस्था अलग हैं, इसलिए विचार की प्रासंगिकता को वर्तमान की जरूरतों के साथ समझना होगा। पहाड़ के संदर्भ में पलायन की चर्चा भी सावधानी से करनी चाहिए। अपने क्षेत्र से बाहर पढ़ने या काम करने जाना हमेशा मजबूरी का परिणाम नहीं होता। यह व्यक्ति की पसंद और आगे बढ़ने की इच्छा भी हो सकती है। कठिनाई तब बढ़ती है जब स्थानीय अवसर इतने कम हों कि रहने का विकल्प ही कमजोर पड़ जाए।

किसी युवा के पास बाहर जाने और अपने इलाके में काम करने, दोनों के सम्मानजनक रास्ते होने चाहिए। यह प्रश्न केवल नौकरी पैदा करने तक सीमित नहीं है। परिवार को स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की पढ़ाई और रोजमर्रा की सुविधाओं पर भी भरोसा चाहिए। रोजगार का एक अवसर मिल जाए, लेकिन बाकी जीवन कठिन बना रहे, तो परिवार का निर्णय फिर भी बाहर जाने का हो सकता है। ग्रामीण विकास के अलग-अलग कामों को साथ देखकर ही इस स्थिति को समझा जा सकता है। पर्यावरण और आजीविका का संबंध उत्तराखंड में विशेष महत्व रखता है। विकास के किसी काम का आकलन करते समय स्थानीय भूगोल, पानी और सुरक्षा की जरूरतों को ध्यान में रखना पड़ता है। थोड़े समय की कमाई के साथ लंबे समय के नुकसान की संभावना को भी समझना जरूरी है। स्थानीय लोगों का अनुभव इस चर्चा में उपयोगी होता है, क्योंकि वे बदलाव को अपने जीवन में महसूस करते हैं। राष्ट्रीय लोक दल की ग्रामीण पृष्ठभूमि इन विषयों से उसका वैचारिक संबंध बनाती है। उत्तराखंड में उसका स्थानीय प्रभाव अलग प्रश्न है। नियमित काम और स्थानीय नेतृत्व की मौजूदगी के प्रमाण के बिना संगठन के व्यापक विस्तार का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। जयंत चौधरी जी की केंद्रीय जिम्मेदारी और राष्ट्रीय लोक दल की राजनीतिक गतिविधि के बीच अंतर भी स्पष्ट रहना चाहिए। मंत्री के रूप में उनका कार्यक्षेत्र पूरे देश के पात्र नागरिकों से जुड़ा है। किसी राज्य में प्रशिक्षण या शिक्षा से संबंधित काम का उद्देश्य वहाँ के लोगों को सुविधा देना है। उसका मूल्यांकन सार्वजनिक लाभ के आधार पर होना चाहिए। उससे किसी दल को कितना राजनीतिक लाभ मिला, यह अलग प्रश्न है। यह अंतर आसपास के दूसरे क्षेत्रों पर भी लागू होता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली से जुड़े ग्रामीण इलाकों के बीच कई सामाजिक तथा आर्थिक संपर्क हैं। फिर भी उनकी स्थानीय राजनीति, खेती की व्यवस्था और रोजगार की परिस्थितियां समान नहीं हैं। किसान की साझा पहचान के भीतर भी क्षेत्र का अपना इतिहास और अनुभव मौजूद रहता है। इसलिए उत्तर प्रदेश से आगे की चर्चा को केवल पार्टी के विस्तार की कहानी बनाना उचित नहीं होगा। अधिक उपयोगी प्रश्न यह है कि किसान, छोटे उत्पादक और ग्रामीण युवा से जुड़े विचार अलग परिस्थितियों में कितने काम के साबित होते हैं। कहीं सिंचाई प्रमुख विषय हो सकता है, कहीं बाजार तक पहुँच और कहीं शिक्षा के बाद स्थानीय रोजगार।

इन अंतरों को स्वीकार करने से ही गंभीर राजनीतिक समझ बनती है। उत्तराखंड इस तरह किसान राजनीति के सामने अलग भूगोल और आजीविका के प्रश्न रखता है। छोटे उत्पादक की चिंता यहाँ भी उपयोगी है, लेकिन उसके उत्तर स्थानीय परिस्थितियों से निकलेंगे। जयंत चौधरी जी के शिक्षा और कौशल संबंधी कार्यक्षेत्र का सार्वजनिक महत्व उन उत्तरों की तलाश में हो सकता है।

## भाग 4 — जयंत चौधरी जी, राष्ट्रीय लोक दल और मुस्लिम समाज

### अध्याय 25 — मुस्लिम समाज को केवल वोट बैंक से आगे समझना

चुनाव की चर्चा में किसी बस्ती का परिचय अक्सर उसकी आबादी से शुरू होता है। कितने मतदाता हैं, किस समुदाय के हैं और पिछली बार किसके साथ गए थे—इन सवालों का अपना चुनावी महत्व है। लेकिन उसी बस्ती में रहने वाले लोगों का जीवन इससे कहीं बड़ा होता है। वहाँ बच्चे पढ़ते हैं, परिवार रोजी कमाते हैं, कारोबार चलता है और बुजुर्ग अपनी अगली पीढ़ी का भविष्य देखते हैं। मुस्लिम समाज को समझने की शुरुआत इसी जीवन से होनी चाहिए। ‘वोट बैंक’ की भाषा सबसे पहले लोगों के बीच के अंतर को छिपाती है। वह मानकर चलती है कि एक धार्मिक पहचान रखने वाले सभी व्यक्ति एक जैसी परिस्थितियों में रहते हैं और एक जैसे राजनीतिक फैसले लेते हैं। जबकि जमीन के मालिक किसान, किराये की दुकान चलाने वाले कारोबारी, मजदूर और विश्वविद्यालय में पढ़ रहे छात्र का अनुभव अलग होता है। उनकी कुछ चिंताएं साझा हो सकती हैं, लेकिन उनकी प्राथमिकताओं में फर्क भी रहता है। इस भाषा में एक और कमी है। उससे मतदाता ऐसा दिखाई देता है मानो उसके अपने विवेक का कोई महत्व न हो। जैसे कोई प्रभावशाली व्यक्ति कहेगा और पूरा समुदाय उसी दिशा में चल देगा। वास्तविक जीवन में परिवार अपने अनुभव, उम्मीदवार के व्यवहार, स्थानीय काम और व्यापक परिस्थितियों को देखकर निर्णय लेते हैं। एक ही घर के भीतर भी राजनीतिक मत अलग हो सकते हैं। एक मोहल्ले में दो परिवार पास-पास रहकर भी बहुत अलग अवसरों के बीच जी सकते हैं। एक परिवार अपने बच्चे को दूसरे शहर भेज सकता है, दूसरे के लिए रोज की बस का किराया कठिन हो सकता है। उनके लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था का अर्थ भी अलग होगा। पहले को बेहतर संस्थान की तलाश है, दूसरे को पढ़ाई जारी रखने का साधन चाहिए। चुनावी भाषा में दोनों एक संख्या बन जाते हैं, जबकि नीति को दोनों की अलग जरूरत पहचाननी पड़ती है। जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ मुस्लिम समाज के संबंध को इसी स्वतंत्रता के साथ समझना होगा।

चौधरी चरण सिंह जी की किसान राजनीति और चौधरी अजीत सिंह जी के नेतृत्व में बने संबंध इस इतिहास का हिस्सा हैं। उनसे परिचय और अपनत्व का आधार मिलता है। लेकिन किसी पीढ़ी का समर्थन अगली पीढ़ी की स्थायी सहमति नहीं बन जाता। हर दौर में नए प्रश्न आते हैं। मुस्लिम किसान के लिए गन्ने का भुगतान और सिंचाई महत्वपूर्ण हैं। कस्बे में काम करने वाले कारीगर को ग्राहक, कच्चा माल और उचित मेहनताना चाहिए। पढ़ाई पूरी कर रहे युवक को नौकरी तथा युवती को अपनी रुचि के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर चाहिए। इन्हें केवल धार्मिक प्रश्न मानना उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन को छोटा कर देता है। इसके साथ पहचान और सुरक्षा की चिंताओं को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोई व्यक्ति अच्छी कमाई करने लगे, तब भी उसके लिए सम्मानजनक व्यवहार और निष्पक्ष प्रशासन का महत्व समाप्त नहीं होता। रोजी-रोटी और बराबरी, दोनों की जरूरत है। इनमें से किसी एक को दूसरे का विकल्प मान लेने से बात अधूरी रह जाती है। धार्मिक पहचान को बिल्कुल अप्रासंगिक मान लेना भी उतनी ही अधूरी समझ होगी। व्यक्ति का नाम, पहनावा या पारिवारिक परंपरा उसके सामाजिक अनुभव का हिस्सा हो सकती है। यदि वह कहीं असमान व्यवहार महसूस करता है, तो उसकी शिकायत को केवल आम आर्थिक समस्या बताकर टालना ठीक नहीं। साथ ही उसके पूरे जीवन को उसी शिकायत में सीमित कर देना भी अन्याय है। वह काम करता है, सीखता है, अपने बच्चों के लिए फैसले लेता है और सार्वजनिक जीवन में अपनी पसंद बनाता है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अर्थ भी कुछ प्रमुख व्यक्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। किसी समुदाय के प्रभावशाली नेता की पहुँच और साधारण परिवार की सुनवाई अलग हो सकती है। मंच पर किसी परिचित चेहरे की मौजूदगी से यह अपने आप सिद्ध नहीं होता कि छोटे कारीगर, मजदूर, महिलाएं और दूर की बस्तियों में रहने वाले लोग भी निर्णय में भागीदार हैं। राष्ट्रीय लोक दल के इतिहास में मुस्लिम नेतृत्व की भागीदारी रही है। उसका महत्व स्वीकार करते हुए यह पूछना भी उचित है कि वह भागीदारी कितनी व्यापक थी और संगठन के भीतर कितने नए लोगों के लिए रास्ते बने। यह प्रश्न किसी एक दल के लिए नहीं, सभी राजनीतिक संगठनों के लिए प्रासंगिक है। जयंत चौधरी जी के शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता से जुड़े कार्यक्षेत्र का मुस्लिम समाज के विभिन्न वर्गों से संबंध यहीं बनता है।

प्रशिक्षण तक पहुँच और उसके बाद काम के अवसर अलग परिवारों पर अलग असर डाल सकते हैं। घोषित कार्यक्रम से वास्तविक लाभ तक की दूरी को समझे बिना किसी समुदाय की प्रगति का दावा अधूरा रहेगा।

लोकतांत्रिक संबंध में समर्थन के साथ सवाल की जगह भी होती है। कोई व्यक्ति किसी नेता का सम्मान करते हुए उसके फैसले से असहमत हो सकता है। वह अपने पुराने राजनीतिक संबंध को बनाए रखते हुए बदलाव की मांग कर सकता है। ऐसी स्वतंत्रता को स्वीकार करने से ही नागरिक और नेतृत्व के बीच परिपक्व संबंध बनता है। यही स्वतंत्रता पुरानी राजनीतिक निष्ठा पर भी लागू होती है। किसी परिवार ने चौधरी चरण सिंह जी या चौधरी अजीत सिंह जी का साथ दिया हो, तो उस स्मृति का अपना भावनात्मक महत्व है। उसके आधार पर नई पीढ़ी के समर्थन को पहले से तय नहीं माना जा सकता। नया मतदाता पुराने संबंध को जान सकता है और अपने अनुभव के आधार पर अलग निष्कर्ष भी निकाल सकता है। जयंत चौधरी जी और राष्ट्रीय लोक दल के साथ उसके संबंध को समझने के लिए यह खुलापन बना रहना चाहिए। मुस्लिम समाज को वोट बैंक से आगे समझने का अर्थ उसे उसके पूरे जीवन के साथ देखना है। उसकी मेहनत, मतभेद, उपलब्धियाँ और चिंताएं—सभी इस तस्वीर में शामिल हैं। तब राजनीतिक चर्चा संख्या से आगे बढ़कर उस सवाल तक पहुँचती है जो हर नागरिक के लिए महत्वपूर्ण है: सार्वजनिक जीवन में मेरी आवाज और मेरे भविष्य की कितनी जगह है?

## अध्याय 26 — शिक्षा और कौशल: मुस्लिम युवाओं के लिए संभावित नीतिगत प्रभाव

किसी युवक के लिए पढ़ाई का अवसर मिलना और उसे पूरा कर पाना दो अलग पड़ाव हैं। प्रवेश के बाद फीस, किताब, सफर और घर के खर्च की जरूरत बनी रहती है। जिस परिवार की आमदनी सीमित हो, वहाँ पढ़ाई जारी रखने का निर्णय बार-बार आर्थिक परिस्थिति से टकराता है। मुस्लिम युवाओं की शिक्षा पर विचार करते समय परिवार और संस्थान के बीच की इस दूरी को समझना होगा। सभी मुस्लिम परिवारों की स्थिति समान नहीं है। किसी घर में उच्च शिक्षा की पुरानी परंपरा हो सकती है और किसी में पहली बार कोई बच्चा कॉलेज पहुँच रहा हो सकता है। पहले परिवार को विषय, संस्थान और आगे की पढ़ाई के बारे में मार्गदर्शन आसानी से मिल सकता है। दूसरे को प्रवेश की प्रक्रिया से लेकर छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण की जानकारी तक सहायता चाहिए हो सकती है। इस अंतर को केवल रुचि या मेहनत की कमी से नहीं समझा जा सकता। शिक्षा और कौशल से जुड़ी जयंत चौधरी जी की जिम्मेदारियाँ ऐसे परिवारों से सीधे संबंध रखती हैं। सार्वजनिक संस्थान सुलभ हों, पढ़ाई बीच में न छूटे और प्रशिक्षण आगे के काम से जुड़े, तो पात्र युवाओं के अवसर बढ़ सकते हैं। यह संभावना संस्थानों के रोजमर्रा के काम पर निर्भर है। प्रशिक्षण का विषय चुनना भी महत्वपूर्ण है। किसी युवक को केवल इसलिए एक पाठ्यक्रम में भेज देना उचित नहीं कि उसमें सीट खाली है। उसकी रुचि, पहले की पढ़ाई और काम की स्थानीय संभावना का मेल होना चाहिए। जो व्यक्ति लेखांकन में रुचि रखता हो, उसके लिए एक रास्ता उपयोगी होगा; जो मशीन या मरम्मत के काम में दक्ष हो, उसके लिए दूसरा। पाठ्यक्रम के नाम से उसके स्तर का पूरा पता नहीं चलता। मशीन पर अभ्यास करने का कितना समय मिला, प्रशिक्षक ने गलती सुधारने में कितनी मदद की और उपकरण इस्तेमाल करने योग्य थे या नहीं—सीखने पर इन बातों का असर पड़ता है। जिस युवक के परिवार में उस काम का अनुभव नहीं है, उसके लिए संस्थान का मार्गदर्शन और भी जरूरी हो जाता है। उसे केवल प्रवेश दिला देना पर्याप्त सहायता नहीं है; पाठ्यक्रम के दौरान आने वाली कठिनाई पर बात करने की जगह भी चाहिए। भाषा कई बार सीखने के बीच अनावश्यक दीवार बन जाती है। व्यक्ति काम समझ सकता है, लेकिन कठिन लिखित निर्देश या अपरिचित तकनीकी शब्द उसे पीछे कर सकते हैं।

स्थानीय भाषा में समझाने के साथ काम में जरूरी शब्दावली सिखाई जाए तो सीखने का रास्ता आसान हो सकता है। उद्देश्य व्यक्ति को आगे बढ़ाना होना चाहिए, उसकी शुरुआती झिझक को स्थायी कमजोरी मान लेना नहीं। स्कूल या कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ चुके युवाओं के लिए वापसी का रास्ता भी जरूरी है। उनके पास काम का अनुभव हो सकता है, लेकिन औपचारिक प्रमाणपत्र न हो। ऐसी स्थिति में पहले से सीखे हुए काम की पहचान और आगे की तैयारी उपयोगी हो सकती है। हर व्यक्ति को शुरुआत की एक ही सीढ़ी पर खड़ा करने से उसके अनुभव की अनदेखी होती है। पढ़ाई और हुनर के बीच रास्ता खुला रहना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कम उम्र में घर चलाने के लिए काम शुरू करने वाला युवक बाद में औपचारिक शिक्षा जारी रखना चाहे तो उसके अनुभव को बाधा नहीं बनना चाहिए। तकनीकी काम सीखने वाली युवती आगे उच्च अध्ययन की इच्छा रख सकती है। कौशल को शिक्षा का स्थायी विकल्प बना देने से कम साधन वाले परिवारों के बच्चों के रास्ते संकुचित हो सकते हैं। बेहतर व्यवस्था उन्हें अपने जीवन के अलग पड़ावों पर फिर सीखने का अवसर देती है।

मुस्लिम युवतियों की जरूरतों पर अलग ध्यान देना भी आवश्यक है। सुरक्षित आवागमन की सुविधा, संस्थान की दूरी और प्रशिक्षण का समय—ये सभी भागीदारी को प्रभावित कर सकते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में कोई इच्छुक युवती अवसर से वंचित रह जाए तो इसे उसकी महत्वाकांक्षा की कमी नहीं कहा जा सकता। उसके सामने उपलब्ध विकल्पों को बेहतर बनाना अधिक उपयोगी होगा। हुनर सीखने के बाद रोजगार तक पहुँच अगला बड़ा प्रश्न है। प्रमाणपत्र मिलने पर भी यदि काम का अवसर न बने तो परिवार की निराशा बढ़ सकती है। प्रशिक्षण देने वाली संस्था और काम देने वाले प्रतिष्ठानों के बीच वास्तविक संबंध होने चाहिए। युवक को काम की शर्तों, संभावित आय और आगे बढ़ने की गुंजाइश की स्पष्ट जानकारी भी मिले। हर प्रशिक्षित व्यक्ति अपना कारोबार शुरू नहीं कर सकता। किसी को नौकरी की जरूरत होगी, किसी को अनुभव और किसी को थोड़ी पूंजी के साथ मार्गदर्शन। उद्यमशीलता को बेरोजगारी का आसान उत्तर मान लेना ठीक नहीं। छोटा काम शुरू करने वाले के लिए ग्राहक, जगह, औजार और शुरुआती महीनों का खर्च उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका हुनर। इन नीतियों के मुस्लिम युवाओं पर असर का अध्ययन नामांकन की संख्या तक सीमित नहीं होना चाहिए।

प्रशिक्षण छोड़ने की वजहों, युवतियों की भागीदारी, मिली हुई नौकरी की गुणवत्ता और आय में वास्तविक बदलाव का भी अध्ययन करना होगा। तभी पता चलेगा कि अवसर किस तक पहुँचा और कौन अब भी पीछे रह गया। नौकरी के परिणाम को देखते समय भी केवल नियुक्ति पत्र पर्याप्त नहीं है। काम कब शुरू हुआ, वेतन नियमित मिला या नहीं और आने-जाने का खर्च घटाने पर कितना बचा, यह परिवार के लिए अधिक सीधा हिसाब है। प्रशिक्षण के बाद कुछ महीनों तक संपर्क बना रहे तो संस्थान को भी अपनी कमी का पता चल सकता है। यदि बहुत-से युवक एक ही वजह से काम छोड़ रहे हों, तो पाठ्यक्रम और कार्यस्थल के बीच संबंध दोबारा देखना पड़ेगा। यह सुधार पूरे प्रशिक्षण तंत्र के लिए उपयोगी होगा। जयंत चौधरी जी के कार्यक्षेत्र से जुड़ी संभावनाओं को इसी आधार पर समझा जा सकता है। अच्छी सार्वजनिक शिक्षा और उपयोगी प्रशिक्षण अलग-अलग समुदायों के युवाओं को लाभ पहुँचा सकते हैं। मुस्लिम युवाओं के लिए उनका महत्व तभी ठोस होगा जब व्यवस्था उनकी वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए काम करे और अवसर तक पहुँच में मौजूद बाधाएं कम हों।

## अध्याय 27 — रोजगार, छोटे कारोबार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था

छोटा कारोबार अक्सर घर और काम की दुनिया को एक साथ जोड़ता है। दुकान की बिक्री से भोजन का खर्च निकलता है, उसी से बच्चे की फीस जाती है और जरूरत पड़ने पर उसी पूंजी से इलाज भी कराया जाता है। ऐसे परिवार के लिए कारोबार में आई रुकावट व्यक्तिगत जीवन में तुरंत दिखाई देती है। महीना खराब जाए तो उसका असर पूरे घर पर पड़ता है। मुस्लिम समाज के आर्थिक जीवन पर चर्चा करते समय छोटे कारोबार और स्वरोजगार को समझना उपयोगी है, लेकिन पूरे समुदाय को कुछ परंपरागत पेशों में बांध देना उचित नहीं होगा। उसके भीतर किसान, वेतनभोगी कर्मचारी, पेशेवर, मजदूर और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोग हैं। उनकी परिस्थितियों का अध्ययन अलग-अलग करना होगा। छोटे कारोबारी की पहली कठिनाई कई बार पूंजी की होती है। काम आता है, ग्राहक भी हैं, लेकिन पर्याप्त माल खरीदने या समय पर बड़ा ऑर्डर पूरा करने के लिए रकम नहीं है। दूसरी ओर ग्राहक से भुगतान देर से मिले तो पहले से लगा पैसा फंस सकता है। इस स्थिति में बिक्री अच्छी दिखाई देने पर भी कारोबार दबाव में रह सकता है। कौशल और उद्यमशीलता का प्रश्न इसी जगह रोजमर्रा के आर्थिक जीवन से मिलता है। बेहतर काम करना उपयोगी है, लेकिन लागत और बिक्री का हिसाब समझना भी जरूरी है। कितना माल उधार दिया जा सकता है, किस खर्च को पहले पूरा करना है और उपकरण बदलने के लिए कितना बचाना होगा—इन फैसलों से छोटे व्यवसाय की निरंतरता तय होती है। छोटे व्यवसाय में निजी और कारोबारी पैसे का हिसाब अक्सर साथ चलता है। बीमारी आने पर दुकान की पूंजी घर में लग सकती है; अचानक बड़ा ऑर्डर मिले तो घर की बचत माल खरीदने में चली जाती है। इस स्थिति में केवल बिक्री बढ़ाना काफी नहीं होता। कारोबारी को यह भी समझना पड़ता है कि उसके काम में कितनी रकम लगातार लगी रहनी चाहिए और कितना पैसा वह घर ले जा सकता है। सहज भाषा में दिया गया लेखांकन का प्रशिक्षण ऐसी रोजमर्रा की उलझन कम कर सकता है। जयंत चौधरी जी की संबंधित प्रशासनिक जिम्मेदारी में ऐसे लोगों के लिए सीखने और आगे बढ़ने के अवसरों की गुंजाइश है। हालांकि किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम से छोटे व्यवसाय की सभी समस्याएं हल नहीं होतीं। वित्त, बिजली, स्थान, परिवहन और बाजार से जुड़े विषय भी सामने आते हैं। अलग-अलग विभागों की सुविधाएं व्यक्ति के लिए कितनी आसानी से एक साथ उपलब्ध होती हैं, यह महत्वपूर्ण है।

डिजिटल साधन कुछ काम आसान कर सकते हैं। ग्राहक को उत्पाद दिखाना, भुगतान प्राप्त करना और बिक्री का रिकॉर्ड रखना अधिक सुविधाजनक हो सकता है। लेकिन इसके साथ शुल्क, धोखाधड़ी, गलत लेन-देन और निजी जानकारी की सुरक्षा समझना भी जरूरी है। केवल किसी मंच पर खाता बन जाने को कारोबारी सफलता नहीं कहा जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे कारोबार की स्थिति खेती से भी जुड़ती है। फसल का भुगतान आने पर बाजार में खरीद बढ़ सकती है। किसान की आमदनी रुकने पर दुकानदार और सेवा देने वाले व्यक्ति को भी उधार बढ़ाना पड़ सकता है। इसलिए गाँव के छोटे व्यवसाय और किसान की आर्थिक सुरक्षा को पूरी तरह अलग नहीं देखा जा सकता।

कारीगर के लिए अपने हुनर का उचित मूल्य मिलना महत्वपूर्ण है। कई बार तैयार माल की अंतिम कीमत अच्छी होती है, लेकिन उसे बनाने वाले की आय सीमित रह जाती है। उत्पादन, बिक्री और बीच के खर्चों का संबंध समझे बिना केवल बाजार बढ़ने को सबकी समृद्धि मान लेना अधूरा होगा। काम करने वाले की हिस्सेदारी भी देखनी होगी। बाजार तक सीधी पहुँच की चर्चा में भी पूरा खर्च देखना पड़ता है। माल की तस्वीर भेज देना आसान है, लेकिन पैकिंग, ढुलाई, वापसी और भुगतान में लगने वाला समय छोटे उत्पादक पर नया बोझ डाल सकता है। बीच के व्यापारी को हटाने से हर परिस्थिति में लाभ बढ़ेगा, ऐसा मान लेना जल्दबाजी है। कहीं वही व्यापारी माल एकत्र करता है, खरीदार ढूँढ़ता है और भुगतान का जोखिम उठाता है। बदलाव का फायदा तभी होगा जब उत्पादक इन कामों की लागत समझकर अपना रास्ता चुने। सहयोग के छोटे रूप कुछ स्थितियों में उपयोगी हो सकते हैं। औजार साझा करना, सामूहिक ढुलाई या एक साथ कच्चा माल खरीदना खर्च घटाने की संभावना दे सकता है। मगर ऐसी व्यवस्था का सफल होना पारदर्शी हिसाब और भरोसे पर निर्भर करता है। बिना तैयारी के बनाए गए समूहों में जिम्मेदारी और लाभ के विवाद भी पैदा हो सकते हैं। कामगार की स्थिति इस आर्थिक चर्चा का जरूरी हिस्सा है। छोटा प्रतिष्ठान खुद कठिनाई में हो सकता है, फिर भी वहाँ काम करने वाले व्यक्ति का समय, मेहनताना और सुरक्षा महत्व रखते हैं। रोजगार की संख्या के साथ उसकी गुणवत्ता देखनी होगी। नियमित काम के बिना या लंबे समय तक रुके वेतन के साथ परिवार की आर्थिक असुरक्षा बनी रहती है। महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू उत्पादन और छोटे काम में भी श्रम का सही मूल्य समझना आवश्यक है।

घर से काम होने के कारण उसका खर्च या समय शून्य नहीं हो जाता। सामग्री, बिजली, उपकरण और मेहनत की कीमत होती है। कम दाम पर मिलने वाला ऑर्डर कभी-कभी अधिक काम के बावजूद बहुत कम आय छोड़ता है। किसी घर में सिलाई या दूसरा उत्पादन बढ़े तो परिवार की कमाई बढ़ सकती है, लेकिन काम करने वाली महिला के हिस्से में अतिरिक्त समय का बोझ भी आ सकता है। घरेलू जिम्मेदारियां वैसी ही रहें और उत्पादन का काम उनके ऊपर जुड़ जाए, तो बढ़े हुए कारोबार का मूल्यांकन केवल आय से नहीं किया जा सकता। भुगतान किसके हाथ में आता है और उससे जुड़े फैसले कौन लेता है, यह भी महत्व रखता है। आर्थिक अवसर में व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके श्रम की पहचान दोनों शामिल हैं।

छोटे उत्पादक की स्वतंत्रता का प्रश्न इस तरह कारोबार की साधारण जरूरतों में लौटता है। चौधरी चरण सिंह जी की आर्थिक परंपरा और जयंत चौधरी जी की उद्यमशीलता संबंधी जिम्मेदारी के बीच यह एक साझा विषय है। इसका अर्थ उस व्यक्ति के काम में खुलता है जो सीमित पूंजी से अपना परिवार चलाता है और अगले महीने के लिए कुछ भरोसा चाहता है।

## अध्याय 28 — मुस्लिम किसान और राष्ट्रीय लोक दल की किसान राजनीति

मुस्लिम किसान की पहचान में धर्म के साथ जमीन, श्रम और स्थानीय समाज से उसके संबंध भी शामिल होते हैं। उसकी खेती मौसम से प्रभावित होती है, खर्च बाजार से तय होते हैं और आमदनी बिक्री तथा भुगतान पर निर्भर करती है। दूसरे किसानों के साथ उसके अनेक आर्थिक प्रश्न साझा होते हैं। लेकिन साझा परेशानी के भीतर उसके अपने सामाजिक अनुभव भी मौजूद रहते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की किसान राजनीति ने खेती करने वाले व्यक्ति को एक व्यापक राजनीतिक पहचान दी। इस पहचान में विभिन्न समुदायों के लोगों के साथ आने की संभावना थी। चौधरी अजीत सिंह जी के दौर में राष्ट्रीय लोक दल और किसान आंदोलनों के भीतर मुस्लिम नेतृत्व तथा किसानों की भागीदारी इसी इतिहास का हिस्सा रही। यह संबंध केवल नेताओं की मुलाकातों से नहीं बना था। गाँव में साथ रहना, बाजार और मंडी में आना-जाना, खेती की समान समस्याएं और स्थानीय संपर्क उसका आधार थे। फिर भी इन संबंधों को हमेशा सहज और बराबरी वाला मान लेना ठीक नहीं होगा। जमीन, आर्थिक प्रभाव और सामाजिक स्थिति के अंतर गाँव में भी मौजूद रहते हैं। मुस्लिम किसानों के भीतर भी पर्याप्त विविधता है। किसी के पास बड़ी जोत हो सकती है और कोई छोटी जमीन पर परिवार चला रहा हो सकता है। कुछ परिवार खेती के साथ दूसरा काम करते हैं। खेतिहर मजदूर या बटाईदार की जरूरत जमीन के मालिक से अलग हो सकती है। इसलिए किसान राजनीति में उनकी बात सुनते समय एक ही अनुभव को पूरे समाज का अनुभव नहीं मानना चाहिए। छोटी खेती में नकदी की जरूरत बहुत तत्काल हो सकती है। बोआई के समय बीज और खाद खरीदनी है, लेकिन पिछली फसल का पैसा नहीं आया। ऐसे में किसान उपलब्ध उधार की शर्त मानने को मजबूर हो सकता है। उसकी धार्मिक पहचान से यह हिसाब नहीं बदलता, हालांकि स्थानीय संपर्क और सामाजिक स्थिति सहायता पाने के रास्ते को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समान कृषि समस्या और अलग सामाजिक अनुभव को साथ देखने से ही मुस्लिम किसान की परिस्थिति की पूरी तस्वीर बनती है। गन्ने का भुगतान और कृषि मूल्य जैसे प्रश्न साझा आंदोलन का आधार बन सकते हैं। 2009 के आंदोलन में विभिन्न संगठनों का साथ आना इसी संभावना को दिखाता है।

चौधरी अजीत सिंह जी ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऐसा सहयोग बताता है कि आर्थिक मुद्दों पर मिलकर दबाव बनाया जा सकता है, लेकिन उससे सभी सामाजिक मतभेद अपने आप समाप्त नहीं होते।

मुस्लिम किसान के लिए खेत तक निर्भय होकर पहुँचना, अपनी उपज बेच पाना और स्थानीय प्रशासन में भरोसा होना भी जरूरी है। सामाजिक तनाव बढ़ने पर खेती और बाजार के सामान्य संबंध प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए किसान की आर्थिक सुरक्षा और उसकी नागरिक सुरक्षा को अलग-अलग विषय मानकर नहीं छोड़ा जा सकता। बटाई या किराये की जमीन पर काम करने वाले व्यक्ति का अनुभव इसमें एक और परत जोड़ता है। फसल का जोखिम वह उठाता है, लेकिन हर सरकारी या संस्थागत प्रक्रिया में उसकी पहचान जमीन के स्वामी जैसी नहीं होती। किसी सुविधा के लिए कौन-से दस्तावेज मांगे जाते हैं और वास्तविक खेती करने वाला व्यक्ति उन्हें जुटा सकता है या नहीं, यह पहुँच का व्यावहारिक प्रश्न है। भूमि संबंधों की इस भिन्नता को देखे बिना किसान परिवारों पर किसी नीति का एक जैसा असर मानना गलत होगा।

2013 की हिंसा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस संबंध को गंभीर चोट पहुँचाई। विस्थापित परिवारों के लिए घर, काम और परिचित सामाजिक वातावरण छूटने का प्रश्न था। बाद में किसान आंदोलन के माध्यम से कुछ पुराने संपर्क फिर बने, लेकिन उस मेल-मिलाप को सभी पीड़ितों की समस्या के समाधान का प्रमाण मानना उचित नहीं होगा। जयंत चौधरी जी को किसान राजनीति की यही मिली-जुली विरासत मिली है। उसमें साथ काम करने का इतिहास है और विश्वास टूटने का अनुभव भी। आगे की सार्वजनिक भूमिका को समझते समय दोनों को जगह देनी होगी। साझा आर्थिक मांगों के साथ लोगों की अपनी चिंताओं को सुना जाना आवश्यक है। मुस्लिम किसानों की भागीदारी का अर्थ केवल सभा में मौजूदगी नहीं है। उनकी स्थानीय समस्याएं संगठन की प्राथमिकताओं तक पहुँचें और वे बातचीत में अपनी राय रख सकें, तभी प्रतिनिधित्व गहरा होता है। प्रभावशाली व्यक्ति की पहुँच से अलग साधारण किसान की सुनवाई की स्थिति भी देखनी होगी। सरकारी सहायता के मामले में पात्रता और निष्पक्ष व्यवहार का महत्व सबसे ऊपर है। खेती से संबंधित सुविधा किसी राजनीतिक समर्थन का पुरस्कार नहीं है।

किसान को जानकारी मिले, प्रक्रिया समझ में आए और शिकायत का रास्ता उपलब्ध हो—इन बातों से व्यवस्था में भरोसा बनता है। खेती के साथ पशुपालन, मजदूरी या छोटा काम करने वाले परिवार की सालाना आय को भी एक ही फसल से नहीं समझा जा सकता। एक साधन कमजोर पड़े तो दूसरा सहारा दे सकता है, लेकिन बीमारी या सामाजिक तनाव एक साथ कई रास्ते रोक सकते हैं। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उपयोगी अर्थ ऐसी जुड़ी हुई कठिनाइयों को सामने लाना है। राष्ट्रीय लोक दल के किसान संबंधी परिचय की चर्चा में यह देखने की जगह होनी चाहिए कि स्थानीय शिकायत खेत के बाहर घर और आजीविका तक कितनी समझी जाती है।

राष्ट्रीय लोक दल और मुस्लिम किसान के संबंध का मूल्यांकन इसलिए दो आधारों पर किया जा सकता है। पहला, खेती और ग्रामीण आय के प्रश्नों पर पार्टी का वास्तविक काम। दूसरा, संगठन और सार्वजनिक जीवन में बराबरी तथा सम्मान का अनुभव। किसी एक की मौजूदगी दूसरे की कमी को पूरी तरह नहीं भर सकती। साझा किसान मंच में अलग अनुभवों की जगह बनी रहे तो सहयोग अधिक गहरा हो सकता है। जयंत चौधरी जी को मिली विरासत में आर्थिक मांगों के साथ सुनवाई और सम्मान का यही प्रश्न जुड़ा हुआ है।

## अध्याय 29 — पसमांदा समाज और राजनीतिक प्रतिनिधित्व

मुस्लिम समाज के बारे में बात करते समय अक्सर उसके भीतर के सामाजिक और आर्थिक अंतर पीछे छूट जाते हैं। कुछ प्रसिद्ध नाम पूरे समुदाय के प्रतिनिधि मान लिए जाते हैं, जबकि अनेक परिवार अपने श्रम और सीमित साधनों के सहारे जीवन चलाते रहते हैं। पसमांदा प्रश्न इसी अनदेखे अंतर को सामने लाता है। 'पसमांदा' का आशय पीछे रह गए लोगों से है। सार्वजनिक चर्चा में यह शब्द मुस्लिम समाज के भीतर सामाजिक रूप से वंचित और पिछड़े समूहों की पहचान तथा उनके अधिकारों से जुड़ा है। इसे केवल कम आय का दूसरा नाम मान लेना पर्याप्त नहीं होगा। सामाजिक हैसियत, परंपरागत पेशे, शिक्षा और सत्ता तक पहुँच के अंतर भी इस प्रश्न में शामिल हैं। हर आर्थिक रूप से कमजोर मुस्लिम परिवार का सामाजिक अनुभव एक जैसा नहीं होता। इसी तरह किसी व्यक्ति की आमदनी बढ़ जाने से पुराने सामाजिक संबंधों का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाए, यह भी आवश्यक नहीं। इसलिए पसमांदा समाज पर विचार करते समय गरीबी और सामाजिक पदानुक्रम के संबंध को समझना पड़ता है। सामाजिक पिछड़ापन हमेशा बाहर से दिखाई नहीं देता। किसी व्यक्ति का हुनर बाजार में उपयोगी हो सकता है, फिर भी उसकी बिरादरी को कम सम्मान की नजर से देखा जाए। बच्चे को पारिवारिक काम सीखने का अवसर मिले, लेकिन दूसरे पेशे में जाने के लिए मार्गदर्शन न मिले। ऐसी परिस्थितियों में केवल आमदनी बढ़ने की बात से समस्या का पूरा उत्तर नहीं मिलता। शिक्षा के रास्ते, सामाजिक सम्मान और अपनी योग्यता के अनुसार आगे बढ़ने की स्वतंत्रता भी चाहिए। राजनीति में पहली कठिनाई दिखाई देने की होती है। सार्वजनिक मंच पर समुदाय की बात कौन रखता है? संगठन की बैठक में किसकी राय सुनी जाती है? स्थानीय समस्या बताने के लिए किसके पास पहुँच है? इन प्रश्नों से पता चलता है कि प्रतिनिधित्व केवल धार्मिक पहचान का नहीं, समुदाय के भीतर शक्ति के बंटवारे का भी विषय है। किसी दल में कुछ मुस्लिम पदाधिकारी होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि पसमांदा समाज की पर्याप्त भागीदारी हो गई। उसी तरह किसी व्यक्ति को उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण पद दे देना भी पूरी भागीदारी का प्रमाण नहीं है। उसके पास काम करने की जिम्मेदारी, निर्णय की गुंजाइश और अपने अनुभव के आधार पर विषय उठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए।

राष्ट्रीय लोक दल की किसान और कामगार से जुड़ी राजनीतिक परंपरा के संदर्भ में यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। ग्रामीण समाज की आर्थिक बात करते समय कारीगर, भूमिहीन मजदूर और सेवा से जुड़े परिवारों का अनुभव सामने आना चाहिए। उनकी समस्या बड़े किसान या प्रभावशाली कारोबारी की समस्या से अलग हो सकती है। मसलन, भूमि के मूल्य में वृद्धि से मालिक की संपत्ति बढ़ सकती है, लेकिन उसी इलाके में रहने वाले मजदूर के लिए किराया और जीवनयापन महंगा हो सकता है। किसी आर्थिक बदलाव को सबके लिए समान लाभ मान लेने से कमजोर वर्ग की स्थिति छूट जाती है। राजनीतिक चर्चा में ऐसे अंतर सामने आएँ, तभी नीति का असर ठीक से समझा जा सकता है। इसलिए किसी वंचित समूह के एक सफल व्यक्ति की कहानी को पूरे समूह की स्थिति का प्रमाण नहीं माना जा सकता। उसकी उपलब्धि महत्वपूर्ण है और दूसरों को प्रेरणा दे सकती है, लेकिन बाकी परिवारों की जमीन, पढ़ाई और रोजगार की हालत अलग से सामने आनी चाहिए। इसी तरह केवल कठिनाइयों की चर्चा करके लोगों की अपनी मेहनत और उपलब्धियों को भुला देना भी अधूरा चित्र है। पसमांदा समाज को समझने में अभाव के साथ उसकी पहल और अनुभव की जगह बनी रहनी चाहिए।

शिक्षा और कौशल यहाँ उपयोगी अवसर दे सकते हैं। लेकिन प्रशिक्षण को केवल परंपरागत पेशे तक सीमित करना नई पीढ़ी की पसंद कम कर सकता है। कोई अपने पारिवारिक हुनर को बेहतर बनाना चाहे तो उसे सहायता मिले। कोई दूसरा क्षेत्र चुनना चाहे तो उसके लिए भी रास्ता हो। सामाजिक प्रगति में पेशा चुनने की स्वतंत्रता का अपना महत्व है। जयंत चौधरी जी की संबंधित जिम्मेदारियों का अध्ययन करते समय देखा जा सकता है कि अवसर कम पहुँच वाले परिवारों तक कितने प्रभावी ढंग से जाते हैं। कार्यक्रम में प्रवेश, प्रशिक्षण पूरा करना और आगे काम मिलना, तीनों स्तरों पर बाधाएं अलग हो सकती हैं। केवल कुल संख्या से सामाजिक पहुँच का पूरा पता नहीं चलता। पसमांदा महिलाओं के अनुभव में आर्थिक स्थिति, सामाजिक पृष्ठभूमि और लैंगिक असमानता एक साथ प्रभाव डाल सकते हैं। उनके श्रम की पहचान, शिक्षा और स्वतंत्र सार्वजनिक भागीदारी का प्रश्न अलग से सुना जाना चाहिए। परिवार या समुदाय के किसी पुरुष प्रतिनिधि की राय से महिलाओं का पूरा अनुभव सामने नहीं आता। प्रतिनिधित्व का विस्तार तभी महसूस होता है जब नए व्यक्ति को बोलने का अवसर मिलने के बाद उसका विषय चर्चा में ठहरता भी है।

कारीगर अपनी समस्या रखे और बैठक फिर केवल चुनाव की बात पर लौट जाए, तो उसकी उपस्थिति का असर सीमित रह जाता है। सामाजिक पहचान के साथ विषय की समझ को महत्व देने से चर्चा अधिक उपयोगी बन सकती है। किसी समूह का नाम मंच पर लेना आसान है; उसके अनुभव को निर्णय की भाषा में जगह देना अधिक धैर्य और तैयारी मांगता है।

इस विषय को किसी राजनीतिक दल के लिए समर्थन जुटाने की श्रेणी तक सीमित कर देना उसके मूल अर्थ को कमजोर कर देगा। पसमांदा समाज के लोग अपने अधिकार, सम्मान और अवसर के प्रश्न रखते हैं। उनकी राजनीतिक पसंद स्वतंत्र है और उनके बीच भी मतभेद हो सकते हैं। पसमांदा समाज की अपनी आवाज, संगठन में जिम्मेदारी और नीतिगत चर्चा में भागीदारी इस प्रश्न को ठोस रूप देती है। राष्ट्रीय लोक दल सहित किसी भी दल के साथ उसके संबंध को इन्हीं अनुभवों में पढ़ना होगा। केवल नाम का उल्लेख उस जगह की भरपाई नहीं करता जहाँ व्यक्ति अपना विषय स्वयं रख सके।

## अध्याय 30 – मुस्लिम महिलाओं और युवाओं की राजनीतिक भागीदारी

किसी सार्वजनिक बैठक में किसी समुदाय की ओर से बोलने वाले लोग अक्सर उसके सभी अनुभवों का प्रतिनिधित्व नहीं करते। घर की जिम्मेदारी संभालने वाली महिला, पढ़ाई कर रही युवती और काम तलाशता युवक अपनी परिस्थितियों को अलग ढंग से देखते हैं। उनकी बात सीधे सुने बिना समुदाय की पूरी तस्वीर नहीं बन सकती। मुस्लिम महिलाओं के जीवन के बारे में एक जैसी धारणाएं बना लेना उचित नहीं है। परिवार, शिक्षा, आर्थिक स्थिति और स्थानीय वातावरण के अनुसार उनके अनुभव बदलते हैं। कोई पेशेवर काम करती है, कोई पढ़ रही है, कोई घर और आजीविका की दोहरी जिम्मेदारी निभाती है। राजनीतिक भागीदारी की चर्चा में इस विविधता को जगह मिलनी चाहिए। भागीदारी का अर्थ चुनाव लड़ना ही नहीं है। स्थानीय सुविधा पर सवाल उठाना, सार्वजनिक बैठक में राय रखना, संगठन का काम संभालना और किसी सामुदायिक समस्या के समाधान में शामिल होना भी राजनीतिक जीवन का हिस्सा है। इन रास्तों से व्यक्ति अपने इलाके के निर्णयों में जगह बनाता है। महिलाओं के लिए समय और आवागमन की परिस्थितियां इस भागीदारी को प्रभावित कर सकती हैं। बैठक का समय ऐसा हो कि घर और काम की जिम्मेदारियों के कारण पहुँचना कठिन हो, तो इच्छा के बावजूद भागीदारी कम रह सकती है। किसी सार्वजनिक भूमिका में सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण भी महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक काम का समय निकालना अपने आप में संसाधन है। घर में बच्चे या बुजुर्ग की देखभाल हो तो बैठक में पहुँचने के लिए किसी दूसरे की मदद चाहिए। बाहर काम करने वाली महिला को छुट्टी या काम का समय बदलना पड़ सकता है। यह खर्च राजनीतिक पदों की सूची में दिखाई नहीं देता, लेकिन भागीदारी के मौके तय करता है। महिलाओं की कम मौजूदगी का कारण केवल रुचि का अभाव मान लेने से ऐसी व्यावहारिक कठिनाइयाँ अनदेखी रह जाती हैं। राजनीतिक संगठन की भाषा और व्यवहार से भी फर्क पड़ता है। किसी महिला की राय को गंभीरता से लिया जाता है या उसे केवल औपचारिक उपस्थिति माना जाता है, यह अनुभव उसके आगे बने रहने को प्रभावित करता है। जिम्मेदारी मिले तो उसके साथ अधिकार और आवश्यक सहयोग भी होना चाहिए। युवाओं के सामने दूसरी तरह की चुनौतियाँ हो सकती हैं।

सार्वजनिक काम में समय देने के साथ उन्हें पढ़ाई और रोजगार की चिंता भी रहती है। राजनीति में सक्रिय रहने का खर्च किस तरह निकलेगा, यह साधारण परिवार के युवक के लिए वास्तविक प्रश्न है। केवल वही लोग आगे बढ़ें जिनके पास समय और पैसा पहले से है, तो प्रतिनिधित्व सीमित रह जाता है। नई पीढ़ी को केवल प्रचार का साधन समझना भी उसकी भूमिका को छोटा करना है। सोशल मीडिया का काम उपयोगी हो सकता है, लेकिन युवाओं की क्षमता उससे आगे है। वे स्थानीय जरूरतें पहचान सकते हैं, सार्वजनिक सेवाओं की जानकारी समझ सकते हैं और अपने अनुभव के आधार पर नए सवाल रख सकते हैं। युवाओं को सार्वजनिक विषय समझने का अवसर भी चाहिए। किसी स्थानीय काम के लिए धन कहाँ से आता है, जिम्मेदार विभाग कौन है और प्रस्ताव से काम पूरा होने तक कौन-से पड़ाव हैं—यह जानकारी अनुभव से बनती है। संगठन यदि नए सदस्य को केवल नारा और प्रचार सिखाए, तो उसकी राजनीतिक तैयारी अधूरी रहती है। नागरिक जरूरत को समझना, विभिन्न पक्षों की बात सुनना और निभाए जा सकने वाले वादे करना नेतृत्व के ऐसे गुण हैं जो धीरे-धीरे विकसित होते हैं।

जयंत चौधरी जी की राजनीति में नई पीढ़ी का विषय उनके स्वयं के नेतृत्व से भी जुड़ा है। उन्हें युवा नेता के रूप में मिली पहचान का व्यापक अर्थ तभी होगा जब संगठन में दूसरे युवाओं के लिए भी जिम्मेदारी और आगे बढ़ने की जगह दिखाई दे। यह बात विभिन्न सामाजिक पृष्ठभूमियों के युवाओं पर समान रूप से लागू होती है। मुस्लिम युवक और युवती की भागीदारी को केवल मुस्लिम मुद्दों तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वे खेती, पर्यावरण, शिक्षा, परिवहन और स्थानीय विकास पर भी अपना अनुभव रखते हैं। नागरिक की भूमिका को उसकी धार्मिक पहचान तक सीमित कर देने से सार्वजनिक चर्चा संकुचित हो जाती है। डिजिटल माध्यम कुछ नई जगह खोलते हैं। अपनी बात रखने और जानकारी साझा करने का अवसर मिलता है। इसके साथ अपमानजनक टिप्पणियाँ, अफवाह और निजी जीवन पर हमले भी किसी को सार्वजनिक चर्चा से दूर कर सकते हैं। इसलिए ऑनलाइन पहुँच को वास्तविक और सुरक्षित भागीदारी के बराबर नहीं मानना चाहिए। परिवार और समुदाय के भीतर भी युवा की स्वतंत्र राय का सम्मान महत्वपूर्ण है। पुराने राजनीतिक संबंध उपयोगी अनुभव देते हैं, लेकिन नई पीढ़ी को अपने प्रश्न पूछने का अधिकार है। वह सम्मान के साथ असहमत हो सकती है।

इस असहमति को अवज्ञा मानने के बजाय संवाद का अवसर माना जाए तो संबंध अधिक परिपक्व बनते हैं। मतभेद की जगह महिलाओं के लिए भी उतनी ही जरूरी है। किसी विषय पर उनकी राय परिवार, समुदाय या पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति की राय से अलग हो सकती है। ऐसी राय को सुनना सार्वजनिक जीवन में उनकी स्वतंत्र उपस्थिति स्वीकार करना है। साथ ही किसी एक महिला की बात को सभी महिलाओं का मत मान लेना भी ठीक नहीं। उम्र, शिक्षा, आर्थिक परिस्थिति और काम के अनुभव से उनके बीच अंतर आते हैं। अधिक आवाजें सामने आने पर ही राजनीतिक चर्चा इस विविधता को समझ सकती है। महिलाओं और युवाओं की आवाज तब टिकती है जब उसका असर सार्वजनिक काम में दिखाई दे। वे विषय रखें, निर्णय में शामिल हों और अपने सुझाव पर उत्तर पा सकें। राष्ट्रीय लोक दल में नई पीढ़ी के नेतृत्व की चर्चा का अर्थ भी इन्हीं रोजमर्रा के अनुभवों से बनेगा।

## अध्याय 31 – पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सामाजिक भाईचारा

भाईचारे की पहचान बड़े मंच पर कही गई बातों से पहले रोजमर्रा के व्यवहार में होती है। पड़ोसी की जरूरत पर कौन पहुँचता है, बाजार में लेन-देन कितना सहज है और बच्चे किस वातावरण में बड़े होते हैं—इन बातों से समाज का रिश्ता बनता है। किसी संकट में ये संबंध सहारा बन सकते हैं। तनाव बढ़ने पर इन्हीं की परीक्षा होती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साझा ग्रामीण जीवन और किसान आंदोलनों ने अलग-अलग समुदायों को साथ आने के अवसर दिए। चौधरी चरण सिंह जी की किसान राजनीति और बाद के आंदोलनों में आर्थिक प्रश्नों पर सहयोग का इतिहास मौजूद है। चौधरी अजीत सिंह जी की राजनीतिक यात्रा भी इन संबंधों से जुड़ी रही। इस इतिहास को याद करना उपयोगी है, लेकिन उसे लगातार समानता और सौहार्द की कहानी बना देना उचित नहीं होगा। गाँव में आर्थिक निर्भरता के साथ शक्ति के अंतर भी होते हैं। किसी प्रभावशाली समूह के संरक्षण में रहना और बराबरी के साथ पड़ोसी होना अलग स्थितियाँ हैं। टिकाऊ भाईचारा सम्मान और अधिकार के साथ जुड़ा है। 2013 की हिंसा ने इस क्षेत्र के सामाजिक जीवन को गहरी चोट पहुँचाई। मौत और विस्थापन के साथ लोगों का एक-दूसरे पर विश्वास प्रभावित हुआ। घर छोड़ने वाले परिवारों के लिए नुकसान केवल संपत्ति का नहीं था। रोजी-रोटी के रास्ते, बच्चों की पढ़ाई और परिचित वातावरण भी छूट सकता था। ऐसे अनुभव के बाद मेल-मिलाप की चर्चा में पीड़ित की आवाज केंद्र में रहनी चाहिए। बाहर का व्यक्ति जल्दी आगे बढ़ने की बात कर सकता है, लेकिन जिसने नुकसान सहा है, उसके लिए सुरक्षा और न्याय का प्रश्न बना रहता है। उसके दुख को पीछे छोड़ देने की शर्त पर बना समझौता भरोसे की मजबूत बुनियाद नहीं बन सकता। विस्थापन के बाद बस जाने का अर्थ पुरानी जिंदगी लौट आना नहीं होता। नए स्थान पर रहने की जगह मिल जाए, फिर भी काम, स्कूल और परिचित सहारे दोबारा बनाने पड़ते हैं। परिवार के सदस्य इस परिवर्तन को अलग तरह से महसूस करते हैं। बच्चे के लिए पढ़ाई का टूटना बड़ी बात हो सकती है, बुजुर्ग के लिए अपने पुराने पड़ोस से दूर होना। सामाजिक संबंधों की बहाली पर बात करते समय इन अनुभवों को किसी राजनीतिक बैठक की सफलता में समेटा नहीं जा सकता। साथ ही पूरे समुदायों को एक जैसा मानकर दोष देना भी संबंधों को और कठिन बनाता है। जिम्मेदारी व्यक्तियों और संस्थाओं के काम के आधार पर तय होती है।

किसी गाँव या धर्म के प्रत्येक व्यक्ति को हिंसा का समर्थक मान लेना तथ्य और न्याय, दोनों के विरुद्ध है।

बाद के किसान आंदोलन में पुराने सहयोगियों के बीच संवाद के अवसर बने। श्री गुलाम मोहम्मद जौला जी और टिकैत परिवार के बीच फिर संपर्क स्थापित होना इस प्रक्रिया का एक उदाहरण था। चौधरी अजीत सिंह जी के जीवन के अंतिम दौर में भी हिंदू-मुस्लिम सहयोग को मजबूत करने की चिंता सामने आई। इन घटनाओं का महत्व शुरुआत के रूप में है। उनसे यह संभावना दिखाई देती है कि टूटा संवाद फिर खुल सकता है। लेकिन किसी सभा में साथ आना हर परिवार के अनुभव को नहीं बदल देता। विश्वास की बहाली को स्थानीय जीवन में समय, निरंतरता और सुरक्षित व्यवहार चाहिए। साझा मंच तब उपयोगी बनता है जब बातचीत उसके बाद भी चलती रहे। लोगों को बिना डर अपनी असुविधा बताने का अवसर मिले और दूसरे पक्ष को उसे सुनने का धैर्य हो। इसका कोई एक सार्वजनिक दृश्य नहीं होता। कई बार सबसे जरूरी परिवर्तन साधारण लेन-देन, स्कूल आने-जाने या स्थानीय विवाद की निष्पक्ष सुनवाई में दिखाई देता है। वहीं पता चलता है कि संपर्क केवल नेताओं के बीच लौटा है या सामान्य जीवन में भी कुछ भरोसा बना है। जयंत चौधरी जी के सामने इस इतिहास के साथ काम करने की जिम्मेदारी है। उनकी किसान राजनीति की पृष्ठभूमि साझा आर्थिक प्रश्नों पर संवाद का अवसर देती है। फिर भी सामाजिक भरोसे का काम चुनावी समीकरण से अधिक व्यापक है। उसमें राजनीतिक लाभ से बाहर खड़े लोगों की सुरक्षा और सम्मान भी शामिल हैं। अफवाह किसी तनाव को बढ़ा सकती है। इसलिए किसी घटना की अधूरी जानकारी को तुरंत समुदायों के बीच आरोप में बदल देना खतरनाक होता है। जिम्मेदार सार्वजनिक भाषा तथ्य स्पष्ट होने की गुंजाइश रखती है। नेतृत्व की परीक्षा उस समय होती है जब संयम बनाए रखना अपने समर्थकों की तत्काल भावनाओं के विरुद्ध भी पड़ सकता है। स्थानीय प्रशासन का निष्पक्ष व्यवहार सामाजिक शांति की महत्वपूर्ण शर्त है। शिकायत दर्ज होने, जांच और कार्रवाई पर लोगों का भरोसा कमजोर हो तो तनाव गहरा सकता है। भाईचारे का पूरा भार नागरिकों की व्यक्तिगत सद्भावना पर नहीं छोड़ा जा सकता; सार्वजनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी भी है। शांति का अर्थ शिकायत का समाप्त हो जाना नहीं है। असहमति और विवाद किसी भी समाज में होंगे।

बेहतर संबंध की पहचान यह है कि विवाद को पूरी धार्मिक आबादी के खिलाफ आरोप बनाए बिना सुलझाने के रास्ते खुले हों। निष्पक्ष जांच और शांतिपूर्ण बातचीत एक-दूसरे के विरोध में नहीं हैं। कानून का भरोसा कमजोर हो तो समझौता दबाव जैसा लग सकता है; सुनवाई उपलब्ध हो तो व्यक्ति को अपने अधिकार छोड़कर शांति खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान साझेदारी का भविष्य इसी व्यापक समझ से जुड़ा है। खेत और बाजार लोगों को जोड़ सकते हैं, लेकिन संबंधों में बराबरी और सुरक्षा भी चाहिए। जहाँ कोई व्यक्ति अपनी पहचान के कारण भय महसूस किए बिना काम कर सके और अपनी शिकायत रख सके, वहीं भाईचारा रोजमर्रा की वास्तविकता बनता है।

## अध्याय 32 — उत्तराखंड के मुस्लिम समाज और राष्ट्रीय लोक दल के लिए संभावित राजनीतिक-सामाजिक क्षेत्र

उत्तराखंड के मुस्लिम समाज पर विचार करते समय पूरे प्रदेश को एक जैसी परिस्थितियों वाला क्षेत्र नहीं माना जा सकता। मैदानी इलाके, पहाड़ी कस्बे और अलग-अलग रोजगार से जुड़े परिवार अपने अनुभव रखते हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण प्रश्न किसी पहाड़ी कस्बे के छोटे व्यवसायी के प्रश्नों से अलग हो सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ पड़ोसी क्षेत्रों के पारिवारिक और आर्थिक संपर्क हैं। इनसे आना-जाना, कारोबार और सामाजिक परिचय बनता है। लेकिन परिचय को राजनीतिक समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय लोक दल के संदर्भ में संभावनाओं की चर्चा करते समय स्थानीय काम और स्थापित प्रभाव के बीच अंतर रखना आवश्यक है। मैदानी क्षेत्र के मुस्लिम किसान के लिए लागत, सिंचाई और बिक्री के प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कस्बे का दुकानदार ग्राहक और कारोबार की निरंतरता देखता है। काम तलाशता युवा प्रशिक्षण और रोजगार की स्थिति समझना चाहता है। किसी एक परिचित चेहरे के माध्यम से इन सभी की राय जान लेने का दावा पर्याप्त नहीं होगा। शिक्षा तक पहुँच में दूरी और खर्च की भूमिका भी देखनी पड़ती है। किसी संस्थान का प्रदेश में मौजूद होना अपने आप हर परिवार के लिए उसे सुलभ नहीं बनाता। आवागमन, रहने का खर्च और परिवार की जिम्मेदारियाँ अवसर के उपयोग को प्रभावित कर सकती हैं। युवतियों के लिए सुरक्षित पहुँच का प्रश्न अतिरिक्त महत्व रख सकता है। किसी इलाके की शैक्षणिक स्थिति को केवल वहाँ कॉलेज होने से नहीं समझा जा सकता। छात्र किस विषय में पढ़ सकता है, नियमित कक्षाएं मिलती हैं या नहीं और पढ़ाई जारी रखने के लिए बाहर रहना पड़ेगा या नहीं—इन बातों से परिवार का फैसला बनता है। सीमित आमदनी वाले घर में संस्थान की फीस से अधिक बोझ कभी रहने और आने-जाने का होता है। इसलिए क्षेत्रीय विकास की चर्चा में दूरी को केवल किलोमीटर में मापना पर्याप्त नहीं है; परिवार की क्षमता के संबंध में भी देखना पड़ता है। शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में जयंत चौधरी जी की जिम्मेदारी इन जरूरतों से जुड़ती है। उपयोगी पाठ्यक्रम के साथ प्रशिक्षण तक पहुँच और आगे काम की संभावना हो, तो पात्र युवाओं को अवसर मिल सकता है। इससे किसी समुदाय का राजनीतिक समर्थन पहले से तय नहीं होता।

पर्यटन और स्थानीय सेवाओं से जुड़े परिवारों की आय में मौसम का असर हो सकता है। ऐसे काम में प्रशिक्षण उपयोगी है, लेकिन वर्ष के बाकी समय की आजीविका का प्रश्न भी बना रहता है। छोटे व्यवसायी के लिए स्थिरता, सुरक्षित कार्यस्थल और ग्राहक तक पहुँच उतनी ही जरूरी है जितना नया कौशल सीखना। मौसमी कारोबार में अच्छे महीनों की बिक्री देखकर साल भर की समृद्धि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। किराया, उपकरण और उधार का खर्च कमजोर महीनों में भी रह सकता है। काम करने वाले व्यक्ति को तब दूसरी आजीविका खोजनी पड़ती है। पर्यटन या स्थानीय सेवाओं के प्रशिक्षण की उपयोगिता का एक पक्ष यह होगा कि उससे व्यक्ति अपने पुराने काम को बेहतर चला पाता है या नए समय में काम बदलने की तैयारी हासिल करता है। केवल मौसम के दौरान नियुक्ति को स्थायी रोजगार कहना वास्तविक स्थिति छिपा देगा। ग्रामीण और कस्बाई समाज में दस्तावेज, बैंकिंग तथा सार्वजनिक सुविधाओं की प्रक्रिया समझने में सहायता भी उपयोगी हो सकती है। यह सहायता नागरिक सुविधा के रूप में उपलब्ध होनी चाहिए। किसी दल या नेता से निकटता उसके लिए अनिवार्य शर्त बने तो कम पहुँच वाला व्यक्ति फिर पीछे रह जाएगा। मुस्लिम समाज के भीतर विभिन्न आर्थिक और सामाजिक वर्गों की अपनी आवाज भी है। स्थानीय प्रभावशाली व्यक्ति की राय महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन वह महिलाओं, युवाओं, मजदूरों और छोटे कारोबारियों का पूरा अनुभव नहीं बताती। किसी भी सार्वजनिक अध्ययन को इस विविधता के साथ आगे बढ़ना होगा। उत्तराखंड में किसी राजनीतिक धारा की प्रासंगिकता का अध्ययन स्थानीय समाज को केवल पड़ोसी प्रदेश का विस्तार मानकर नहीं किया जा सकता। वहाँ प्रशासन का अनुभव, बाजार तक पहुँच और विभिन्न समुदायों के संबंध अपना इतिहास रखते हैं। चौधरी चरण सिंह जी की ग्रामीण आर्थिक सोच से प्रश्न पूछने की दृष्टि मिल सकती है, लेकिन उनके उत्तर स्थानीय परिस्थितियों से निकलेंगे। इसी अंतर को स्वीकार करने पर राष्ट्रीय लोक दल के बारे में संभावना और स्थापित उपस्थिति की चर्चा अधिक साफ रहती है। राष्ट्रीय लोक दल की किसान और छोटे उत्पादक संबंधी परंपरा इन मुद्दों से वैचारिक संबंध रखती है। उसकी स्थानीय प्रासंगिकता का फैसला वास्तविक काम करेगा। नियमित सार्वजनिक उपस्थिति, समस्याओं की समझ और लोगों के अनुभव के बिना संगठनात्मक विस्तार का दावा केवल संभावना बना रहेगा।

इसी तरह केंद्रीय मंत्री के रूप में जयंत चौधरी जी की जिम्मेदारी को पार्टी की गतिविधि से अलग देखना चाहिए। सरकारी कार्यक्रम सभी पात्र नागरिकों के लिए होते हैं। उनका उद्देश्य सार्वजनिक जरूरत पूरी करना है। राजनीतिक समर्थन के आधार पर सुविधा की उपलब्धता लोकतांत्रिक प्रशासन का उचित मानदंड नहीं हो सकती।

उत्तराखंड के मुस्लिम समाज और राष्ट्रीय लोक दल के संबंध का भविष्य पहले से तय नहीं है। उसमें पड़ोसी क्षेत्रों का परिचय, ग्रामीण आर्थिक प्रश्न और नई पीढ़ी की जरूरतें चर्चा का आधार बन सकती हैं। लेकिन समर्थन, असहमति और राजनीतिक पसंद स्थानीय लोगों के स्वतंत्र निर्णय हैं। स्थानीय परिवारों की शिक्षा, रोजगार और सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें इस चर्चा का आधार हैं। उनके अनुभव सामने आएँ तो संभावनाओं का अर्थ स्पष्ट होता है। बाहर से देखा गया राजनीतिक परिचय उनकी रोजमर्रा की स्थिति की जगह नहीं ले सकता।

## अध्याय 33 — सत्ता में हिस्सेदारी: टिकट से आगे संगठन और नीति निर्माण तक

सत्ता में हिस्सेदारी की चर्चा अक्सर इस प्रश्न से शुरू होती है कि किसे टिकट मिला और कौन मंत्री बना। ये महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। चुनाव लड़ने का अवसर विधानमंडल तक पहुँच का रास्ता देता है और मंत्री पद प्रशासनिक जिम्मेदारी देता है। लेकिन सार्वजनिक निर्णयों पर प्रभाव डालने की पूरी प्रक्रिया इन्हीं दो पड़ावों तक सीमित नहीं है। किसी नीति का विषय तय होने से लेकर उसका बजट बनने और उसे लागू करने तक अनेक फैसले होते हैं। किस समस्या को तत्काल माना जाएगा, किन लोगों से बातचीत होगी और काम की समीक्षा कैसे होगी—इन चरणों में भी भागीदारी मायने रखती है। कोई समुदाय चुनाव में दिखाई दे, लेकिन इन प्रक्रियाओं में उसकी बात न पहुँचे, तो प्रतिनिधित्व सीमित रह सकता है। मुस्लिम समाज के संदर्भ में यही प्रश्न अलग-अलग स्तरों पर सामने आता है। किसी मुस्लिम जनप्रतिनिधि का चुना जाना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके काम का दायरा पूरे निर्वाचन क्षेत्र तक होता है। उसकी धार्मिक पहचान से ही यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि समुदाय के सभी वर्गों की समस्याएं नीति तक पहुँच गईं। इसी तरह किसी दूसरे धर्म का प्रतिनिधि भी मुस्लिम नागरिकों के प्रश्न जिम्मेदारी से उठा सकता है। प्रतिनिधित्व में पहचान का अपना महत्व है, लेकिन सुनवाई, जवाबदेही और काम भी उतने ही जरूरी हैं। व्यक्ति किसके लिए बोलता है और निर्णय में किस अनुभव को स्थान देता है, यह उसके सार्वजनिक व्यवहार से पता चलता है। राष्ट्रीय लोक दल के इतिहास में विभिन्न समुदायों के नेताओं की भागीदारी रही है। जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में उसकी गहराई का मूल्यांकन संगठन के कामकाज से होगा। स्थानीय स्तर की राय ऊपर कैसे पहुँचती है, किसे जिम्मेदारी मिलती है और नीतिगत चर्चा में किन लोगों को सुना जाता है—इन बातों से वास्तविक स्थिति सामने आती है। केवल पदों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं हो सकता। किसी पदाधिकारी के पास काम का स्पष्ट दायरा हो, आवश्यक जानकारी मिले और वह अपने सुझाव रख सके, तभी पद अर्थपूर्ण बनता है। प्रभावशाली नेता के आसपास बने रहने और संस्थागत जिम्मेदारी निभाने में अंतर है। पद की उपयोगिता उसके कामकाज में खुलती है। कोई सदस्य शिकायतें एकत्र करता है, लेकिन उसे जवाब देने या संबंधित अधिकारी तक बात पहुँचाने की व्यवस्था न हो, तो लोगों की निराशा बढ़ सकती है।

जिम्मेदारी स्पष्ट होने पर नागरिक जानता है कि किससे क्या पूछना है और पदाधिकारी जानता है कि उसे किस काम का उत्तर देना है। सत्ता में हिस्सेदारी के भीतर यह साधारण-सी स्पष्टता भी महत्वपूर्ण है। अधिकार और जवाबदेही के बिना मिला पद कई बार केवल परिचय का हिस्सा बनकर रह जाता है। नीति निर्माण में विषय का अनुभव भी महत्वपूर्ण होता है। शिक्षा पर बात करते समय शिक्षक और विद्यार्थी का अनुभव उपयोगी है। छोटे कारोबार के प्रश्न में दुकानदार, कामगार और संबंधित विशेषज्ञ की समझ जरूरी है। समुदाय की ओर से हर विषय पर केवल राजनीतिक प्रतिष्ठा के आधार पर बोलने से कई व्यावहारिक बातें छूट सकती हैं। महिलाओं और युवाओं की भागीदारी इस प्रक्रिया को व्यापक बनाती है। प्रशिक्षण का समय, छात्रावास की सुविधा या कार्यस्थल की सुरक्षा जैसे प्रश्न उन लोगों के अनुभव से बेहतर समझे जा सकते हैं जिन पर उनका सीधा असर पड़ता है। किसी निर्णय के बाद उनकी राय लेने की तुलना में शुरुआत से शामिल करना अलग परिणाम दे सकता है। परामर्श में आमंत्रण मिलना भी अंतिम पड़ाव नहीं है। जो लोग बैठक में आए, उनकी बात लिखी गई या नहीं, निर्णय में उसका क्या हुआ और अस्वीकार किए गए सुझाव का कारण बताया गया या नहीं—इनसे प्रक्रिया की गंभीरता समझ में आती है। किसी अनुभवी कारीगर की भाषा सरकारी दस्तावेज की भाषा से अलग हो सकती है, फिर भी उसके अनुभव में नीति की उपयोगी जानकारी हो सकती है। संस्थाओं का काम दोनों के बीच संवाद संभव बनाना है। भागीदारी के साथ हिसाब मांगने का अधिकार भी होना चाहिए। किसी कार्यक्रम का वादा हुआ तो उसके क्रियान्वयन की स्थिति पूछना विरोध नहीं है। समर्थक भी काम की गति, खर्च और परिणाम पर प्रश्न रख सकता है। लोकतांत्रिक संबंध तभी परिपक्व होता है जब सम्मान और जांच साथ चल सकें। जवाबदेही का अर्थ हर देरी के लिए किसी एक व्यक्ति को दोषी ठहरा देना भी नहीं है। कभी धन की कमी होती है, कभी विभागों का तालमेल टूटता है और कभी निर्णय ही अस्पष्ट रहता है। नागरिक के सामने कारण साफ आए तो वह समझ सकता है कि काम कहाँ अटका है। अस्पष्ट आश्वासन के बजाय ऐसा उत्तर सार्वजनिक भरोसा बढ़ा सकता है। राजनीति में हिस्सेदारी का लाभ यही है कि सामान्य व्यक्ति निर्णय की प्रक्रिया को दूर खड़े होकर देखने के बजाय उसके बारे में प्रश्न रख सके। सरकारी योजनाओं का लाभ किसी राजनीतिक पक्षधरता पर निर्भर नहीं होना चाहिए। नागरिक अपने अधिकार और पात्रता के आधार पर सुविधा पाता है।

पार्टी उसके लिए जानकारी और संवाद का माध्यम बन सकती है, लेकिन योजना को निजी कृपा की तरह प्रस्तुत करना सत्ता और नागरिक के संबंध को कमजोर करता है। जयंत चौधरी जी की मंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष की भूमिकाओं में यह अंतर विशेष महत्व रखता है। मंत्री के रूप में उनकी जवाबदेही व्यापक है। संगठन के नेता के रूप में वे समर्थकों और कार्यकर्ताओं से संवाद करते हैं। सार्वजनिक संसाधनों और दल की गतिविधियों के बीच स्पष्टता बनी रहे तो दोनों भूमिकाओं का मूल्यांकन अधिक ईमानदारी से हो सकता है। सत्ता में हिस्सेदारी का गहरा अर्थ निर्णय के पास पहुँचना है, साथ ही निर्णय के परिणाम के लिए जवाबदेह होना भी। किसी कमजोर परिवार की समस्या नीति की प्राथमिकता बने और काम पूरा होने के बाद उसे अपना अनुभव बताने की जगह मिले, तो भागीदारी अधिक वास्तविक होती है। इस अध्याय के शीर्षक में आया 'सत्ता में हिस्सेदारी' का प्रश्न इसी व्यापक नागरिक अर्थ में समझा जाना चाहिए।

## अध्याय 34 — नया सवेरा: चौधरी चरण सिंह जी की विरासत से जयंत चौधरी जी के दौर तक

इस पुस्तक की शुरुआत चौधरी चरण सिंह जी के जीवन और विचारों से हुई थी। वहाँ किसान का प्रश्न था—उसकी मेहनत, उसकी जमीन और देश की आर्थिक व्यवस्था में उसका स्थान। आगे चौधरी अजीत सिंह जी की यात्रा आई, जिसमें उसी विरासत को बदलती राजनीति के बीच संगठन और प्रतिनिधित्व देने का प्रयास दिखाई दिया। जयंत चौधरी जी के दौर तक पहुँचते-पहुँचते शिक्षा, कौशल और नई पीढ़ी के अवसर भी इस चर्चा में प्रमुख हो गए। तीनों पीढ़ियों के बीच संबंध है, लेकिन उनकी परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं थीं। चौधरी चरण सिंह जी के सामने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और विकास की प्राथमिकताओं को लेकर बुनियादी प्रश्न थे। चौधरी अजीत सिंह जी को संगठनात्मक विभाजन, गठबंधन और बदलते सामाजिक आधार के बीच काम करना पड़ा। जयंत चौधरी जी के सामने इन अनुभवों के साथ नई पीढ़ी की अपेक्षाएँ हैं। विरासत का महत्व तभी बना रहता है जब उसके भीतर वर्तमान को समझने की क्षमता हो। किसान के अधिकार की बात आज भी जरूरी है, लेकिन किसान परिवार का जीवन खेत के बाहर भी फैला हुआ है। उसके बच्चे पढ़ते हैं, नौकरी तलाशते हैं और छोटे कारोबार में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। परिवार की आर्थिक सुरक्षा अब अनेक अवसरों और जोखिमों से जुड़ी है। मुस्लिम समाज के साथ इस राजनीतिक धारा का संबंध भी कई स्तरों पर बना। किसान की साझा समस्याएँ थीं, संगठित मुस्लिम नेतृत्व की भागीदारी थी और क्षेत्रीय जीवन के पुराने संपर्क थे। इसके साथ मतभेद, असुरक्षा और विश्वास टूटने के अनुभव भी मौजूद रहे। इन सबको साथ रखे बिना संबंध का पूरा इतिहास नहीं समझा जा सकता। इस रिश्ते को किसी स्थायी राजनीतिक समझौते की तरह पढ़ना उसके मानवीय हिस्से को कम कर देगा। जिन परिवारों ने साथ दिया, उनके अनुभव समय के साथ बदले। किसी को अपने प्रश्न की आवाज मिली, किसी को अपेक्षित जगह नहीं मिली और किसी ने पुराने संबंध के बावजूद अलग राजनीतिक रास्ता चुना। इन अलग अनुभवों को एक इतिहास में रहने देना ही उसके प्रति ईमानदारी है। सम्मान का अर्थ यह नहीं कि सभी लोगों की स्मृति एक जैसी हो। मुस्लिम समाज के भीतर किसान, मजदूर, कारीगर, विद्यार्थी, महिला और छोटे कारोबारी के अपने अनुभव हैं।

इनकी जरूरतें कभी मिलती हैं और कभी अलग होती हैं। राजनीतिक संबंध की गंभीरता इसी विविधता को समझने में है। किसी एक परिवार को मिला अवसर पूरे समाज की दशा नहीं बताता और किसी एक शिकायत से सभी अनुभव समाप्त नहीं हो जाते।

जयंत चौधरी जी की शिक्षा, कौशल और उद्यमशीलता संबंधी जिम्मेदारियां इन जरूरतों के अध्ययन का अवसर देती हैं। इनसे लाभ की संभावना है, लेकिन उसका प्रमाण वास्तविक काम और परिणाम होंगे। प्रशिक्षण पूरा हुआ या नहीं, काम मिला या नहीं और परिवार की स्थिति में क्या बदलाव आया—इन सवालों के बिना केवल घोषणा से उपलब्धि तय नहीं की जा सकती। इसी तरह राजनीतिक प्रतिनिधित्व का महत्व मंच और पद से आगे जाता है। साधारण नागरिक अपनी बात रख सके, उसके अनुभव को निर्णय में जगह मिले और वह सार्वजनिक काम का हिसाब मांग सके—यह लोकतांत्रिक भागीदारी का आधार है। मुस्लिम समाज सहित सभी समुदायों के लिए सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ इसी व्यापक रूप में उपयोगी है। सामाजिक भाईचारे का प्रश्न भी पुस्तक के साथ चलता रहा है। साझा आर्थिक हित लोगों को साथ ला सकते हैं, लेकिन सुरक्षा और सम्मान का अपना स्थान है। जहाँ किसी व्यक्ति को अपनी पहचान के कारण भय हो, वहाँ विकास की चर्चा अधूरी रहेगी। भरोसा लौटाने के लिए संवाद के साथ निष्पक्ष संस्थाएं और न्यायपूर्ण व्यवहार भी चाहिए। चौधरी चरण सिंह जी के विचारों के प्रति सम्मान का अर्थ उनके नाम का बार-बार उल्लेख भर नहीं है। किसान और छोटे उत्पादक की कठिनाई को निर्णय की प्राथमिकता बनाना उस सम्मान का व्यावहारिक रूप हो सकता है। चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत का अर्थ संगठन बनाए रखने के उनके प्रयास और उनके सामने आई सीमाओं, दोनों से सीखना है। तीनों पीढ़ियों की यात्रा में गाँव की अपनी बदलती तस्वीर भी मौजूद है। खेत अब भी परिवार का आधार हो सकता है, लेकिन उसी घर की बातचीत में नौकरी की परीक्षा, प्रशिक्षण का खर्च और शहर का किराया शामिल हैं। कारीगर अपने पुराने ग्राहक के साथ दूर के बाजार को देखता है। छात्र अपना रास्ता चुनते समय परिवार की बचत का हिसाब लगाता है। किसान राजनीति इन जीवनों से जुड़ी रहे तो उसे विरासत और वर्तमान के बीच कृत्रिम दूरी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। जयंत चौधरी जी के सामने इन्हीं विरासतों को अपने काम से अर्थ देने की जिम्मेदारी आई।

शिक्षा और कौशल के क्षेत्र में मिले प्रशासनिक अवसर ने उनके काम का दायरा बढ़ाया। किसान परिवार की नई आकांक्षाओं और पुराने ग्रामीण प्रश्नों को साथ लेकर चलना इस भूमिका का महत्वपूर्ण पक्ष है।

‘नया सवेरा’ अपने आप आने वाला राजनीतिक परिणाम नहीं है। वह उन छोटे, ठोस परिवर्तनों में दिखाई दे सकता है जिनसे परिवार का जीवन कुछ अधिक सुरक्षित हो। किसान को समय पर कमाई मिले, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सके, हुनर सीखने वाले को सम्मानजनक काम मिले और नागरिक की शिकायत बिना भेदभाव सुनी जाए—तभी इस अभिव्यक्ति को जीवन में अर्थ मिलता है। ऐसे बदलाव का श्रेय भी किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, कार्यकर्ता और नागरिक, सभी की भूमिका होती है। नेतृत्व का महत्व इन प्रयासों को दिशा देने और उनके लिए जवाबदेह रहने में है। जनता केवल उम्मीद रखने वाली भीड़ नहीं है; वह लोकतंत्र की भागीदार और उसके काम की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षक है। इसीलिए उम्मीद का अर्थ सार्वजनिक जीवन में प्रश्न पूछना बंद कर देना नहीं है। नागरिक नेतृत्व का सम्मान कर सकता है और काम का ब्यौरा भी मांग सकता है। वह पुराने योगदान को याद रखते हुए नई जरूरत सामने रख सकता है। चौधरी चरण सिंह जी की किसान संबंधी चिंता से शुरू हुई चर्चा का सबसे उपयोगी विस्तार यही होगा कि मेहनत करने वाले व्यक्ति की आवाज बनी रहे। उसके अनुभव से असुविधाजनक प्रश्न उठें, तब भी उन्हें सुनने की जगह हो।

इस यात्रा के अंत में फिर वही आदमी सामने आता है जिससे इसकी शुरुआत हुई थी—अपनी मेहनत से घर चलाने वाला नागरिक। कभी वह खेत में है, कभी कार्यशाला में और कभी पढ़ाई के बाद काम खोज रहा है। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी की राजनीति का अर्थ उसके जीवन से जुड़कर खुलता है। उसकी मेहनत का मूल्य, उसकी बात की सुनवाई और अपने भविष्य का फैसला करने की स्वतंत्रता बनी रहे—नए सवेरे की उम्मीद इसी में है।





# धरतीपुत्र की विरासत:

## पश्चिमी यूपी और किसान की राजनीति



चौधरी चरण सिंह जी की ग्रामीण आर्थिक सोच से शुरु होकर यह पुस्तक चौधरी अजीत सिंह जी के सार्वजनिक जीवन और जयंत चौधरी जी के दौर तक आती है। चार भागों और चौतीस अध्यायों में जमीन, किसान, छोटे उत्पादक, संगठन, शिक्षा, कौशल और रोजगार के प्रश्न साथ चलते हैं।



मुस्लिम समाज यहाँ अपने अलग-अलग अनुभवों के साथ उपस्थित है—किसान, मज़दूर, कारीगर, विद्यार्थी, महिला और छोटे कारोबारी के रूप में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाट—मुस्लिम किसान साझेदारी, सामाजिक भरोसा, पसमांदा समाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी इस चर्चा के महत्वपूर्ण हिस्से हैं।



सत्ता में हिस्सेदारी का अर्थ टिकट और पद से आगे कहाँ तक जाता है? विरासत के प्रति सम्मान और नेतृत्व से जवाब माँगने का अधिकार साथ कैसे रह सकते हैं? यह पुस्तक इन्हीं के बीच राष्ट्रीय लोक दल और मुस्लिम समाज के संबंध को समझने का प्रयास करती है।

लेखक : डॉ. सैयद नासिर शाह

